चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

08 जून –14 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मोदी सरकार का एक साल

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

कम कम बातें ज़्यादा

पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरा होने को लेकर उत्सुक है. एक तरफ़ एनडीए ने पिछले एक साल की उपलब्धियां लोगों को बताने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर रैलियां करने की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार की वादाख़िलाफ़ी पर हमला बोल दिया है. बहरहाल, हम इस एक साल का आराम से, बिना किसी लाग-लपेट के विश्लेषण करते हैं.

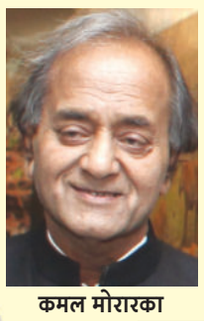

कमल मोरारका

चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी द्वारा जगाई गई उम्मीदें बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए अवास्तविक किस्म की थीं. ये ऐसे राजनीतिक प्रेक्षक हैं, जो पक्षपात रहित हैं. इसलिए मेरे जैसे आदमी निराश नहीं हैं, क्योंकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सरकार एक साल में कोई चमत्कार कर सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग्यशाली रहे कि पिछले साल मानसून काफी ठीक था और खाद्यान्न उत्पादन नीचे नहीं गया. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर तेल की क़ीमतों में कमी आई. इससे विकास और योजनाओं के लिए और अधिक धन आवंटित करने का मौक़ा वित्त मंत्री को मिला. विडंबना यह है कि आलोचना भी हुई, तो कॉरपोरेट सेक्टर से, जो पिछले साल और इस साल के बजट से भारी राहत व गिफ्ट की उम्मीद कर रहा था, जो नहीं मिला. मैं इसे ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर कभी खुश नहीं होगा. आइए, सरकार की खुद की योजनाओं पर सरकार का परीक्षण करते हैं. स्वच्छ भारत और गंगा सफ़ाई आदि योजनाओं के तत्काल परिणाम नहीं निकलते. आप एक साल में स्वच्छ भारत नहीं बना सकते हैं. वैसे ही आप तुरंत गंगा को साफ़ नहीं कर सकते हैं.

लेकिन, इन दो बिंदुओं के बारे में यह समझना चाहिए कि भारत को स्वच्छ बनाना केंद्र सरकार का काम नहीं है, प्रधानमंत्री का काम नहीं है. यह ग़ैर सरकारी संगठनों, पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों का काम है. वास्तव में देश स्वच्छ बनाया कैसे जाएगा, इसके लिए कोई नीति सामने नहीं लाई गई है, यह निराशाजनक है. दूसरे, गंगा की सफ़ाई पर बात करें, तो तथ्य यह है कि हर साल जब बर्फ पिघलती है, तो इतना पानी आता है, जिससे गंगा खुद ही साफ़ हो जाती है. स्वच्छ गंगा के लिए जो हमें करना है, वह है नहीं करना. नहीं करना यानी हमें कारखानों से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट, चमड़े के उद्योग से निकलने वाले कचरे को गंगा में नहीं डालना है, जो हर रोज गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं. यदि इस प्रदूषण से हम निपट लें, तो गंगा स्वच्छ रहेगी. गंगा को साफ़ करने के लिए किसी भी योजना में पैसा लगाने की बजाय हमें वह पैसा इन अपशिष्ट पदार्थों के ट्रीटमेंट पर खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि आगे से ये पदार्थ गंगा में जाएं ही नहीं. मुझे इस योजना की विस्तृत जानकारी नहीं है. राजीव गांधी जब सत्ता में आए, तब उन्होंने 1985 में एक गंगा प्राधिकरण बनाया था. 29 सालों के बाद हम वही दोहरा रहे हैं. असल में, इस सब में बहुत कम परिणामों के साथ बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा.

दूसरी एक बड़ी बात है, मेक इन इंडिया, जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. आइए, इसकी वास्तविकताओं को समझते हैं. 1990 में भारतीय रेलवे नेटवर्क का आकार चीन से भी बड़ा था. आज 25 सालों के बाद चीन का रेल नेटवर्क भारत से चार गुना बड़ा है. यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है. अगर हम चाहते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया हो, यह सफल बने, तो

इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से पैसे आएं. हमें एक्सचेंज पॉलिसी की ज़रूरत होगी, ताकि निर्यात में सुधार हो सके. एक मौद्रिक नीति की ज़रूरत है, ब्याज दरों में कटौती की ज़रूरत है, यह सब एकीकृत है. एक पर्यवेक्षक के रूप में मैं ऐसा कोई संकेत नहीं देख रहा हूं. आज क्या हो रहा है? ऊंची ब्याज दर, उच्च रुपया मूल्य, ये दोनों अमेरिकी निवेशकों को मदद करने के लिए हैं. वे भारत के लिए पैसा भेजकर शेयर बाज़ार या अन्य आर्बिट्राज के ज़रिये कमा कर पैसा वापस ले जा सकते हैं. कोई भी भारत में मेक इन इंडिया में निवेश नहीं करेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर ऊंची है. डॉलर की अन्य मुद्राओं या रुपये से तुलना करके अंतर को देखें. डॉलर रुपये के मुक़ाबले मजबूत होता जा रहा है. रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि हमने एक

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मानव संसाधन विकास या विवाद मंत्रालय | P-3

कृषि क्षेत्र : अन्नदाता को अच्छे दिनों का इंतजार है... | P-4

कैसे होगा स्वस्थ भारत का निर्माण | P-5

मोदी सरकार का एक साल : काम कम बातें ज्यादा

पृष्ठ 1 का शेष

कृत्रिम दर को बनाए रखा है. ज़रूरत है कि रुपये को थोड़ा नीचे आने दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह नारा दिया गया था कि कांग्रेस ने रुपये को कमज़ोर कर दिया और हम इसे 40 रुपये प्रति डॉलर तक ला देंगे. आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हम एक रुपये को एक डॉलर के बराबर कर देंगे. वे असल में यह नहीं समझते कि वे क्या बोल रहे हैं. मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा, क्योंकि वे अर्थशास्त्री नहीं हैं. मैं आर्थिक समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य समाचार-पत्र को दोष नहीं देता, लेकिन मैंने यह भी नहीं देखा कि किसी भी लेखक ने यह लिखा हो कि अगर निवेश चाहिए, विनिर्माण क्षमता चाहिए, तो रुपये को थोड़ा नीचे आने दें और एक्सचेंज रेट में कटौती करें. आज जो एक्सचेंज रेट है, उसमें आप कैसे निर्यात करेंगे?

इसलिए मैं नहीं समझता कि मेक इन इंडिया का नारा हमें कहीं ले जाएगा. एक साल बीत चुका है, सिर्फ़ चार साल बाकी हैं. मैं नहीं समझता कि सरकार को यह पता है कि क्या करने की ज़रूरत है. दुर्भाग्य से रिजर्व बैंक के गवर्नर, आर्थिक सलाहकार और वित्त राज्यमंत्री सभी अमेरिकी, ब्रेटन वुड्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक से जुड़े रहे हैं. यह मदद नहीं करेगा. जब चीन ने बड़ा बुनियादी ढांचा बनाने की सोची, तो उसने यह नहीं सोचा कि अमेरिका क्या सोचता है. चीन ने स्वयं के परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने तरीके से अपनी नीतियां बनाईं. एक बार आप मजबूत हो जाते हैं, तो आप सब कुछ समायोजित कर सकते हैं. जब हम अभूतपूर्व रूप से विदेशी मुद्रा रिजर्व की बात करते हैं, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के पास भारत के मुक़ाबले चार गुना अधिक विदेशी मुद्रा रिजर्व है. चीन के साथ अपने आपकी तुलना करना तो ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि उसके साथ हमारा 70 बिलियन का व्यापार है, तो उसमें 55 बिलियन का सामान वह हमें बेच रहा है और हमें 40 बिलियन का घाटा हो रहा है. मैं वित्त मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ कुछ बेहतर सोच वाले लोगों को रखने की ज़रूरत है.

प्रेस बहुत ही कैजुअल रवैया अपना रहा है. प्रधानमंत्री के बारे में दो आलोचनाएं पढ़ने को मिलीं. इन दोनों आलोचनाओं को ग़लत ढंग से प्रस्तुत किया गया. एक तो यह कि वह अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं. इसका कोई अर्थ नहीं है. प्रधानमंत्री को विदेश जाना ही पड़ता है. या तो दूसरे राष्ट्र के प्रमुख यहां आते हैं या फिर हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं. एक मज़ाक चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं. यह एक घटिया मज़ाक है और पूरी तरह से अनुचित है. दूसरा यह कि उनके नाम वाले सूट को लेकर आलोचना होती है. यह सब ऐसे बोलने-सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये बातें उनके या उनके कामकाज की आलोचना का केंद्रीय विषय नहीं बन सकतीं. इस सरकार की चूक कुछ और है, ग़लतियां कुछ और हैं, लेकिन प्रेस गंभीर नहीं है. गंभीर लेखन और गंभीर स्तंभकार नहीं हैं. बेसिर-पैर की बातें कही और लिखी जा रही हैं. एक साल पूरा होने पर वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, सही कहा कि एक साल में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के अधिकार को पुन:प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष के दिशा-निर्देशों पर काम कर रहे थे. प्रेस को वह बात कहनी चाहिए थी, जो वित्त मंत्री ने कही, लेकिन कहा यह गया कि नरेंद्र मोदी ने पीएमओ को मजबूत बना दिया है. ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब पीएमओ नहीं है, पीएमओ को कोई अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय एक सचिवालय है.

वह जो कहने की कोशिश कर रहे थे, उसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की सत्ता स्थापित हुई. पत्रकारों के पढ़ने-लिखने के तरीके ऐसे हैं, जिससे वे सरकार को मदद करने, मार्गदर्शन देने में सक्षम नहीं हैं. मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि हमारे पास एक सरकार है, जो अगले चार सालों तक शासन चलाने वाली है. अगर देश को लाभ प्राप्त करना है, तो हमारे पास स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों की आकांक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह आकांक्षा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रोज़गार के अवसर चाहते हैं. भगवान का शुक्र है कि इस सरकार ने यह समझा कि मनरेगा मददगार साबित हो सकती है. लीकेज वहां भी है, हर जगह है, लेकिन यह कह देना समझदारी नहीं है कि यह एक ग़लत योजना है और इसलिए इसकी आलोचना हो. इसने ग़रीबों एवं ग्रामीणों को मदद दी और आज आप इन क्षेत्रों में जो भी थोड़ी-बहुत समृद्धि देख रहे हैं, वह ऐसी योजनाओं का परिणाम है. ठीक है कि पंचायत स्तर, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार फैला, लेकिन ग़रीब लोगों को वास्तव में मदद मिली.

सरकार के पास हाल ही में स्थापित ब्रिक्स बैंक का पहला चेयरमैन नियुक्त करने का एक अवसर था. बहुत से नाम आए, लेकिन अंतिम नियुक्ति कुल मिलाकर निराशा भरी रही. सरकार ने इसके लिए केवी कामथ का नाम चुना. उन्हें इस पद के लिए औसत दर्जे का माना जा सकता है. उन्हें वहां किसी को पैसा उधार देने के लिए नहीं जाना था. ब्रिक्स बैंक को विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुक़ाबले दुनिया के वित्तीय ढांचे को बदलने का काम करना है. ऐसी उससे उम्मीद की जा रही है. यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के नाम भी आए थे और मेरे जैसा आदमी इससे खुश था. यशवंत सिन्हा पहले भी दुनिया के वित्तीय ढांचे को बदलने की बात कहते रहे हैं और वह शंघाई में अपनी छाप छोड़ सकते थे. मैं इन नामों से बहुत खुश था. यह कहा जाता है कि मोदी अपने कुछ नौकरशाहों द्वारा कुछ ज़्यादा ही निर्देशित होते हैं. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों के पास कोई पॉवर नहीं है, इसलिए हमें ही नोट्स और स्कीम्स बनाकर पीएमओ को भेजने हैं, जो वहां से फिर कभी वापस नहीं आते. या तो पीएम बहुत व्यस्त हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी इस बात से सहमत नहीं हैं. कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, नाम न छापने की शर्त पर, बताते हैं कि मनमोहन सिंह के शासन के मुक़ाबले अभी अधिक पॉलिसी पैरालिसिस की हालत है. यह सब मैं नहीं जानता, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि कैबिनेट और सांसदों की क्षमता कम है. इसलिए जब तक आप बाहर से विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और सलाह नहीं लेते हैं, तब तक आप कोई कठोर नीतिगत सुधार या कार्यान्वयन सफलता हासिल नहीं कर सकते.

अब तक उपेक्षित रहा एक और सेक्टर है, कृषि और सिंचाई. अगर अभी हम कुछ नहीं करते हैं, तो पांच-दस सालों के बाद हम फिर से मुसीबत में होंगे. आज हमारे पास पर्याप्त खाद्य उत्पादन है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के साथ यह आगे के लिए काफी नहीं होगा. इस सबके लिए विशेष टीम बनाने की ज़रूरत है. मैं देख सकता हूं कि आज की कैबिनेट में ज़्यादा प्रतिभा नहीं है. वे बस अपना काम कर रहे हैं. यदि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा लेते हैं और उनके मंत्री भ्रष्ट नहीं होते हैं, तो यह एक बड़ी बात है. लेकिन, उन लोगों के पास कोई शानदार आइडिया (विचार) नहीं है. नकारात्मक पक्ष को देखें, तो मैं देखता हूं कि सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, जो अपने राज्य यानी गोवा में बहुत लोकप्रिय है, रंगीन शर्ट पहनता है, रविवार की सुबह खुद के लिए सब्जी खरीदने बाज़ार जाता है. बिना सुरक्षा, ताम-झाम के लोग यह सब देखकर उत्साहित होते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कितना सिम्पल है. यह सब गोवा जैसे राज्य के लिए ठीक है. गोवा एक टूरिस्ट स्टेट है. देश के रक्षा मंत्री का काम बिल्कुल अलग होता है. पहले वह एक बयान देते हैं. मैं इसका पूर्ण विवरण नहीं दे सकता, क्योंकि इससे हमारा विदेशी हित प्रभावित होगा. क्या किसी भी देश का कोई रक्षा मंत्री यह खुलेआम बोलेगा कि विदेश में हमें कोई जासूस मिल गया है? जाहिर है, रक्षा मंत्री इस तरह से नहीं बोलता है. हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि हम कश्मीर में आतंकियों के ज़रिये आतंकियों से निपटेंगे. रक्षा मंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए. कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है.

प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों के विभाग बदल देने चाहिए. मैं समझता हूं कि पहला साल पूरा होने पर कैबिनेट में फेरबदल पहला आवश्यक क़दम है. सक्षम लोगों को जगह दें और उन्हें एक-एक लक्ष्य दे दें. यदि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें यह लक्ष्य देना चाहिए कि कितने कारखाने स्थापित होने हैं, क्या उत्पाद बनाने हैं, कितना निर्यात करना है और इस सबके लिए जो भी नीति बदलनी है, बदल दीजिए. हर वक्त, हर काम के लिए अमेरिका को सुनने की ज़रूरत नहीं है. अमेरिका आपकी कम ही मदद कर सकता है. चीन का अनुपालन करना ज़्यादा अच्छा है. चूंकि हमारे प्रधानमंत्री चीन से प्रभवित हैं, चीन को फॉलो करिए. चीन निजी क्षेत्र को खनन की अनुमति नहीं देता, बैंक को निजी हाथों में नहीं देता. चीन एक लक्ष्य देता है और उसे किसी तरह पूरा करता है. ठीक है कि चीन के उलट हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के भीतर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर आपके पास लक्ष्य है, तो आप उसे क्रियान्वित करेंगे. अगर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप कांग्रेस के मनरेगा मॉडल, कृषि विकास, समावेशी विकास को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं. आप यह सब पसंद नहीं करते हैं. ऐसे में आपकी नई पॉलिसी कागज पर ही रह जाएगी, क्योंकि बाकी की मशीनरी इसके लिए तैयार नहीं है. इसलिए प्रधानमंत्री को तत्काल अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए.

अब नीति आयोग को लें. मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके कार्यों के बारे में जानकारी होगी. हम लोग योजना आयोग के कार्यों को जानते थे, लेकिन अब नीति आयोग है. आप अमेरिका से एक अर्थशास्त्री ले आए. योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट रैंक मिलता था, इस आदमी को कैबिनेट रैंक भी नहीं दिया गया है. मैं समझता हूं कि नौकरशाह उसे यह रैंक नहीं देना चाहते थे. आप किसी का अपमान नहीं कर सकते. मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी यहां क्यों काम कर रहा है? उसे अमेरिका वापस चले जाना चाहिए. उसे यहां वह सब कुछ नहीं मिल रहा है, जिसका वह हक़दार है. नीति आयोग आख़िर करेगा क्या? क्या वह योजना बनाएगा? क्या वह पांच वर्षीय योजना बनाएगा या हर एक साल के लिए बजट बनाएगा और आवंटन का काम करेगा? यह सब स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो नीति आयोग जैसी संस्था बिना किसी उद्देश्य के एक और थिंक टैंक बनकर रह जाएगी.

इसलिए मुझे लगता है कि एक साल के दौरान इस सरकार में कुछ भी नकारात्मक नहीं घटा. यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे जैसे व्यक्ति के मन में जो डर था कि सांप्रदायिक दंगे होंगे और बहुसंख्यक खुद को दूसरे पर थोपेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय स्थानीय स्तर पर कुछ चर्चों पर हमले के. एक हद तक यह राहत की बात है, लेकिन सकारात्मक पक्ष पर बहुत कुछ किया जाना चाहिए. मैंने कहीं पढ़ा है कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, वे खुश हैं. जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है, वे कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए. लेकिन यह भी सच है कि जिन लोगों ने बहुत उम्मीद में मोदी को वोट दिया था, वे आज निराश हैं. मेरे जैसे लोग, जिन्हें कभी बहुत अधिक उम्मीद नहीं रही, बेहतर स्थिति में हैं. आज अगर यूपीए-3 सरकार होती, तो उसका पहला साल भी वैसा ही होता, जैसा आज एनडीए सरकार का है. न नकारात्मक और न अधिक सकारात्मक. यदि मोदी सरकार सचमुच यह दिखाना चाहती है कि वह अलग है, तो उसे अभी बहुत-बहुत काम करना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 14
दिल्ली, 08 जून –14 जून 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

लॉटरी घोटाले में आईपीएस का नाम!

एक लॉटरी घोटाले में कथित भूमिका होने के संदेह में कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार का निलंबन राज्य के बाबुओं में चर्चा का विषय बना हुआ है. राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को ऐसे मामले में निलंबित किया गया. उनके निलंबन का निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा लिया गया. इसके बारे में मुख्य सचिव कौशिक मुखर्जी के माध्यम से राज्य के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश को अवगत करा दिया गया है. पुलिस वाले के ख़िलाफ़ सुबूत मिलने से राज्य सरकार के पास उसके निलंबन के सिवाय कोई रास्ता नहीं था. कुमार द्वारा राज्य सरकार को अदालत में चुनौती देने के इतिहास को देखते हुए इस मामले में सावधानी से क़दम बढ़ाए जा रहे हैं. निलंबित अधिकारी ने पहले ही कह रखा है कि वह अपने निलंबन के ख़िलाफ़ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास जाएगा. राज्य के आईपीएस अधिकारियों की एसोसिएशन ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से कहा है कि वह असली दागियों के ख़िलाफ़ सावधानी पूर्वक कार्रवाई करे, लेकिन सभी अधिकारियों को दागी न समझे. ■

आशा की नई किरण

लोगों का ऐसा मानना था कि भाजपा के केंद्र और बाद में राज्य की सत्ता में आने से आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अधिकाधिक बार तबादलों के शिकार इस अधिकारी को उस समय क़ीमत चुकानी पड़ी थी, जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ज़मीन के सौदे को निरस्त कर दिया था. खेमका ने सोचा था कि हरियाणा में नवनियुक्त खट्टर सरकार सेवा में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखेगी और कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उनके ख़िलाफ़ दायर किए गई चार्जशीट पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब इस बात की संभावना बन रही है कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग विवादस्पद गुड़गांव ज़मीन सौदे में हुई अनियमितताओं की जांच करके खेमका के ख़िलाफ़ पिछली सरकार के आरोप ढाई साल बाद रद्द करेगी. कुछ लोगों का मानना है कि ईमानदार खेमका के ख़िलाफ़ आरोप रद्द करने में हो रही देरी सेवाकाल के दौरान नेताओं से सीधे टक्कर लेने के कारण प्रतिशोध वश हो रही है. लेकिन, वरिष्ठ नौकरशाह खेमका के लिए यह आशा की किरण है कि उनकी परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली हैं. ■

राहत की सांस

अविनाश चंदर को डीआरडीओ प्रमुख के पद से अचानक हटाए जाने के तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद सरकार ने अंतत: इस पद के लिए एस क्रिस्टोफर को उपयुक्त माना है. चंदर के बाद पूर्व रक्षा सचिव आरके माथुर और फिर उनके बाद जी मोहन इस पद का कार्यभार संभाल रहे हैं. क्रिस्टोफर की नियुक्ति से संबंधित समाचार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए राहत लेकर आया है. चंदर के हटाए जाने के समय रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने कहा था कि जल्द ही सारे खाली पदों को भर लिया जाएगा. रक्षा मंत्रालय के बाबुओं में चिंता इस बात की है कि डीआरडीओ प्रमुख के न होने के कारण कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स और हथियारों के अपग्रेडेशन सिस्टम में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि अंतिम रूप से किसी मसले पर निर्णय डीआरडीओ प्रमुख ही लेते हैं. इसलिए क्रिस्टोफर किसी भी धारणा से निपटने के लिए अपने नए कार्यालय में तैयार हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे लगभग 31 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि माता–पिता ख़राब सरकारी स्कूल प्रणाली से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) फोरम के अम्बरीश राय के अनुसार, हमे 80,000 माध्यमिक स्तर के स्कूलों के सीनियर सेकेंडरी स्तर तक उन्नयन करने की आवश्यकता है, लेकिन बजट में किया गया आवंटन पर्याप्त रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा को भी कवर नहीं करेगा. भारतीय जनता पार्टी के पिछले एक वर्ष के 2 बजटों में शिक्षा क्षेत्र में स्थिर बजटीय आवंटन और किसी भी बड़ी रीएलोकेशन के न होने की वजह से शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों की कमी आई है.

मानव संसाधन विकास या विवाद मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक होता है. मोदी सरकार में इस मंत्रालय की चर्चा और आलोचना सरकार के पहले मंत्रीमंडल की घोषणा के साथ ही शुरू हो गयी थी और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्मृति ज़ुबीन ईरानी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनाने का विवाद जोर पकड़ने लगा था. स्मृति के अब तक के कार्यकाल पर नज़र डालें तो मानव संसाधन के विकास के कार्यों से ज्यादा लम्बी विवादों की सूची है.

मोनिशा भटनागर

मोदी सरकार के बीते एक साल में अगर कोई मंत्री और मंत्रालय अपने काम से ज्यादा विवादों के लिए ख़बरों में रहा, तो वह थीं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और उनका मानव संसाधन विकास मंत्रालय. स्मृति ईरानी पद पर नियुक्त होते ही खुद की येल यूनिवर्सिटी से डिग्री को लेकर विवाद में घिर गयीं. उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के चार साल के कोर्स (एफवाईयूपी) को लेकर हुआ विवाद हो या सरकारी स्कूलों (केंद्रीय विद्यालयों) में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन भाषा को हटाए जाने का फैसला या फिर शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए जारी किया सर्कुलर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्मृति ईरानी लगातार विपक्ष और विशेषज्ञों की आलोचनाओं का पात्र बने रहे. इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रीमंडल में एक साल में किये गए काम के कारण याद किए जाने वाले मंत्रियों में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का नाम शामिल नहीं है. ये और बात है की वह सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली मंत्री रहीं. स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व से लेकर उनके द्वारा लिए गए फैसले पूरे साल विवादों में घिरे रहे. कहीं उनके काम करने के तरीके की तीखी आलोचना हुई तो कहीं उनकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभालने की कार्यक्षमता पर ही सवाल खड़े हुए. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) की भी भूमिका को बदलने की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन यह कब होगा और कैसे होगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मंत्री की उच्च शिक्षा पदाधिकारियों जैसे आई.आई.टी डायरेक्टर्स के बीच एक साल में नियमित रूप से सार्वजनिक कहासुनी से भी मंत्रालय और स्मृति ईरानी दोनों की ही छवि को नुकसान पहुंचा है. शिक्षण संस्थानों, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को लेकर भी भाजपा सरकार के इस एक साल में कई विवाद हुए. आज भी देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के पद खाली हैं, जो नीतिगत निर्णय लेने वालों की बाट जोह रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है.

ऐसा नहीं है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बीते एक वर्ष में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन मंत्रालय का कोई भी काम अपने मंत्री के इर्द–गिर्द घूमते विवादों से बड़ा नहीं था. वर्तमान केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहले साल में की गयी सबसे बड़ी घोषणा या पहल एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की रही. 1986 के बाद वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक मूल रूप से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हमारा देश और दुनिया में पहले की तुलना आज काफी बदलाव आ गए हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आज के समय के अनुरूप बदलाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है की इस बीती अवधि में विकसित हुई शैक्षिक समझ को सरकार अपनी नीति में एकीकृत करे. ये सरकार अगर ईमानदारी और सही नीयत से शिक्षा नीति को मज़बूत और अधिक कारगर बनाने का काम करे तो आने वाले अगले कुछ दशकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वह दशा और दिशा तय करने का काम करेगी. मौजूदा भाजपा सरकार पर विपक्ष द्वारा कई बार शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया गया है, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में सभी आरोपों को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि संविधान के दायरे में ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ज़रिये नई शिक्षा नीति द्वारा हमारी शिक्षा का दार्शनिक आधार तय करने की बड़ी और गंभीर ज़िम्मेदारी इस सरकार पर है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीति तैयार करने के संदर्भ में, 43 विशिष्ट मुद्दों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया लेने की पहल की है और 33 थीम तैयार किए हैं, जिनके बारे में मंत्रालय के अनुसार विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा की जा रही है. सरकार शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक दर्ज़ा तंत्र विकसित कर रही है, जो कि एक सकारात्मक कदम है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कई नई योजनओं की घोषणा की है. जैसे पढ़े भारत, बढ़े भारत, जेंडर एटलस, जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जहां कम लड़कियां पढ़ने जाती हैं. सारांश, जिसके माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जान सकें, पूर्वोत्तर के लिए इशान उदय और इशान विकास, पूरे देश में कला उत्सव की शुरुआत करने की पहल आदि. योजनाओं की घोषणा हर सरकार करती है. देखने वाली बात यह है कि उन योजनाओं में से कितनी किस स्तर तक सफल होतीं हैं, लेकिन इस एक साल में सारी योजन–ाओं को नहीं मापा जा सकता. पहले साल में घोषित की गई योजनाओं की सफलता और महत्ता सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ही पता चलेगी.

पहले साल में शिक्षा के क्षेत्र के विकास और तरक्की की बातें तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों ने बहुत ऊर्जा भरे और ताकतवर शब्दों में की, लेकिन सरकार के एक साल में किये गए कामों में छाया कहीं नज़र नहीं आई. मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है, जो देश के सामाजिक–आर्थिक ताने–बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय और उपचारी भूमिका निभाती है, यह कहती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा पेश किये दो आम बजटों को देखकर लगता है कि सरकार बजट बनाते वक़्त इस बात को भूल गयी. भारत में शिक्षा प्राणाली की जो हालत है, खासकर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की, उसका जिम्मेदार कई विशेषज्ञों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हमारे आम बजट में शिक्षा के प्रति कम एलोकेशन बताते हैं. भारत पहले से ही उन देशों में शामिल है, जो अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ज़रूरत से बहुत कम खर्च करतें हैं. हमारे जैसे विकासशील देश के लिए ये दुखद है. इसी तरह सरकार लगातार कौशल विकास पर जोर दे रही है, लेकिन स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर खर्च 2015–16 के बजट में 12,895.6 करोड़ रुपये कम हो गया है.

ब्रिक्स देशों की तुलना में भारत की साक्षरता दर केवल 74% है, लेकिन यह सरकार बजट के इस तरह के प्रावधानों को देखते हुए शिक्षा को लेकर गम्भीर नहीं नज़र आ रही है. वर्ष 2013–14 के आम बजट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए कुल मिलाकर 71321.51 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे, जो 2014–15 के आम बजट में बढ़ा कर 82771.1 करोड़ किए थे. यह एक अच्छा संकेत था. 2014 के आम चुनाव के पूर्व भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत का वादा किया था, लेकिन 2014–15 के रिवाइज्ड बजट में रकम घटा कर 70505 करोड़ रुपये कर दी गई. सरकार की योजनाओं की सफलता और असर तो 5 साल से पहले नहीं मापे जा सकते, लेकिन सरकार की नीयत ज़रूर बजट में शिक्षा के प्रति किये गए प्रावधान से झलकती है. पहले से घटाए हुए शिक्षा बजट में मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015–16 के बजट में और कटौती कर दी. वर्ष 2015–16 के आम बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए खर्च मात्र 69074.76 रुपये रखा गया है. बजट में सर्व शिक्षा अभियान में 20.74 प्रतिशत की कमी और और मध्याह्न भोजन योजना में 30.11 प्रतिशत की कमी की गयी है. हालांकि राज्यों के लिए योजना धन के आवंटन में वृद्धि की गयी है, लेकिन कुल योजना आवंटन इस वर्ष के लिए 19 प्रतिशत से नीचे आ गया है. हमारे स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य आसान नहीं है, एक साल में बड़े स्तर पर सुधार की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन पहले से ऋणी राज्यों के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि आवंटित कर देना भी समस्या का हल नहीं है. वित्त मंत्री ने इसी बजट में हर बच्चे से 5 किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल का वादा किया है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में गिरावट कुछ और संकेत देते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भारत के नवनिर्माण की बात करतें हैं और शिक्षा की अहमियत बताते हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गयी बातों पर और पहले साल में घोषित की गयी योजनाओं पर बजट के आंकड़े देख यकीन करना मुश्किल हो जाता है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले ही संसाधन की कमी के कारण ठीक से लागू नहीं हो पाया है और अब संसाधन में और कटौती की जा रही है. विशेषज्ञ बताते हैं शिक्षा उपकर ही अब शिक्षा के लिए फंड्स का मुख्य स्रोत बन गया है.

> **ऐसा नहीं है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बीते एक वर्ष में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन मंत्रालय का कोई भी काम अपने मंत्री के इर्द–गिर्द घूमते विवादों से बड़ा नहीं था. वर्तमान केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहले साल में की गयी सबसे बड़ी घोषणा या पहल एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की रही.**

एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे लगभग 31 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि माता–पिता ख़राब सरकारी स्कूल प्रणाली से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) फोरम के अम्बरीश राय के अनुसार, हमे 80,000 माध्यमिक स्तर के स्कूलों के सीनियर सेकेंडरी स्तर तक उन्नयन करने की आवश्यकता है, लेकिन बजट में किया गया आवंटन पर्याप्त रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा को भी कवर नहीं करेगा. भारतीय जनता पार्टी के पिछले एक वर्ष के 2 बजटों में शिक्षा क्षेत्र में स्थिर बजटीय आवंटन और किसी भी बड़ी रीएलोकेशन के न होने की वजह से शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों की कमी आई है. सरकार ने घोषणा की है कि कई नये उच्च शिक्षा संस्थान सीधे केंद्र सरकार की देखरेख में रहेंगे, लेकिन अभी तक पुराने संस्थानों को जिन्हें गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन की आवश्यकता है, कैसे बेहतर फंड किया जाये, इसके बारे में कोई नई सोच सामने नहीं आई है. एक साल तो बीत गया, लेकिन आगे आने वाले 4 सालों में यदि सरकार के मानव विकास संसाधन मंत्रालय का प्रदर्शन ऐसा ही रहा, तो 5 साल में भारत की जनता का संसाधन के रूप में विकास कैसे होगा, ये फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रहा. शिक्षा क्षेत्र की दो व्यापक सुधार प्राथमिकताओं–शिक्षा शास्त्र और संसाधन पर एक साल में किया गया काम संतोषजनक नहीं रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> जहां तक कृषि का सवाल है तो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छठवां हिस्सा कृषि से आता है. कृषि से सम्बंधित एक वास्तविकता यह भी है कि पिछले आठ–दस वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में खाद्यान के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. भारत भी इसके असर से बच नहीं पाया. तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद खाद्यान की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है. चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां कृषि की अहमियत और भी बढ़ जाती है.

कृषि क्षेत्र

अन्नदाता को अच्छे दिनों का इंतजार है...

शफीक आलम

नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरे हो गए. यहां हम मोदी सरकार के कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक साल के कार्यों पर नज़र डालेंगे. हालांकि एक साल का समय किसी नई सरकार के लिए कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाने के लिए काफी नहीं होता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना कार्यभार संभालते ही अपने मंत्री परिषद की बैठक में अपनी सरकार का 10 सूत्री विज़न पेश किया था, इस क्रम में उन्होंने अपने मंत्रियों को उनके मंत्रालय के कार्यों से सम्बन्धित 100 दिनों का एजेन्डा तय करने, कार्यों की प्राथमिकता तय करने और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया था. आम तौर पर किसी नई सरकार से जनता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार से ये अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही हैं. इसकी वजह चुनाव प्राचार के दौरान गुजरात मॉडल के सफलता का प्रचार और खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जुड़े देश के युवाओं (जिन्होंने 2014 के आम चुनाव मे सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया था) की आशाएं हैं. साथ ही 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है. इसलिए इस बार मोदी सरकार पर गठबंधन धर्म के पालन का भी दबाव नहीं है. उन्हें अपनी सरकार की नीतियों को लागू करने की पूरी आज़ादी है. लिहाज़ा, यही वजह है कि उनके कार्यकाल के हर लैंडमार्क पर उनकी सरकार के कामों की जांच–परख होगी.

जहां तक कृषि का सवाल है तो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छठवां हिस्सा कृषि से आता है. कृषि से सम्बंधित एक वास्तविकता यह भी है कि पिछले आठ–दस वर्षों के दौरान पूरी दुनिया में खाद्यान के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. भारत भी इसके असर से बच नहीं पाया. तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद खाद्यान की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है. चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां कृषि की अहमियत और भी बढ़ जाती है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दस–बीस वर्षों में भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के पार हो जाएगी. इसलिए इतनी बड़ी आबादी तक अगर खुराक पहुंचाना है तो भारत को कृषि पर विशेष ध्यान देना होगा. खास तौर पर उस वक़्त जब संयुक्त राष्ट्र संघ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अधिक भूखे लोगों की संख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है. बहरहाल, अगर किसानों की समस्याओं को देखा जाए तो वे आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं. हालांकि, पिछले कुछ दशकों से भारत में खाद्यान की पैदावार दोगुनी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. किसानों द्वारा आत्महत्या, मौसम की मार के चलते फसल की बर्बादी, लगातार खेती की वजह से ज़मीन की उर्वरा शक्ति में कमी, कृषि ऋण के लिए किसानों का क्षेत्रीय साहूकारों पर आश्रित रहना, सिंचाई के लिए वर्षा पर अधिक निर्भरता, खेती में आधुनिक तकनीक का न्यूनतम इस्तेमाल और अनाज भंडारण की सुविधा का अभाव आदि ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे किसान आज भी जूझ रहा है.

केंद्रीय कृषि मंत्री राधे मोहन सिंह ने अपने मंत्रालय के कार्य का लेखा–जोखा देते हुए एक अष्ठ बार को बताया कि उनकी सरकार कृषि और उससे सम्बंधित क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव लाने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार दशकों से उपेक्षा का शिकार इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है. इस सिलसिले में सिंचाई तंत्र को मज़बूत बनाने, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड (स्वायल हेल्थ कार्ड) बनाए, ताकि खेत की क्षमता के अनुसार फसल उगाई जा सके. आमदनी से जुड़े बिमा योजनाएं और एक बाधारहित राष्ट्रीय कृषि बाज़ार की स्थापना, इत्यादि शामिल हैं. ज़ाहिर है, इन योजनाओं का प्रतिफल एक–दो साल के अन्दर नहीं आएगा. दूसरे यह कि इनकी सफलता का दारोमदार बहुत हद तक भी मौसम पर आधारित है.

कृषि क्षेत्र के लिए अगर पिछले बजट की बात की जाये तो इस में भी मिट्टी की उर्वरता को बचाए रखने के लिए जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए पूर्वोतर के राज्यों को 125 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई थी. अब उस पर कार्यान्वयन हो रहा है. उसी तरह चूंकि सिंचाई के लिए भारतीय किसान आज भी बारिश के ऊपर अधिक निर्भर हैं, इसलिए मौसम में बदलाव के चलते कम बारिश की वजह से खेती भी प्रभावित होती है. इसी के मद्देनज़र प्रति बूंद अधिक पैदावार के नारे के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड विकास के लिए बजट में 5,300 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया था.

पिछले साल मॉनसून की औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था. हालांकि मानसून देर से आया था, लेकिन बाद में हालात सुधर गए थे. इस पूर्वानुमान को देखते हुए सरकार ने आपदा योजना बनाई थी, जिसमें कम वर्षा वाले जिलों में किसानों को डीज़ल सब्सिडी, कम ब्याज दर पर कृषि ऋण, और खाद्यान्न की कमी होने पर इसकी आपूर्ति का प्रावधान था. इस साल भी मौसम विभाग ने कम बारिश की संभावना जताई है. ज़ाहिर है, ऊपर दर्ज सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभी समय लगेगा. इसलिए कृषि की सफलता और असफलता का सारा दारोमदार अब भी बारिश पर निर्भर है. खास तौर पर मानसून पर निर्भर है. बहरहाल, बारिश की कमी से निपटने के लिए सरकार ने योजना तो बना ली, लेकिन बेमौसम बारिश से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार के पास फ़िलहाल कोई स्पष्ट नीति नहीं है. इसकी मिसाल इस साल रबी फसल के दौरान बारिश की वजह से हुई बर्बादी में देखा जा सकता है. खास तौर पर मुआवजा वितरण में किस तरह का घालमेल हुआ, यह सब के सामने है.

बहरहाल, एक दूसरी अहम बात है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में भी उठाया था. उसमें उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की थी. उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो समर्थन मूल्य तय करने का एक नया फॉर्मूला लाएगी. दरअसल, यह फॉर्मूला स्वामीनाथन समिति की शिफारिशों पर आधारित था. इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि समर्थन मूल्य तय करते समय किसान की फसल पर उसकी लागत के बाद पचास प्रतिशत मुनाफा दिया जाए, लेकिन इस बार सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है, उस में केवल 10 प्रतिशत का मुनाफा दिया गया है. इससे तो यही साबित होता है कि कृषि देश में सबसे अधिक जोखिम भरा व्यवसाय होने के साथ–साथ सबसे कम लाभ का व्यवसाय है. दूसरी तरफ किसानों की आत्म हत्याएं बदस्तूर जारी हैं. ऊपर से भूमि अधिग्रहण बिल पर बने गतिरोध से यह सन्देश जा रहा है कि सरकार किसान विरोधी है. बहरहाल, इजराइल से कृषि में सहयोग के लिए तीसरे दौर के समझौते के बावजूद भारतीय कृषि अब भी मौसमपर आश्रित है. कहने का अर्थ यह कि किसानों को अच्छे दिन के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा.

अब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक साल के कार्य पर नज़र डालते हैं. प्रधानमंत्री के आदेश पर इस विभाग के मंत्री रामविलास पासवान ने भी अपने 100 दिनों के कार्य का एजेंडा तैयार किया था, जिसमें अनाज भंडारण की सुविधाओं में विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी. अपने चुनाव प्रचार में नरेन्द्र मोदी ने इस मुद्दे को बड़े जोर–शोर से उठाया था. खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि सड़ रहे अनाज को वितरित कर दिया जाए, लेकिन यूपीए सरकार ने इस पर अमल नहीं किया था. भारत में खाद्यान्न का भंडारण एक बहुत बड़ी समस्या है. हर साल, खास कर बरसात के मौसम में स्टोरेज सुविधाओं के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर अनाज सड़ जाते हैं. यह समस्या कई सालों से जस की तस बनी हुई है. 2014 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने यह अनुमान लगाया था कि जून के महीने में जब मानसून अपने शबाब पर होगा तो 231.82 लाख टन गेहूं तीन राज्यों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ होगा. इसीलिए एफसीआई ने राज्यों को ग़रीबों में अनाज वितरण की आवंटन सीमा बढ़ा कर 750 लाख टन करने की सिफारिश की थी. उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भंडारण की सुविधा बढ़ाने को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए. इस सम्बन्ध में एफसीआई निजी क्षेत्र के सहयोग से अपने भंडारण के सुविधा को विस्तार देने का प्रस्ताव रखा है. ज़ाहिर है, इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर समय लगेगा. एक बार फिर मानसून सिर पर है, अब देखना यह है कि अनाज को सड़ने से बचाने के लिए सरकार कौन सा उपाय करती है?

इस विभाग के मंत्री रामविलास पासवान ने यह घोषणा की कि संसद के मानसून सत्र में भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) अधिनियम 1986 में संसोधन प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके तहत मौजूदा 102 वस्तुओं के बजाए 2300 वस्तुओं के लिए बीएसआई मानक अनिवार्य होगा. मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून में सशोधन कर एक उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और दूसरे उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है. साथ ही एक एकीकृत राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी गठित की गई है. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए प्राइस मॉनिटरिंग सेल स्थापित की गई है.

मंत्रायल ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 100 लाख टन गेहूं खुले बाज़ार में बेचने का फैसला किया है. बीपीएल और राशन कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त 50 लाख टन चावल आवंटित किया गया है. आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद में शामिल किया गया है. इसके साथ–साथ एपीएमसी एक्ट में संसोधन, जमा खोरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ–साथ राज्यों को अपनी कीमत निगरानी इकाई स्थापित करने की सलाह दी गई है. साझा अंतरराज्यीय बाज़ार की स्थापना. गन्ना किसानों की लंबित भुगतान की समस्या से निपटने और चीनी उद्योग को गतिशील बनाने के लिए क़दम उठाये गये हैं. एफसीआइ के कार्यों के निपटारे के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा रही है. इसके अतरिक्त 16 और राज्यों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल कर लिया गया है. इससे पहले केवल 11 राज्य इसमें शामिल थे. इस मंत्रालय द्वार उठाये गए अधिकतर नये क़दमों का लाभ तुरंत नहीं ज़ाहिर होगा. इनमें बहुत से फैसले ऐसे हैं, जिन पर अमल होना बाकी है. इसलिए इस मंत्रालय के कार्य को असल पड़ताल के लिए कुछ समय और दिया जाना चाहिए.

मंत्रायल ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 100 लाख टन गेहूं खुले बाज़ार में बेचने का फैसला किया है. बीपीएल और राशन कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त 50 लाख टन चावल आवंटित किया गया है. आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद में शामिल किया गया है. इसके साथ-साथ एपीएमसी एक्ट में संसोधन, जमा खोरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राज्यों को अपनी कीमत निगरानी इकाई स्थापित करने की सलाह दी गई है.

मंत्रालय के कार्यों में चीनी उद्योग पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी मार गन्ना किसानों पर भी पड़ा है. साथ ही देश में फैले सहकारी क्षेत्र की गन्ना मिलें तो बंद होने के कगार पर आ पहुंची हैं. इस सम्बन्ध में चौथी दुनिया ने मराठवाड़ा की सहकारी क्षेत्र की चीनी मीलों को बंद किये जाने की साजिश पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अभी काफी दूरी तय करनी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस अच्छे दिनों का सपना लोगों को दिखाया था, उसको पूरा होते देखने के लिए लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस साल के बजट में स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़ी कटौती की गई है. सरकार ने सबसे पहले आईसीडीएस जैसी योजना के बजट में बड़ी कटौती की है, जो कुपोषण से लड़ने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, इसे लेकर कई तरह की नकारात्मक बातें भी समय-समय पर आती रही हैं, कई विश्लेषक इस योजना को सफेद हाथी तक कह चुके हैं, लेकिन इस योजना के बजट में कटौती का सीधा असर शिशुओं, किशोरों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ा है. यह योजना कई दशकों से चल रही है, लेकिन देश में कुपोषण के मामलों में कमी नहीं आ पाई है. इसलिए किसी वैकल्पिक योजना की शुरुआत की बात सरकार ने नहीं की है.

स्वास्थ्य बजट में कटौती

कैसे होगा स्वस्थ भारत का निर्माण

भारत सरकार ने बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष नामक एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत बच्चों की जान को ख़तरे में डालने वाली सात बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हैपेटाइटिस-बी आदि से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा. इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को अपने दायरे में लाना है, जिनका उक्त सात टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध या तो टीकाकरण हुआ नहीं है अथवा आंशिक टीकाकरण हुआ है. साल 2013 तक देश के केवल 65 प्रतिशत बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाया जा सका है.

नवीन चौहान

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है. कहा जाता है कि किसी भी सरकार के पहले वर्ष में उसके काम करने की दशा और दिशा निर्धारित हो जाती है. नवगठित सरकार के ऊपर सबसे पहले अपने चुनावी वादे पूरे करने और चुनावी घोषणा-पत्र को अमलीजामा पहनाने का दबाव होता है, क्योंकि सरकार से लोगों की कई तरह की आशाएं जुड़ी होती हैं. एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया. मोदी सरकार भले ही नई स्वास्थ्य नीति की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन आवंटन में कमी से उसकी कथनी-करनी का भेद दिखाई दे जाता है. ढाई दशकों बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के गठन के बाद आशा की गई थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार अपनी प्राथमिकता में रखेगी और उसमें सुधार के लिए आवश्यक एवं कड़े क़दम उठाएगी, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कटौती करके सही संदेश नहीं दिया.

इस साल के बजट में स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़ी कटौती की गई है. सरकार ने सबसे पहले आईसीडीएस जैसी योजना के बजट में बड़ी कटौती की है, जो कुपोषण से लड़ने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि, इसे लेकर कई तरह की नकारात्मक बातें भी समय-समय पर आती रही हैं, कई विश्लेषक इस योजना को सफेद हाथी तक कह चुके हैं, लेकिन इस योजना के बजट में कटौती का सीधा असर शिशुओं, किशोरों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ा है. यह योजना कई दशकों से चल रही है, लेकिन देश में कुपोषण के मामलों में कमी नहीं आ पाई है. इसलिए किसी वैकल्पिक योजना की शुरुआत की बात सरकार ने नहीं की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए वर्ष 2015 में निर्धारित शताब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के भारत के प्रयास बेहद निराशाजनक रहे हैं. निर्धारित दस लक्ष्यों में से वह महज चार ही हासिल कर पाया है और बाकी के सबंध में हुई प्रगति भी न के बराबर है. हो सकता है कि सरकार आईसीडीएस की जगह कोई और योजना लाना चाहती हो, लेकिन इस तरह के कोई संकेत सरकार द्वारा अब तक पेश किए गए दो बजटों में तो दिखाई नहीं दिए हैं.

भारत के लिए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में अपेक्षित कमी न आ पाना अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है. भले ही इसमें अब तक जो भी कमी है, बावजूद उसके अब भी वह सहारा के अफ्रीकी देशों के समकक्ष खड़ा दिखता है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के चलते मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज़्यादा है. दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे खराब हालत में है. सरकार की नीतियां अगले चार सालों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की होनी चाहिए. इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले एक साल में इस दिशा में कोई बड़े क़दम नहीं उठाए हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं की रूपरेखा में बदलाव की आशा की जा रही थी, जिस पर शहरी एवं ग्रामीण ग़रीब पूरी तरह निर्भर हैं.

संसदीय कमेटी ने स्वास्थ्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बजटीय आवंटन पर चिंता जाहिर की है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स शेयर को 42 प्रतिशत करने की वजह से केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य बजट की ज़िम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी है. यदि ऐसा हुआ है, तो ग़रीब और पिछड़े राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीधा असर पड़ेगा. स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय मद में कमी का सीधा असर सरकार के नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन पर पड़ेगा, जिसमें लोगों को मुफ्त दवाएं देने और जांच किए जाने का प्रावधान है. यदि सरकार स्वास्थ्य बजट में आवश्यक इज़ाफा नहीं करती है, तो प्रधानमंत्री के चुनावी वादे सिर्फ़ वादे बनकर रह जाएंगे.

स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का अंश खर्च करने के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों से बहुत पीछे है. कुल स्वास्थ्य बजट का 40 प्रतिशत रिसर्च, मैन पॉवर के विकास, नियंत्रण और महंगी दवाएं थोक में खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा. सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत 58 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है. अगले पांच वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर 14 नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे. नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद देश में सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 के आसपास पहुंच जाएगी. देश में फिलहाल 398 मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की डिग्री देते हैं, जिनमें 52,105 सीटें हैं. यह संख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अपर्याप्त है. दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जनसंख्या के लिहाज से बेहद कम है. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 32 और बिहार में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हैं. लेकिन, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नए संस्थानों के लिए गुणवत्ता वाला वर्क फोर्स तैयार करने की है, ताकि नए संस्थान एम्स-दिल्ली के बराबर गुणवत्ता से कार्य कर सकें.

मोदी सरकार के पास अपने वादे पूरे करने के लिए चार साल का समय है. फिलहाल सरकार जीडीपी का 1.2 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का पांच प्रतिशत खर्च करने की बात कहता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सरकार ने स्वास्थ्य बजट में महज दो प्रतिशत की वृद्धि की है, जो कि महंगाई की दर (इन्फ्लेशन) की तुलना में कम है. ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी बढ़ोत्तरी हुई है, उससे कुछ होने वाला नहीं है. वर्तमान में देश की तक़रीबन 17 प्रतिशत आबादी ही स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आती है. सरकार ने इसमें बढ़ोत्तरी करने के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए करों में छूट की सीमा बढ़ा दी है. इसका असर भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन ने तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने के लिए कई तरह के क़दम उठाए थे, जिनमें तंबाकू उत्पादों पर पिक्टोरियल वार्निंग के आकार में बढ़ोत्तरी और सिगरेट की खुदरा बिक्री पर रोक जैसे निर्णय शामिल थे. ऐसे में कहा गया कि तंबाकू लॉबी की वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाकर विज्ञान मंत्रालय में भेज दिया गया.

भारत के लिए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में अपेक्षित कमी न आ पाना अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है. भले ही इसमें अब तक जो भी कमी है, बावजूद उसके अब भी वह सहारा के अफ्रीकी देशों के समकक्ष खड़ा दिखता है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के चलते मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज़्यादा है. दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे खराब हालत में है. सरकार की नीतियां अगले चार सालों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की होनी चाहिए.

भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले जारी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में देश के स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता देते हुए कहा था कि उसकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी. भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में यह भी कहा था कि यूपीए सरकार की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है. इस योजना में मूलभूत बदलाव किए जाने की आवश्यकता है. भाजपा स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे उच्च वरीयता देती है. इसलिए सरकार नई स्वास्थ्य नीति लेकर आएगी. सरकार ने अपने घोषणा-पत्र के अनुरूप पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास पर ज़ोर देते हुए आयुष (आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्ध) के लिए अलग से 1,214 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. आयुष पिछले साल तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक अलग मंत्रालय बना दिया. सरकार उपचार की इन प्राचीन पद्धतियों को जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित कर रही है. भारत सरकार की पहल के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने इसी साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

देश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने की नीयत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की. दो अक्टूबर, 2014 को इस अभियान की विधिवत शुरुआत की गई. प्रधानमंत्री के झाड़ू उठाने के बाद मंत्रियों एवं अधिकारियों के बीच झाड़ू पकड़ कर फोटो खिचाने की जैसे होड़ मच गई. लेकिन सात महीने बाद भी यह अभियान परवान नहीं चढ़ सका है. नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर यह अभियान आगे बढ़ रहा है. जिन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ने इस अभियान के लिए नामांकित किया था वे भी फोटो खिचवा कर और खानापूर्ति करके आगे बढ़ गए. अब किसी को इस अभियान की सुध नहीं है. सिर्फ़ नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे में दिए गए भाषणों में स्वच्छ भारत अभियान नज़र आता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है.

भारत सरकार ने बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष नामक एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत बच्चों की जान को ख़तरे में डालने वाली सात बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हैपेटाइटिस-बी आदि से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा. इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को अपने दायरे में लाना है, जिनका उक्त सात टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध या तो टीकाकरण हुआ नहीं है अथवा आंशिक टीकाकरण हुआ है. साल 2013 तक देश के केवल 65 प्रतिशत बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाया जा सका है. इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में 50 जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त में देने की शुरुआत की गई है. सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.सरकार ने बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत से क़दम उठाए हैं, लेकिन उनका ज़मीन पर असर कम दिखाई देता है. नई स्वास्थ्य नीति आने के बाद ही स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति सरकार की मंशा जाहिर हो जाएगी. मोदी सरकार का पहला साल कायाकल्प की तैयारी में बीत गया. ये तैयारियां किस तरह और कब परवान चढ़ेंगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा. ऐसे में नए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी पूरे करने की चुनौती भारत के सामने होगी, जिनके लिए 2015 से लेकर 2030 तक का समय निर्धारित किया गया है. इसकी झलक मोदी सरकार के अगले चार सालों में दिखाई देगी.■

navinonline2003@gmail.com

कटौती दर कटौती

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद साल 2014-15 के बजट में स्वास्थ्य बजट में 27 फ़ीसद का इजाफा किया था. लेकिन अक्टूबर आते-आते उसमें 20 प्रतिशत की कटौती भी कर दी. सरकार ने एड्स कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन में 30 प्रतिशत की कटौती की थी. जबकि संयुक्त राष्ट्र के साल 2013 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एड्स के मरीज भारत में हैं. इसके बाद साल 2015-16 के बजट में साल 2014-15 के मुख्य स्वास्थ्य बजट की तुलना में महज दो प्रतिशत का इज़ाफा किया, जो कि महंगाई में वृद्धि की तुलना में काफी कम है.■

मोदी की विदेश नीति का संचालन नौकरशाह कर रहे हैं. क्या इसके पीछे कारण यह है कि मोदी की विदेश नीति पर अपनी कोई दृष्टि नहीं है, अनुभव नहीं है. अनुभव के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी न तो विदेश नीति के अध्येता रहे हैं और न वह कभी विदेश मंत्री रहे हैं, जबकि जवाहर लाल नेहरू आज़ादी मिलने के पहले से कांग्रेस का विदेश विभाग संभाले हुए थे. अटल बिहारी वाजपेयी 1977 से लेकर 1979 तक विदेश मंत्री रह चुके थे और नरसिम्हा राव भी दो बार विदेश मंत्रालय संभाल चुके थे. दूसरी तरफ़ मोदी का स्वभाव भी अनुभवी विशेषज्ञों से फ़ायदा उठाने का नहीं है. मोदी की विदेश यात्राओं से ऐसा कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, जो पहले की यात्राओं से न हुआ हो.

मोदी की विदेश यात्राएं

देश को आख़िर क्या मिला

प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की कोई अंतरराष्ट्रीय छवि नहीं थी. ऐसे में अगर मोदी ने देशों को समझने और उन्हें जानने के लिए विदेशी दौरे किए, तो उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए. लेकिन, जनता को इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन यात्राओं से भारत को हासिल क्या हुआ? मोदी ने अप्रवासी भारतीयों को अपने भाषण से सम्मोहित किया, बड़े शो और धमाल किए, लेकिन अपने बड़बोलेपन के चलते वह कुछ ऐसी बातें कह गए, जिनसे हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया. विदेश मसले पर अपनी कोई मौलिक दृष्टि न होने के कारण मोदी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, जहां से भारत के विश्व महाशक्ति बनने का कोई रास्ता तैयार हो सके.

राजीव रंजन

प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही साल में नरेंद्र मोदी ने जितनी विदेश यात्राएं की हैं, उतनी अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कीं. पहले ही साल में मोदी पड़ोसी और शक्तिशाली देशों में तो हो आए, लेकिन उनकी यात्राओं के दौरान कोई ठोस नीतिगत क़दम नहीं दिखाई दिए. न तो दक्षिण एशिया के महासंघ की कोई पहल हुई, न विश्व राजनीति के किसी महत्वपूर्ण मसले पर हमने कोई क़दम उठाया और न सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सीट का प्रबंध हुआ. अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद दक्षिण एशिया में जो संकट आने वाला है, उसके मुक़ाबले की भी कोई तैयारी नहीं है. मोदी सरकार ने अपनी अब तक की विदेश यात्राओं के दौरान कनाडा से यूरेनियम आपूर्ति, फ्रांस से राफेल एवं रेलवे पर समझौते के अलावा जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर ज़रूर किए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, तो मोदी की विदेश यात्रा पहले के प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं की तुलना में बहुत खास नहीं रही. मोदी के व्यवहार में दिखावा ज़्यादा है, जबकि नीतिगत दृष्टि का अभाव है. सही मायने में देखा जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रचार मंत्री साबित हुए.

अपनी विदेश यात्राओं के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी भूल यह की कि अपनी जनसभाओं में उन्होंने एक-दो बार भारत की आंतरिक राजनीति को भी घसीट लिया. मोदी के इस क़दम को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भले ही आप इसके माध्यम से थोड़ी-बहुत अपनी राजनीति चमका लें, लेकिन विदेशी मंचों पर आप अपने देश का नाम बदनाम होने से नहीं रोक सकते. चीन में उन्होंने यह कह दिया कि उनकी सरकार आने के पहले भारतीय होना कोई गर्व की बात नहीं थी. यह बयान घोर आपत्तिजनक है, लेकिन ज़ुबान से निकली हुई बात भला कहां वापस लौटती है. मोदी ने विदेशी राष्ट्रपतियों एवं प्रधानमंत्रियों को अपने हाव-भाव और लटकों-झटकों से प्रभावित तो किया, लेकिन अपनी इन यात्राओं के दौरान मोदी के व्यवहार में न तो जवाहर लाल नेहरू एवं पीवी नरसिम्हा राव जैसी गंभीरता देखने को मिली और न इंदिरा गांधी एवं अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तिगत आकर्षण देखने को मिला. मोदी को यह नहीं भूलना चाहिए कि विदेश नीति का धरातल बहुत सख्त होता है और उस ज़मीन पर कोरी भावुकता ज़्यादा काम नहीं आती, क्योंकि आख़िरकार विदेशी आपके देश में उस माहौल को खोजने आएंगे, जिसका भरोसा आप उन्हें विदेशी धरती पर देकर आए हैं.

मोदी की विदेश नीति का संचालन नौकरशाह कर रहे हैं. क्या इसके पीछे कारण यह है कि मोदी की विदेश नीति पर अपनी कोई दृष्टि नहीं है, अनुभव नहीं है. अनुभव के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी न तो विदेश नीति के अध्येता रहे हैं और न वह कभी विदेश मंत्री रहे हैं, जबकि जवाहर लाल नेहरू आज़ादी मिलने के पहले से कांग्रेस का विदेश विभाग संभाले हुए थे. अटल बिहारी वाजपेयी 1977 से लेकर 1979 तक विदेश मंत्री रह चुके थे और नरसिम्हा राव भी दो बार विदेश मंत्रालय संभाल चुके थे. दूसरी तरफ़ मोदी का स्वभाव भी अनुभवी विशेषज्ञों से फ़ायदा उठाने का नहीं है. मोदी की विदेश यात्राओं से ऐसा कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, जो पहले की यात्राओं से न हुआ हो. जापान, चीन, दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका आदि देशों ने लगभग 70-80 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है. आतंकवाद पर लगभग हर देश ने भारत के साथ सहमति जताई है. द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ी हैं. यानी वही हुआ, जो प्राय: हर प्रधानमंत्री की यात्रा में होता है.

भारत के लिए ऊर्जा और रेलवे काफी अहम हैं. जर्मनी के साथ ऊर्जा, कौशल विकास, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी. वहीं कनाडा भारत को तीन हज़ार मीट्रिक टन यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है. कनाडा रेलवे के आधुनिकीकरण में भी भारत को सहयोग देगा, लेकिन इन मुद्दों पर अभी बातचीत का दौर जारी है. भारत को तत्काल परमाणु ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बातचीत का लंबा दौर चलेगा. निवेश और तकनीकी हस्तांतरण के मामले में इन देशों की भी अपनी मांगें होती हैं. वे चाहते हैं कि उन्हें भारत में सस्ती ज़मीन मिले, करों में छूट दी जाए.

भारत के लिए ऊर्जा और रेलवे काफी अहम हैं. जर्मनी के साथ ऊर्जा, कौशल विकास, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी. वहीं कनाडा भारत को तीन हज़ार मीट्रिक टन यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है. कनाडा रेलवे के आधुनिकीकरण में भी भारत को सहयोग देगा, लेकिन इन मुद्दों पर अभी बातचीत का दौर जारी है. भारत को तत्काल परमाणु ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बातचीत का लंबा दौर चलेगा. निवेश और तकनीकी हस्तांतरण के मामले में इन देशों की भी अपनी मांगें होती हैं. वे चाहते हैं कि उन्हें भारत में सस्ती ज़मीन मिले, करों में छूट दी जाए. ये देश कई क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढ़ाना चाहते हैं. क्या मोदी सरकार इन देशों की मांगें पूरी करने की स्थिति में है? देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. बेरोज़गारी और ग़रीबी किसी से छिपी नहीं है. भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है. इतना ही नहीं, भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे भारत में जो माहौल है, उसके बारे में सभी जानते हैं. श्रम सुधार जैसे जटिल मसले भी सामने हैं. इन सबका तात्कालिक समाधान मुश्किल है. सरकार कई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन परेशानी यह है कि लोकतंत्र में बदलाव आने में समय लगता है. ऐसे में इन देशों की मांगों को पूरा करना मुश्किल है.

जर्मनी की चांसलर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत तो किया, लेकिन जर्मनी का भारत प्रेम यानी भारत के साथ साझीदारी का मसला सिरे नहीं चढ़ा है. यूरोपीय साझा बाज़ार यानी ब्रूसेल से मुक्त व्यापार करार के बाद ही गति बनेगी. फ्रांस, जर्मनी एवं कनाडा तीनों विकसित पश्चिमी देश हैं. फ्रांस और जर्मनी यदि भारत को अपना मानते हुए नीति बनाएं, तो यूरोपीय साझा बाज़ार और निवेश में बहुत फ़ायदा होगा. सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की यात्रा से इन देशों की सोच बदली होगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विदेश यात्रा पर चाहे कितना भी बड़ा धमाल या शो क्यों न हुआ हो, लेकिन भारत में उनकी विदेश यात्राओं की चमक अब धूमिल होने लगी है. अब पहले की तरह चार्म नहीं रहा, क्योंकि मोदी की विदेश यात्राओं से वास्तविकता में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया, जो पहले की तुलना में मील का पत्थर साबित हो. कोई भी सरकार एक-दो समझौते ऐसे कर ही लेती है, जो पहले न हुए हों या उन समझौतों पर पहले से गतिरोध चला आ रहा हो. भारत की अंदरूनी छोटी-छोटी बातों से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं हाशिये की ओर बढ़ रही हैं, उनका शोर कोने में दबता जा रहा है.

रूस आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है. इसलिए कारोबार और निवेश के लिहाज से वह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है. चीन भारत का मुख्य कारोबारी सहयोगी है. चीन के नए प्रधानमंत्री भी बहुत विदेश यात्राएं कर रहे हैं. अगर हम चीन से अपनी तुलना करें, तो उपलब्धियों के मामले में चीन का विदेश विभाग रिकॉर्ड तोड़ तैयारियां किए हुए होता है. वहीं हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में भारतवंशियों का दिल जीतने और उससे ब्रांडिंग का मकसद जाहिर होता है. सच मायने में देखा जाए, तो सौदे पटाने के मामले में चीन को गजब की काबलियत हासिल है. दूसरी ओर चीन के मुद्दे पर हमें यह भी सोचना होगा कि आर्थिक व सैन्य दृष्टि से भारत कमजोर है और मोदी कितने ही बड़े राष्ट्रवादी क्यों न हों, लेकिन वह पेइचिंग से लड़ाई मोल लेना नहीं चाहेंगे. चीन अगर आज वैश्विक ताकत बनकर उभरा है, तो अपनी आर्थिक ताकत के कारण. इसलिए चीन के सामने खड़े होने के लिए मोदी को पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा.

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मोदी ने पहल की और उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया, लेकिन उसके बाद उनकी पाक-नीति अधर में लटक गई. जबकि मोदी के प्रति औसत पाकिस्तानी के मन में कटुता होने के बावजूद वहां के नीति निर्माता चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध सुधरें. लेकिन, मोदी की पाक-नीति हुर्रियत के कीचड़ में फिसल गई. सरहद पर गोलीबारी में अमन-चैन की कोशिशों के लिए उठ रही आवाज़ दबी सो अलग. दोनों देशों की फौजों, सत्ता प्रतिष्ठानों और सतही लोकमत से ऊपर उठकर बड़े फ़ैसले करने की हिम्मत जब तक मोदी नहीं जुटाएंगे, उनकी नीतियां इसी तरह लंगड़ाती रहेंगी. यदि मोदी भारतीय विदेश नीति को पाकिस्तानी फांस से निकाल सकें, तो उन्हें भारत के सारे प्रधानमंत्रियों में सर्वोपरि स्थान मिल सकता है.

विभिन्न देशों के कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, तो कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़ा निवेशक उसी जगह पर निवेश करता है, जहां उसे सारी सुविधाएं मिलें, उसे लाभ हो. जब लाभ की स्थिति होती है, तो वह बना रहता है, लेकिन जैसे ही स्थिति विपरीत होती है, वह चला जाता है. जबकि विकास के लिए लॉन्ग टर्म तक कॉरपोरेट इंटरेस्ट को बनाए रखना ज़रूरी है. यह लंबे समय के लिए साझेदारी की दरकार है. फिलहाल सरकार की नीतियों में इसका कोई समाधान नहीं दिखता. भविष्य में भी मोदी ऐसा कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी. एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मोदी सरकार विकसित देशों या किसी भी ऐसे देश के व्यापारिक मापदंडों पर तभी खरी उतर सकती है, जब वह भारत के केंद्र निर्देशित और अतिशय संरक्षित अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने के अपने वादे को पूरा कर सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके.■

feedback@chauthiduniya.com

अब बात करते हैं मुसलमानों के साथ देश में होने वाले भेदभाव की. भारत का संविधान भले ही धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति न देता हो, लेकिन आज़ादी के 67 वर्षों से अधिक समय गुज़र जाने के बावजूद आज भी जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदवभाव हो रहा है. हाल में मुंबई के ज़ीशान को मुसलमान होने के कारण हरि कृष्णा नामक कंपनी में नौकरी न मिलना इसका ताजा उदाहरण है. इस तरह के भेदभाव को मद्देनज़र रखते हुए सच्चर कमेटी ने समान अवसर आयोग गठित करने की सिफ़ारिश की थी, ताकि अल्पसंख्यकों, विशेषत: मुसलमानों के साथ अगर धार्मिक आधार पर कहीं भेदभाव होता है कि तो यह आयोग उस पूरे मामले की जांच–पड़ताल कर सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके.

मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति

विश्वास बहाली बाक़ी है

डॉ. क़मर तबरेज़

पिछले वर्ष 16 मई को सोलहवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित हुए. देश की जनता ने पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने का अवसर दिया. लिहाज़ा, 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई सरकार के जिन 25 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, उनमें से एक नाम अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह का भी था. नजमा हेपतुल्लाह को यह मंत्रालय यूपीए सरकार के दौरान इस पद पर रहे कांग्रेस के के. रहमान खान के बाद मिला. मुसलमानों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार से यह शिकायत रही कि उसने अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को लेकर नीतियां तो बहुत अच्छी–अच्छी बनाईं, लेकिन वह उन नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू कराने में असफल रही. इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय की बेबसी और अक्षमता को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया. आइए देखते हैं कि 26 मई, 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभाल रहीं डॉ. नजमा हेपतुल्लाह ने क्या–क्या काम किए हैं और क्या मुसलमान उनके कामों से संतुष्ट हैं अथवा नहीं?

नजमा हेपतुल्लाह पर बात करने से पहले कुछ चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि और उन्हें लेकर मुसलमानों की चिंता पर भी करते चलें, तो आगे की बातों को समझना अधिक आसान होगा. 2002 के गुजरात दंगे तब हुए थे, जब नरेंद्र मोदी उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, इसलिए मुसलमानों की ओर से उसके लिए ज़िम्मेदार सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को ही ठहराया गया. 2002 से लेकर अब तक लगभग 13 वर्ष गुज़र चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी लाख कोशिशों के बावजूद मुसलमानों की इस शिकायत को दूर नहीं कर सके हैं. 2014 के संसदीय चुनाव से पहले अपने कई टीवी साक्षात्कारों में उन्होंने यह संदेश की देने की ज़रूर कोशिश की कि मुसलमानों को उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि उनके काम देखकर मुसलमान उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेंगे. सबका साथ–सबका विकास जैसा नारा देकर भी उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की कि उनकी नज़र में हिंदू और मुसलमान बराबर हैं और देश के विकास का मतलब है, सबका विकास. धर्म की बुनियाद पर किसी से भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन एक वर्ष गुज़र जाने के बाद, मुसलमानों को लेकर देश में जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे मोदी सरकार पर विश्वास बहाल होने के बजाय अल्पसंख्यकों की चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं.

अब नज़र डालते हैं अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह के कार्यों पर. सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह काम में विश्वास रखती है, बातों में नहीं. लेकिन 26 मई, 2014 से जैसे–जैसे समय आगे बढ़ता गया, मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने ऐसे–ऐसे विवादित बयान दिए, जिनसे बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें निरंतर बढ़ती रहीं और यह सिलसिला आज भी जारी है. नजमा हेपतुल्लाह ने भी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभालते ही ऐसे कई विवादित बयान दिए, जिनकी हर तरफ़ निंदा हुई. मसलन 14 जुलाई, 2014 को उन्होंने कहा कि भारत की अल्पसंख्यक बिरादरी असल में पारसी हैं, मुसलमान नहीं. इसी तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, का समर्थन करते हुए अगस्त 2014 में नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि सभी भारतीयों को हिंदू कहने में कोई बुराई नहीं है. जब उनके इस बयान की निंदा हुई, तो उन्होंने सफ़ाई देते हुए कहा, मैंने भारत में रहने वाले लोगों को हिंदी कहा था, हिंदू नहीं.

यह तो विवादित बयानों की बात थी. अब देखते हैं कि काम के स्तर पर नजमा हेपतुल्लाह ने शुरुआती दिनों में क्या–क्या किया. आठ जुलाई, 2014 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में अपने मंत्रालय की कई स्कीमों के बारे में बताते हुए नजमा हेपतुल्लाह ने कहा कि उनका मंत्रालय अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैरिट कम मींस स्कॉलरशिप मुहैया करा रहा है. यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्कॉलरशिप की उक्त स्कीमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई थीं, जिनसे अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिली. हैरानी की बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने केंद्र सरकार की इस स्कीम को अपने यहां लागू करने से मना कर दिया था, जिससे गुजरात के अल्पसंख्यक छात्रों का काफ़ी नुक़सान हुआ. लेकिन, आज केंद्र की सत्ता संभालने के बाद उन्हीं की एक कैबिनेट मंत्री राज्यसभा को इस स्कीम का विवरण बता रही हैं. नजमा हेपतुल्लाह ने राज्यसभा को यह भी बताया कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के तहत अल्पसंख्यक स्कॉलर्स को उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है.

उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय की ओर से मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) के तहत देश भर में अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 117 आईटीआई, 44 पॉलिटेक्निक, 645 हॉस्टल, 1092 स्कूल भवन और 20,656 अतिरिक्त क्लास रूम बनाने की स्वीकृति दे दी गई है. यहां पर ग़ौर करने वाली बात यह है कि अल्पसंख्यकों को लेकर पिछली मनमोहन सिंह सरकार के काम करने का तरीक़ा भी कुछ ऐसा ही था. यह घोषणा तो कर दी जाती थी कि इतने आईटीआई, हॉस्टल, अतिरिक्त क्लास रूम आदि बनाए जाएंगे, लेकिन उन पर ज़मीनी स्तर पर कहीं काम हुआ भी या नहीं, सरकार यह बात कभी बताती नहीं थी. मोदी सरकार में हम यह उम्मीद करते हैं कि जब ये सारे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हॉस्टल, स्कूल भवन और अतिरिक्त क्लास रूम अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बनकर तैयार हो जाएंगे, तो सरकार जनता को यह ज़रूर बताएगी कि वे कहां–कहां बने हैं, ताकि अगर कोई वहां जाकर देखना चाहे, तो ज़रूर देख ले और अल्पसंख्यकों को यह भरोसा हो जाए कि वाकई में मोदी सरकार उनके लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है. फिलहाल, मोदी सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर जनता के सामने ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है.

इसके बाद 22 जुलाई, 2014 को राज्यसभा में अल्पसंख्यकों से संबंधित एक और सवाल का जवाब देते हुए नजमा हेपतुल्लाह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में केंद्र सरकार की ओर से उनके मंत्रालय को 3,511 करोड़ रुपये सालाना बजट के रूप में दिए गए थे, जिनमें से 1789.55 करोड़ रुपये यानी 50.97 प्रतिशत रकम अन्य स्कॉलरशिप स्कीमों पर ख़र्च की गई. ये वही स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया. नजमा हेपतुल्लाह ने राज्यसभा को यह भी बताया कि देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को अगर कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए उनके मंत्रालय की ओर से मौलाना आज़ाद सेहत स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत ऐसे छात्र को इलाज कराने के लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी. उल्लेखनीय है कि यह स्कीम यूपीए सरकार के आख़िरी दिनों में शुरू की गई थी, जिसे मौजूदा मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है.

हैरानी की बात यह है कि नजमा हेपतुल्लाह को मालूम नहीं है कि भारत में ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है और वह केवल विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को पैसा बांटने में लगी हुई हैं. 14 अगस्त, 2014 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए नजमा हेपतुल्लाह ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है और इस सिलसिले में सरकार के अन्य मंत्रालयों से उन्हें ऐसी कोई संख्या अभी तक हासिल नहीं हुई है. 10 मार्च, 2015 को एक बार फिर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहले देश में ग़रीबी से संबंधित आंकड़े योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते थे. योजना आयोग यह डाटा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) से प्राप्त करता था.

हैरानी की बात यह है कि नजमा हेपतुल्लाह को मालूम नहीं है कि भारत में ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है और वह केवल विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को पैसा बांटने में लगी हुई हैं. 14 अगस्त, 2014 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए नजमा हेपतुल्लाह ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है और इस सिलसिले में सरकार के अन्य मंत्रालयों से उन्हें ऐसी कोई संख्या अभी तक हासिल नहीं हुई है. 10 मार्च, 2015 को एक बार फिर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहले देश में ग़रीबी से संबंधित आंकड़े योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते थे.

मुख्तार अब्बास नक़वी ने राज्यसभा को यह भी बताया कि एनएसओ ने धार्मिक आधार पर आंकड़े एकत्र नहीं किए, हालांकि पहले वह ऐसा करता था. यही कारण है कि योजना आयोग के पास ग़रीबी से संबंधित 2011–12 के जो आंकड़े हैं, उनमें मुसलमानों की कोई अलग से संख्या नहीं बताई गई है. लेकिन, मुख्तार अब्बास नक़वी को यह जवाब भी देना चाहिए कि अगर सच्चर कमेटी देश के मुसलमानों में ग़रीबी की स्थिति का पता लगा सकती है, तो फिर मोदी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उल्लेखनीय है कि 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में सच्चर कमेटी ने बताया था कि वर्ष 2004–05 में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले 38.4 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 26.9 प्रतिशत मुसलमान ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे थे. स्वयं मुख्तार अब्बास नक़वी ने 10 मार्च, 2015 को राज्यसभा में उक्त सवाल का जवाब देते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ज़िक्र किया था.

मुख्तार अब्बास नक़वी ने 20 मार्च, 2015 को राज्यसभा में एक और सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में कुल 98 स्थायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बक़ौल मुख्तार अब्बास नक़वी, इस समय मंत्रालय में केवल 66 अधिकारी–कर्मचारी ही कार्यरत हैं. ऐसी स्थिति में हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित काम कितनी तेज़ी से अंजाम पा रहे होंगे? सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के उक्त रिक्त पद कब भरेगी? मोदी सरकार को लेकर मुसलमानों की चिंता अभी तक दूर न होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अल्पसंख्यक मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में इस समय एक भी मुस्लिम अधिकारी मौजूद नहीं है. इससे मुसलमानों के इस मत को बल मिलता है कि अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ़ नहीं है.

अब बात करते हैं मुसलमानों के साथ देश में होने वाले भेदभाव की. भारत का संविधान भले ही धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति न देता हो, लेकिन आज़ादी के 67 वर्षों से अधिक समय गुज़र जाने के बावजूद आज भी जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदवभाव हो रहा है. हाल में मुंबई के ज़ीशान को मुसलमान होने के कारण हरि कृष्णा नामक कंपनी में नौकरी न मिलना इसका ताजा उदाहरण है. इस तरह के भेदभाव को मद्देनज़र रखते हुए सच्चर कमेटी ने समान अवसर आयोग गठित करने की सिफ़ारिश की थी, ताकि अल्पसंख्यकों, विशेषत: मुसलमानों के साथ अगर धार्मिक आधार पर कहीं भेदभाव होता है कि तो यह आयोग उस पूरे मामले की जांच–पड़ताल कर सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सके. मोदी सरकार सच्चर कमेटी की इस अनुशंसा पर क्या अमल कर रही है, इसका एक लिखित जवाब देते हुए नजमा हेपतुल्लाह ने पिछले वर्ष 22 जुलाई को राज्यसभा को बताया था कि समान अवसर आयोग (ईओसी) की रूपरेखा क्या होगी और वह काम कैसे करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए पिछली यूपीए सरकार ने विशेषज्ञों का एक समूह बनाया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन एवं अमेरिका जैसे देशों में मौजूद इस तरह के मॉडल का विवरण सहित अध्ययन किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी. फिर पिछली यूपीए सरकार ने ही संबंधित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, मंत्रियों के समूह की अनुशंसाओं और विचार–विमर्श के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) गठित करने के लिए ईओसी बिल–2013 का मसौदा तैयार कर लिया था, ताकि उसे संसद में पेश किया जा सके, लेकिन उसी समय 2014 के आम चुनाव आ गए, जिसके बाद केंद्र में नई सरकार बन गई. नजमा हेपतुल्लाह ने राज्यसभा को बताया था कि उनकी सरकार अब संबंधित राजनेताओं से ईओसी बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक बार फिर मंज़ूरी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, ताकि समान अवसर आयोग गठित करने के लिए इस बिल को संसद में पेश किया जा सके. दुर्भाग्य है कि जुलाई, 2014 के बाद संसद के दो सत्र हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार द्वारा ईओसी बिल अब तक संसद में पेश नहीं किया जा सका है और न यह मालूम है कि कब तक इस पर आख़िरी अमल मुमकिन हो सकेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

सरकार को जानकारी है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी और कुशलता से कार्य कर रही है. एक पार्टी के रूप में भाजपा ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकती. दिल्ली भाजपा की मजबूत पकड़ में थी. लोकसभा में भारी जीत के बाद भी दिल्ली को खोना, वह भी तब, जब स्वयं प्रधानमंत्री ने छह रैलियां संबोधित कीं, भाजपा के चेहरे पर एक तमाचे की तरह था. किरण बेदी को प्रोजेक्ट करना दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक झटके जैसा था. बेदी को उन केजरीवाल के मुक़ाबले लाया गया था, जिन्होंने कहा था कि वह पुराना सिस्टम साफ़ करके प्रशासन के नए प्रतिमान देंगे. फिर बेदी का एक संदिग्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड रहा है. मैं यह विश्वास करने को तैयार नहीं, फिर भी मानता हूं कि केंद्र सरकार को यह सूचना है कि केजरीवाल के नए प्रशासनिक प्रतिमान सफल हो सकते हैं.

आप से किसे डर लग रहा है

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फरवरी में 67 सीटों के साथ निर्वाचित होने वाली दिल्ली सरकार को सामान्य ढंग से सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिये केंद्र सरकार पुलिस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काबिज है. दरअसल, तकनीकी रूप से एलजी कुछेक यानी डीडीए चेयरमैन की नियुक्ति जैसे काम करता है. इस सबके अलावा अगर वह कुछ और अधिक करता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि वह मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश कर रहा है. एक ऐसा मुख्यमंत्री, जो केंद्र सरकार की पार्टी से संबंध नहीं रखता है और केंद्र सरकार उसे सफल होते देखना पसंद नहीं करेगी. हास्यास्पद बात यह है कि मीडिया बिना किसी विश्लेषण के यह रिपोर्टिंग कर रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है. वह केजरीवाल का मज़ाक यह कहकर उड़ा रहा है कि उनकी सरकार ने सौ दिनों में क्या काम किए? सवाल यह है कि केजरीवाल को क्या करना चाहिए था? उन्होंने वादा किया था कि बिजली और पानी के शुल्क कम करेंगे. कम भी किया. कोई अन्य सरकार ऐसी कुशलता के साथ काम नहीं कर सकी है.

मैंने केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट नहीं दिया. मैं दिल्ली का नागरिक भी नहीं हूं, दिल्ली का मतदाता नहीं हूं और न मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता है. लेकिन, एक नई पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है, उसे काम करने का मौक़ा मिलना चाहिए. वह काम नहीं करेगी, तो जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी. लेकिन, केंद्र सरकार की घबराहट, प्रधानमंत्री या गृहमंत्री, एलजी के माध्यम से जो कर रहे हैं, वह सब एक अलग कहानी कहती है. सरकार को जानकारी है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी और कुशलता से कार्य कर रही है. एक पार्टी के रूप में भाजपा ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकती. दिल्ली भाजपा की मजबूत पकड़ में थी. लोकसभा में भारी जीत के बाद भी दिल्ली को खोना, वह भी तब, जब स्वयं प्रधानमंत्री ने छह रैलियां संबोधित कीं, भाजपा के चेहरे पर एक तमाचे की तरह था. किरण बेदी को प्रोजेक्ट करना दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक झटके जैसा था. बेदी को उन केजरीवाल के मुक़ाबले लाया गया था, जिन्होंने कहा था कि वह पुराना सिस्टम साफ़ करके प्रशासन के नए प्रतिमान देंगे. फिर बेदी का एक संदिग्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड रहा है. मैं यह विश्वास करने को तैयार नहीं, फिर भी मानता हूं कि केंद्र सरकार को यह सूचना है कि केजरीवाल के नए प्रशासनिक प्रतिमान सफल हो सकते हैं. जाहिर है, ऐसा होता है, तो यह कांग्रेस और भाजपा दोनों के हित में नहीं होगा. इस वजह से आम आदमी पार्टी को कमतर करने की इस प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ है.

मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और दोनों पक्षों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर स्टे देने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने चतुराई से काम किया. वह समझता है कि मामला क्या है. सुप्रीम कोर्ट दो शक्तियों के बीच के अंतर को समझता है. नजीब जंग के पास दो अधिकार हैं, एक बाहैसियत एलजी और एक राज्यपाल के रूप में. आप चुनाव के लिए कॉल कर सकते हैं, सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, आदि. लेकिन यह उस वक्त होता है, जब राज्य का शासन तंत्र बिल्कुल विफल हो जाता है और सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चलती है. लेकिन यहां मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ही व्यक्ति क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की नियुक्ति कर रहा है. यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति और दूसरे राज्यों के गवर्नर के पास भी है, लेकिन ये केवल तकनीकी बातें हैं. यह सब आम तौर पर मंत्रि परिषद की सलाह से ही होता है. मैं नहीं समझता कि गृह मंत्रालय, जाहिर है कि राजनीतिक और संदिग्ध कारणों से, एक सर्कुलर जारी करता है, जिसे मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा. केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का केवल एक साल पूरा किया है, उसके पास चार साल का कार्यकाल और है. लेकिन पता नहीं, वह ऐसे छोटे मामलों में क्यों उलझ रही है? उसे अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए.

राष्ट्रीय परिदृश्य पर आएं, तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना पद्धति बदल दी गई है. ऐसा करने पर वे एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि देश ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है. इसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि यह वृद्धि 7.4 प्रतिशत है, तो पिछले वर्ष की वृद्धि का नई प्रणाली के अंतर्गत आकलन करने पर वह 6.9 प्रतिशत होगी. इस आधार पर यूपीए सरकार के कार्यकाल का आख़िरी साल आर्थिक दृष्टि से खराब नहीं था. कोई यह नहीं कह सकता है कि वह बहुत अच्छा था या बहुत खराब. इस तरह की पैंतरेबाजी से सरकार और अर्थव्यवस्था दोनों को फ़ायदा नहीं होगा. ज़रूरत इस बात की है कि सरकार अपना ध्यान नीतिगत निर्णयों पर केंद्रित करे. मुझे नहीं लगता है कि रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच तालमेल है. रिजर्व बैंक को लगता है कि ब्याज दरों में अभी कमी करना जल्दबाजी है और जोखिम भरा है, लेकिन वित्त मंत्रालय चाहता है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करे. प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को अपना मुख्य अभियान बनाया है. आप तब तक देश में निर्माण नहीं कर सकते हैं, जब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नहीं होगा.

अभी लोग केवल शेयर बाज़ार अथवा वित्त बाज़ार में पैसा लगाने के लिए भेज रहे हैं, जहां उन्हें आठ प्रतिशत का लाभ होगा. वे यहां पैसा इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि यहां ब्याज की दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है और वे अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं. यदि आप चाहते हैं कि लोग अपना पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं, तो बहुत-से क़दम उठाने की आवश्यकता है. दलाली वाले व्यापार को कम आकर्षक बनाना चाहिए. व्यापार करने में आसानी की बात वित्त मंत्री हमेशा करते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने अब तक एक धारा या क़ानून में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए हैं. वास्तव में आयकर अधिकारी वित्त मंत्रालय को हास्यास्पद आयकर रिटर्न फॉर्म लाकर शर्मिंदा कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इसमें फिर से सुधार करने का वादा किया है. मुझे लगता है कि यदि वित्त मंत्री क़ानूनों को आसान बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम-1973 जैसे क़ानूनों को बदलना चाहते हैं, जो कि कठोर हैं और जिनका इस्तेमाल नागरिकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को परेशान करने और पैसे बनाने के लिए नौकरशाह करते रहे हैं. यदि इन क़ानूनों का यही उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं. ये सभी क़ानून अजीब हैं और नौकरशाही की मदद के लिए हैं. एक भी नियम इतना पारदर्शी नहीं बनाया गया कि उद्यमियों को नौकरशाहों के पास न जाना पड़े. मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक व्यापार करने में आसानी नहीं होगी. एशियाई देशों में विदेशी मुद्रा आएगी, श्रीलंका में आएगी, फिलीपींस में आएगी, हमारे पड़ोसी देशों में आएगी, लेकिन यहां नहीं आएगी. मैं कह नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नौकरशाहों के संपर्क में हैं, लेकिन यह एक परीक्षा है, क्योंकि नौकरशाह उदारीकरण करते वक्त उस सीमा को नहीं लाघेंगे, जहां उनकी अहमियत कम हो जाए. वे कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी अहमियत कम हो.

प्रधानमंत्री पूर्व नौकरशाहों या उदारवाद की पैरवी करने वाले नौकरशाहों की एक टीम गठित करें और उसे ये मामले सौंप दें. अन्यथा मुझे लगता है कि क़ानूनों में संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से कुछ हासिल नहीं होगा. विदेशियों का नज़रिया टाइम्स और इकोनॉमिस्ट मैग्जीन में प्रकाशित लेखों से साबित होता है कि नरेंद्र मोदी मॉडल दे सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं. सुधार बिल्कुल अलग चीज है, जिसके लिए एक अलग सोच की आवश्यकता होती है. वह आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी योजनाएं लाना चाहते हैं. लेकिन, दूसरा पहलू क़ानूनों में बदलाव की पहल है, न केवल विदेशी उद्यमियों के लिए, बल्कि घरेलू उद्यमियों के लिए भी. इस पहलू पर अभी तक काम नहीं किया गया है. हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार अपने दूसरे साल में इस दिशा में कुछ काम करेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

कुख्यात डाकू मुस्तकीम कैसे मारा गया

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

पांच मार्च, 1981 को कानपुर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में डाकू मुस्तकीम और उसके साथ जा रहे एक पूर्णतया निर्दोष युवक को पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की पूरी सुविधा के बावजूद मार डाला, उससे तो यही लग रहा था कि उन दिनों हम एक जंगलराज में रह रहे थे. मुस्तकीम के पास उस समय ढेर सारा रुपया था, जिसे जब्त तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस खाते में नहीं दिखाया गया. हमारी पुलिस व्यवस्था के नए चेहरे और डाकू स्थिति के एक नए आयाम का यह रोमांचकारी वृतांत है. जब मैं यह रिपोर्ट लिख रहा था, जिसमें मुस्तकीम की मौत की वास्तविकता दिखाई दे रही थी, तो मैं यह ख़तरा ज़रूर उठा रहा था कि कहीं डाकू को मैं हीरो जैसा तो नहीं बना रहा हूं? पर इस सच्चाई को न लिखना डेरापुर, पुखरायां, कालपी तथा रूरा क्षेत्र के उन हज़ारों आदमियों के साथ मज़ाक होता, जिन्होंने इस संपूर्ण घटना को अपनी आंखों से देखा था. आज भी इस रिपोर्ट को पढ़कर यह अवश्य लगता है कि क़ानून की रक्षा करने वाले और क़ानून को तोड़ने वालों के बीच आख़िर अंतर है किस बात का?

मुस्तकीम मारा गया. मुस्तकीम ज़िंदा है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीहड़ों में जिसका राज चलता है, उस दस्यु सम्राट मलखान मिरधा के ठीक बाद जिसकी जगह थी, उस मुस्तकीम की मृत्यु सचमुच हो चुकी है या नहीं, इस बहस को फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़िम्मे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुस्तकीम पर घोषित इनाम की रकम, बीस हज़ार रुपये, उसे ही देनी है. यहां जो लिखा जाने वाला है, वह सच्चाई का एक और चेहरा है, जो बताता है कि हमारी समाज-व्यवस्था एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है, जहां क़ानून और संविधान का कोई मतलब नहीं है. जहां पुलिस और प्रशासन की कार्य-पद्धति में कोई मूल्य और आदर्श नहीं बचे हैं. अब भयानक और ख़तरनाक माने जाने वाले डाकुओं के जीवन में भले ही कुछ सिद्धांत दिखाई पड़ जाएं, पर ग़ैर-ज़रूरी ढंग से और नीचतापूर्वक हत्या कर देने वाले हमारे कथित रक्षकों के जीवन में कोई आचार-संहिता नहीं है. मुस्तकीम और उसकी मौत की वास्तविकता लिखने में यह ख़तरा ज़रूर है कि वह डाकू कहीं हीरो जैसा न दिखाई देने लगे. लेकिन इस सच्चाई को न लिखना डेरापुर, पुखरायां, कालपी तथा रूरा क्षेत्र के उन हज़ारों आदमियों के साथ मज़ाक करना होगा, जिन्होंने इस संपूर्ण घटना को अपनी आंखों से देखा है.

स्त्री डकैत फूलन देवी ने बेहमई में जो कुछ किया, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया, जिसका जायज नतीजा होना चाहिए था डाकुओं की बड़े पैमाने पर धर-पकड़, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, वह यह है कि डाकू के नाम पर जिस किसी को मार दो और इस तरह मृत डाकुओं की सूची बढ़ाते रहो. पुलिस का कहना है कि चार मार्च की सुबह दो पुलिस दल गश्त से लौट रहे थे, तभी उनकी भेंट दो ऐसे आदमियों से हुई, जो उन्हें देखकर भागने लगे. पुलिस ने रोका, तो उन्होंने फायर किए. पुलिस ने भी फायर से जवाब दिया और उन्हें मार गिराया. बाद में पता चला कि उनमें से एक मुस्तकीम था, उसके साथ के व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी. लेकिन, दूसरे दिन अख़बारों में छपा कि उप-पुलिस महानिरीक्षक ने पहले से ही सारी योजना बना रखी थी. अब झगड़ा लाजिमी था कि मुस्तकीम को मारने का श्रेय किसे है. बहरहाल, सच्चाई जो भी हो, पुलिस ने एक बड़ा काम किया था. लेकिन स्थानीय लोगों से बात करने पर जैसे-जैसे यथार्थ की परत-दर-परत खुलने लगी, वैसे-वैसे पुलिस का सारा छद्म स्पष्ट होता गया. पहली बात तो यही कि जिस जगह को पुलिस मुठभेड़ स्थल बता रही है, उसका भूगोल ऐसा है कि वहां केवल एक ही तरफ़ से गोली चल सकती है. मुस्तकीम के गांव दस्तमपुर में जिन तथ्यों का पता लगा, उसकी पुष्टि के लिए पांच व छह मार्च को अकबरपुर, रूरा, गुलुआपुर, पुखरायां, मिट्टी, राजपुर, चांदापुर तथा कालपी जाने, इन गांवों के सैकड़ों आदमियों से बातचीत करने तथा सब-इंस्पेक्टर हरिराम पाल का, जिन्होंने मुस्तकीम को पकड़ने और मारने का दावा किया है, वक्तव्य सुनने के बाद पूरी स्थिति आईने की तरह स्पष्ट हो गई.

इन दिनों चंबल के डाकुओं में एक सहयोग वृत्ति-सी पैदा हुई है. छविराम, पोथी को छोड़कर इन सबमें आपसी समन्वय था. मलखान इन सबका समन्वयक है तथा उसका आदेश सभी मानते हैं. जमुना, चंबल, कुआंरी, पहुंज व सिंध का जालौन, उरई, दतिया, कालपी व कानपुर क्षेत्र मुस्तकीम का कार्यक्षेत्र था और राम औतार, मान सिंह, फूलन, रघुनाथ व बलवान गड़रिया उसी के निर्देशन में काम करते थे. बेहमई में फूलन, मान सिंह, राम औतार व भागीरथ द्वारा किए गए नरसंहार के बाद पुलिस का दबाव डाकुओं पर काफी बढ़ गया था. वस्तुत: मुस्तकीम इस प्रकार की हत्याओं का विरोधी था और उसकी ग़ैर जानकारी में ही यह कांड हुआ. ख़बर है कि इसके तत्काल बाद उसने फूलन को बहुत डांटा. भेंट होने पर मलखान ने मुस्तकीम और फूलन दोनों को डांटा. मलखान से मिलकर जब मुस्तकीम लौटा, तो उसे समाचार मिला कि मलखान घेर लिया गया है. उसने अपनी दाढ़ी बनवाई तथा पुलिस उप-अधीक्षक की वर्दी पहन कर मोटर साइकिल से सिपाही की वर्दी पहने एक डाकू को लेकर घेराबंदी वाली जगह पर पहुंच गया. वहां उसने एक तरफ़ की पीएसी के सिपाहियों को आदेश दिया कि मलखान दूसरी तरफ़ से निकला जा रहा है, अत: वे सब वहां जाएं. सिपाही उधर गए और मलखान इधर से निकल गया.

इसके बाद मुस्तकीम अपने गिरोह की तरफ़ नहीं गया. कुछ दिन वह आगरा रुक कर कानपुर आ गया और एक सप्ताह वहीं रहा. वहां से मुस्तकीम ने बंबई जाने की योजना बनाई, लेकिन इसके पहले वह चाहता था कि एक बार अपने बड़े भाई से मिल लेता, जो दस्तमपुर गांव में, जहां उसकी ससुराल है, मेहनत-मज़दूरी करके दिन काट रहा है. तीन मार्च की रात मुस्तकीम मोटर साइकिल से कानपुर से अकबरपुर आया तथा सुबह चार बजे तक वहीं रुका रहा. वहां उसने अपने एक रिश्ते के भाई इमामुद्दीन को बुलवाया. इमामुद्दीन भी अकबरपुर के कसाई मुहल्ले में अपनी ससुराल में रह रहा था तथा नमक के बदले लोहा-टीन खरीदने की फेरी लगाता था.■

क्रमश:

स्त्री डकैत फूलन देवी ने बेहमई में जो कुछ किया, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया, जिसका जायज नतीजा होना चाहिए था डाकुओं की बड़े पैमाने पर धर-पकड़, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, वह यह है कि डाकू के नाम पर जिस किसी को मार दो और इस तरह मृत डाकुओं की सूची बढ़ाते रहो. पुलिस का कहना है कि चार मार्च की सुबह दो पुलिस दल गश्त से लौट रहे थे, तभी उनकी भेंट दो ऐसे आदमियों से हुई, जो उन्हें देखकर भागने लगे. पुलिस ने रोका, तो उन्होंने फायर किए. पुलिस ने भी फायर से जवाब दिया और उन्हें मार गिराया. बाद में पता चला कि उनमें से एक मुस्तकीम था, उसके साथ के व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी. लेकिन, दूसरे दिन अख़बारों में छपा कि उप-पुलिस महानिरीक्षक ने पहले से ही सारी योजना बना रखी थी.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र

सरकार भी एक बड़ी खरीददार है. उसके पास सेना है, पुलिस है, बहुत सारी जगहों में वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती है, ये सारा सामान वह बिचौलियों या दलालों से क्यों खरीदे? वह क्यों नहीं अपनी प्राथमिकता ब्लॉक में लगने वाले इन उद्योगों को अपना मुख्य खरीद का साधन बनाए और उस ब्लॉक में जितनी तरह की फसलें होती हैं, उन फसलों का फिनिश प्रोडक्ट उन्हीं ब्लॉक में छोटे उद्योगों के माध्यम से सरकार के पास जाए? एक तो इससे किसानों के उत्पादन की खरीद की गारंटी मिल जाएगी और दूसरा यह कि बाज़ार में भी अच्छा माल जाने लगेगा.

प्रधानमंत्री जी, एक वर्ष बीत गया और जिस तेज़ी से आपने पिछले वर्ष देश के बढ़ने के लिए जो खाका तैयार किया, उससे ज़्यादा हमारे मीडिया के साथी उस नक्शे को प्रचारित करने में लगे हैं. मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं और मेरा यह भी मानना है कि आप में वह क्षमता है कि आप अपनी दिशा का सही निर्धारण कुतुबनुमा के ज़रिये या कंपास के ज़रिये हमेशा करते रहेंगे. कुतुबनुमा का मतलब कि आप यह कसौटी बनाएंगे कि आपकी योजनाओं का फ़ायदा आपकी नज़र में सबसे आख़िरी ग़रीब आदमी को कितना हो रहा है.

लेकिन, मुझे एक बात समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है. पिछले एक वर्ष में जो भी नक्शा आपने देश के सामने रखा और जिसे आप 16 तारीख से लेकर अब तक बताते आ रहे हैं, अपने द्वारा किए हुए कामों की गिनती गिनाते आ रहे हैं, वे सारे काम देश के लोगों की जिंदगी में बदलाव के साथ कहां जुड़ते हैं? आपने जो किया, वह सब करना आवश्यक था, पर ये सब थाली में चटनी, नमक और सलाद की तरह से हैं. थाली में मुख्य भोजन कहां है? मैं यह सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि पिछले सालों में पहली बार ऐसा लगा था कि आप कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, जिससे इस देश के 80 प्रतिशत लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी-सी आशा की किरण जागेगी. आपको वोट भी उन 80 प्रतिशत लोगों ने ही दिया है, जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं.

प्रधानमंत्री जी, आज जिस तरह से शंखों का शोर आपके पास हो रहा है, आपको मेरी बात शायद नहीं सुनाई देगी, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं ये बातें आपसे कहूं और आपसे यह आशा भी करूं कि आप वक्त रहते चेतेंगे और इस बुनियादी दिशा की तरफ़ अपनी सरकार को ले जाने की बात करेंगे. अगर आप बुनियादी दिशा की तरफ़ सरकार को ले जाने की बात नहीं करते, तो यह देश बहुत सारे लोगों से तो निराश हो चुका है. अगर आपसे भी निराश हुआ, तो फिर किसी के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा.

प्रधानमंत्री जी, जब मैं यह कहता हूं कि देश के लोगों की ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर बदलाव या उनकी थाली का मुख्य भोजन, तो मैं इस देश के उन लोगों की बात करता हूं, जिनकी ज़िंदगी इस देश के सबसे बड़े उद्योग खेती के ऊपर आधारित है और यह खेती शब्द सिर्फ़ किसान से जुड़ा नहीं है. खेती शब्द इस देश के नौजवानों से जुड़ा है, इस देश की शिक्षा से जुड़ा है, इस देश के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस देश के विकास से जुड़ा है, इस देश के संचार से जुड़ा है. इसलिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा उत्पादन का यंत्र खेत, वह भी गांव में है और उससे जुड़े हुए नौजवान, वे भी गांव में हैं. उनकी सबसे बड़ी आशा थी कि उनकी ज़िंदगी के सामने जो अंधेरे की दीवार आ गई है, वह अंधेरे की दीवार आपकी कोशिशों से थोड़ी साफ़ होगी और उन्हें रास्ता मिलेगा.

लेकिन, पिछले दो बजट में इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है. क्या खेती को उत्पादक बनाने का कोई तरीका बजट में दिखाई दिया? खेती की भूमि की मिट्टी का लेबोरेट्री में टेस्ट आवश्यक है, लेकिन सर्वप्रमुख नहीं है. प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रमुख है कि खेती में लगने वाली चीजें, वह चाहे पानी हो, बीज हो, खाद हो और फिर बिजली हो, सिचाई हो और कटाई के बाद फसलों को बाज़ार में ले जाने लायक बनाने का मसला हो, ये सारी चीजें किसान को देने की कोई कोशिश मुझे किसी बजट में दिखाई नहीं दी. दूसरा, खेती से उपजे हुए प्रोडक्ट को, उत्पादन को बिचौलियों से बचाने की कोई कोशिश मुझे किसी बजट में दिखाई नहीं दी. सबसे बड़ी चीज, जो खेती से पैदा होने वाली उपज है, क्या उसका फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने के कारखानों की शृंखला देश के हर ब्लॉक में नहीं लगाई जा सकती? क्या ऐसे उद्योग नहीं लगाए जा सकते, जिनमें नौजवानों को शामिल किया जाए और वहां से फिनिश प्रोडक्ट निकल कर देश के बाज़ारों में जाए?

सरकार भी एक बड़ी खरीददार है. उसके पास सेना है, पुलिस है, बहुत सारी जगहों में वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती है, ये सारा सामान वह बिचौलियों या दलालों से क्यों खरीदे? वह क्यों नहीं अपनी प्राथमिकता ब्लॉक में लगने वाले इन उद्योगों को अपना मुख्य खरीद का साधन बनाए और उस ब्लॉक में जितनी तरह की फसलें होती हैं, उन फसलों का फिनिश प्रोडक्ट उन्हीं ब्लॉक में छोटे उद्योगों के माध्यम से सरकार के पास जाए? एक तो इससे किसानों के उत्पादन की खरीद की गारंटी मिल जाएगी और दूसरा यह कि बाज़ार में भी अच्छा माल जाने लगेगा.

प्रधानमंत्री जी, यह सच है कि यह रास्ता बड़े कॉरपोरेट्स को नहीं सुहाएगा, लेकिन इस रास्ते से देश का सबसे बड़ा धन नौजवान और खेती उत्पादक बनने की दिशा में जाएंगे और तब हर गांव में सड़क भी पहुंचेगी, संचार के साधन भी पहुंचेंगे और आप जिस चीज का सपना देखते हैं सोलर पॉवर का, वह भी हर ब्लॉक में तेजी के साथ विकसित (डेवलप) होगा. बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जो विभिन्न ब्लॉकों में 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 25 मेगावाट का प्लांट लगा सकती हैं और लोग उनसे बिजली लेकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं.

यह तरीका पूरी तरह से बड़े उद्योगों के ख़िलाफ़ भी नहीं है, कॉरपोरेट्स विरोधी भी नहीं है. सारी दुनिया का बाज़ार हमारे कॉरपोरेट्स के लिए खुला हुआ है और कॉरपोरेट्स इन्हीं छोटी-छोटी यूनिट्स से भारतीय कृषि उत्पादन के उत्पाद को खरीद कर दुनिया के बाज़ार में आसानी के साथ बेच सकते हैं. इससे भारतीय उत्पादन को दुनिया के बाज़ार में जगह मिलेगी, देश के बाज़ार में भी जगह मिलेगी और क़ीमतों को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा भी होगी. यह देश के किसानों के हित में है, देश की खेती के हित में है और देश के नौजवानों के हित में है. इससे एक दूसरा बड़ा लाभ यह होगा कि कृषि के ऊपर आधारित एक बड़ी संख्या उनकी है, जिनके पास खेती है ही नहीं, जिन्हें हम खेतिहर मज़दूर कहते हैं, उन्हें हम ब्लॉक लेवल के ऊपर उन सारे उद्योगों में खपा सकते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं. इतना ही नहीं, उद्योगों में खपाने के साथ आप उन्हें पशु धन के ऊपर आधारित उत्पादनों को बढ़ाने में आसानी के साथ लगा सकते हैं. और, इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश में बेरोज़गारी से लड़ने का एक हथियार देशवासियों को मिल जाएगा, पर इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है और उन तरीकों से लड़ने की ज़रूरत है, जो देश में बेरोज़गारी बढ़ाने की बात करते हैं.

इसीलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि थाली में मुख्य भोजन की जगह हमने चटनी बना दी, हमने सलाद काट दिया. हमने कुछ खीरा, कुछ प्याज, कुछ टमाटर रख दिया. इसको हम मुख्य भोजन बताकर लोगों को खिलाने की बात कर रहे हैं. इस देश के लोग पिछले 60-65 वर्षों के सताए हुए हैं. उन सताए हुए लोगों को क्या आप जिस अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ़ एक क़दम बढ़ाने में सहयोग नहीं दे सकते? मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं. आपके पास इस देश में इन चीजों को लागू करने में आने वाली अड़चनों के बारे में सोचने और उन्हें दूर हटाने का वक्त ही नहीं है. मुझे लगता है कि आपके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं, जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं.

मैं आपको एक छोटा सुझाव देना चाहता हूं. कृपया अपने मंत्रिमंडल के राजनीतिक साथियों को टारगेट दीजिए, उसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर डालिए और उन्हें वक्त दीजिए. क्रमबद्ध ढंग से उनके फ़ैसलों को पूर्ण करने का अधिकार दीजिए. उसके बाद या तो उन्हें ईनाम दीजिए या फिर उन्हें विनम्रता से हट जाने के लिए कहिए, ताकि दूसरे लोग आकर उस टारगेट को पूरा कर सकें. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, आपको यह भी देखना होगा कि जिसने अपना टारगेट पूरा किया है क्या उसे आपकी तरफ़ से तवज्जो मिल रही है? क्या आप उसे शाबाशी दे रहे हैं या आप उन्हें शाबाशी दे रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं, और जो सिर्फ़ आपकी परिक्रमा कर रहे हैं?

प्रधानमंत्री जी, आज जिस तरह से शंखों का शोर आपके पास हो रहा है, आपको मेरी बात शायद नहीं सुनाई देगी, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं ये बातें आपसे कहूं और आपसे यह आशा भी करूं कि आप वक्त रहते चेतेंगे और इस बुनियादी दिशा की तरफ़ अपनी सरकार को ले जाने की बात करेंगे. अगर आप बुनियादी दिशा की तरफ़ सरकार को ले जाने की बात नहीं करते, तो यह देश बहुत सारे लोगों से तो निराश हो चुका है. अगर आपसे भी निराश हुआ, तो फिर किसी के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप इतिहास में दर्ज होने वाले एक ऐसे विलक्षण प्रधानमंत्री माने जाएंगे, जो सामान्य जीवन से उठा, जो सर्वोच्च पद पर बैठा और जिसने इस देश के बदलाव के लिए कमाल का काम किया. मेरा ख्याल है, मुझे आपके उत्तर में मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का कुछ सार्थक जवाब मिलेगा. मैं प्रतीक्षारत हूं.■

editor@chauthiduniya.com

अकेला अरविंद पार्टी (आप)

हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सरेआम झगड़ते देखा. ये झगड़े तब तक होते रहे, जब तक यह स्थापित नहीं हो गया कि इस पार्टी का केवल एक ही नेता है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल. बाकी लोग उनके बराबर में खड़े होने के योग्य नहीं हैं. एक ऐसा आंदोलन, जो एक समान सोच रखने वाले दोस्तों के एक समूह ने शुरू किया था, अब अकेला अरविंद पार्टी (आप) बन गया है. अरविंद केजरीवाल ने उसी मीडिया से झगड़े मोल लिए, जिसके सहयोग से उन्हें चुनाव में कामयाबी मिली.

मेघनाद देसाई

एरिक फ्रोम्म ने सामाजिक आंदोलनों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था. उन्होंने फासीवाद की वजह से स्वतंत्रता को लेकर लोगों के भय का विश्लेषण किया. लोगों ने खुद सोचने के बजाय आदेश पालन को पसंद किया. ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, जो तानाशाही पसंद करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र चीज़ों को जटिल बना देता है और फ़ैसला लेने की प्रक्रिया को मुश्किल. लेकिन क्या आपने जो सत्ता हासिल की है, उसके इस्तेमाल से आपको डर लगता है? अरविंद केजरीवाल 49 दिनों की सत्ता में आए थे. उनकी अल्पमत सरकार को कांग्रेस समर्थन दे रही थी. उस समय केजरीवाल मुख्यमंत्री के बजाय एक छात्र आंदोलनकारी की तरह व्यवहार कर रहे थे. इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है. उनकी पार्टी को दिल्ली की 70 में से 67 सीटें मिली हैं. वह जिस तरह के नीति आधारित फ़ैसले लेने चाहते हैं, ले सकते हैं. वह अपने चुनावी वादे पूरे कर सकते हैं. लेकिन, वह शासन चलाने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह की रणनीति अपना रहे हैं.

हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सरेआम झगड़ते देखा. ये झगड़े तब तक होते रहे, जब तक यह स्थापित नहीं हो गया कि इस पार्टी का केवल एक ही नेता है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल. बाकी लोग उनके बराबर में खड़े होने के योग्य नहीं हैं. एक ऐसा आंदोलन, जो एक समान सोच रखने वाले दोस्तों के एक समूह ने शुरू किया था, अब अकेला अरविंद पार्टी (आप) बन गया है. अरविंद केजरीवाल ने उसी मीडिया से झगड़े मोल लिए, जिसके सहयोग से उन्हें चुनाव में कामयाबी मिली. अब महज़ उनका नाम लेने मात्र पर वह मीडिया पर मानहानि का मुक़दमा दायर करना चाहते हैं, आलोचना तो दूर की बात है. इतने बड़े नेता के ऊपर उंगली उठाने की मीडिया को हिम्मत कैसे हुई! अभी तक उनका सामान्य अपरिपक्व व्यवहार सामने आया है. उन्होंने अभी तक उन लोगों से झगड़े मोल लिए हैं, जिन्हें वह अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं. अब उनका हठ यह है कि उप-राज्यपाल उनके लिए ग़ैर-ज़रूरी हैं. केजरीवाल अपने राज्य के एकमात्र नेता बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए हताशा और क्रोध की बात यह है कि दिल्ली केवल एक केंद्र शासित राज्य है.

अब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हालात को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई चारा न बचे. उसके बाद ज़ाहिर है, केजरीवाल अपने आपको पीड़ित दिखाना शुरू कर देंगे. दरअसल, इस बार उनका कार्यकाल 49 दिनों से कुछ ज़्यादा होगा और उसके बाद अगला चुनाव वह इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि पूरी दुनिया उनके ख़िलाफ़ है. इसके लिए वह बहुत से अज़ीबोग़रीब तर्क गढ़ते हैं. दरअसल, एक कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाई केजरीवाल का पसंदीदा खेल है. इसकी शुरुआत उन्होंने अन्ना हजारे के साथ की और वह आज भी एक छात्र आंदोलनकारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं. वह जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने धरना दिया था. जब जनता अपनी समस्याएं सामने लाती है, तो उनके हल के लिए वह उसे धरना देने का मशविरा देते हैं. अपनी सरकार के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर वह खुद भी एक तरह के धरने पर हैं. त्रासदी यह है कि हाल के दिनों में एक लोकतांत्रिक पार्टी के जन्म की आशा दिखाई दी थी, लेकिन वह आशा अब एक व्यक्ति की सनक बन गई है. राजनीतिक मोर्चे पर एक खालीपन है. ऐसा लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की यादव यूनियन की पार्टियां मृतप्राय: हो गई हैं. राहुल गांधी के भारत एक खोज के बावजूद कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान नहीं हो सकता. सीताराम येचुरी चाहे जो कर लें, वामपंथ का आधार खिसक रहा है. एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भारत को एक विश्वसनीय विपक्षी पार्टी की आवश्यकता है, जो भाजपा का मुकाबला कर सके. बावजूद इसके, आम आदमी पार्टी के बर्ताव की वजह से उसे यह मुकाम नहीं दिया जा सकता है. आप से लोगों को आशा थी कि वह दिल्ली की समस्याएं हल कर लेगी. मसलन प्रदूषण, जिसकी वजह से जन-स्वास्थ्य और स्कूली बच्चों एवं बुजुर्गों का जीवन ख़तरे में पड़ गया है. आप का अर्थ है ग़रीब समर्थक, लेकिन बिना किसी आर्थिक रणनीति के. बहुत जल्द उन्हें (अरविंद केजरीवाल को) बजट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की तरह, जिसने पुनर्वितरण के नाम पर पश्चिम बंगाल को दिवालिया बना दिया, आप भी वही काम कर रही है.

अब जयललिता का व्यवहार. उन्होंने अदालत के फ़ैसले का सम्मान करते हुए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी और दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया. हम यह उम्मीद कर सकते थे कि इंदिरा गांधी ने सही आचरण का प्रमाण देते हुए आपातकाल न घोषित किया होता. तमिलनाडु देश के उन गिने-चुने राज्यों में से एक है, जो संपन्न है और अच्छा कल्याणकारी राज्य है. अब सवाल यह उठता है कि उत्तर भारत दक्षिण से आख़िर कब सबक लेगा?■

feedback@chauthiduniya.com

सेवा का भाव संवेदना के स्तर पर निर्भर करता है. 32 वर्ष पहले विदिशा रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरते समय एक महिला गिर गई और ट्रेन के चपेट में आने से उसका हाथ कट गया. इस घटना ने संवेदनशील लोगों की संवेदना को झकझोरा. ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाजसेवी मोहनबाबू अग्रवाल, रामेश्वर दयाल बंसल, नरेंद्र ताम्रकार, लालजी जैन, डॉ सुरेश गर्ग और खीमजी भाई ने मिल कर रेलवे स्टेशन पर जल सेवा शुरू की.

हीट स्ट्रोक से रहें सावधान

चौथी दुनिया ब्यूरो

गर्मी में अधिक शारीरिक गतिविधि के साथ अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी न मिले तो हीट क्रैम्प की समस्या हो सकती है. इस अवस्था में मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर पेट, हाथों और पैरों में दर्द होता है. ऐसा शरीर से पसीने के साथ सोडियम निकल जाने के कारण होता है.

हीट स्ट्रोक को आम बोलचाल की भाषा में लू लगना कहा जाता है. यह एक गंभीर शारीरिक अवस्था है, जिसमें शरीर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है और शरीर का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है. तापमान बढ़ कर 105 डिग्री या उससे भी अधिक हो सकता है. हीट स्ट्रोक में शरीर के तापमान का बढ़ना साधारण बुखार की स्थिति से भिन्न होता है. हीट स्ट्रोक की समस्या बेहद घातक सिद्ध हो सकती है. इसके कारण मस्तिष्क और शरीर के आंतरिक अंगों को क्षति पहुंच सकती है और सही उपचार न मिलने की स्थिति में रोगी को जान तक गंवानी पड़ सकती है.

हीट स्ट्रोक की शुरुआती अवस्थाएं : हीट स्ट्रोक में गंभीर स्थिति से पहले आमतौर पर कुछ शुरुआती अवस्थाएं होती हैं, जिनके लगातार बढ़ने के कारण स्थिति बिगड़ जाती है. इन्हें जान कर और समय रहते सही उपचार करके इस गंभीर स्थिति तक पहुंचने से बचा जा सकता है.

हीट क्रैम्प: गर्मी में अधिक शारीरिक गतिविधि के साथ अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी न मिले तो हीट क्रैम्प की समस्या हो सकती है. इस अवस्था में मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर पेट, हाथों और पैरों में दर्द होता है. ऐसा शरीर से पसीने के साथ सोडियम निकल जाने के कारण होता है. इसलिए कम सोडियम डाइट लेने वाले लोगों और दिल के रोगियों के इससे पीड़ित होने की आशंका ज्यादा होती है. समस्या के काबू में न आने पर अगली अवस्था यानी हीट इग्जॉस्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए इस स्थिति में भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें और कुछ घंटे बाहर न निकलें.

हीट इग्जॉस्शन: तेज गर्मी और डीहाइड्रेशन के कारण हीट इग्जॉस्शन की समस्या हो सकती है. कमजोरी, तेज पसीना, तेज प्यास, जी मिचलाना, सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द, चक्कर आना जैसे लक्षण हीट इग्जॉस्शन का इशारा करते हैं. समय पर उपचार न मिलने पर समस्या बिगड़ सकती है.

हीट स्ट्रोक के संकेत: तेज बुखार होता है, जो 104 डिग्री से ज्यादा रहता है. त्वचा में लालिमा, गर्माहट और खुश्की होती है. अत्यधिक घबराहट होती है. व्यवहार में बदलाव और चिड़चिड़ापन आ जाता है. पसीना कम आता है. सांस लेने में कठिनाई होती है.

कारण : अल्कोहल का सेवन, हृदय रोग, गर्मी में अत्यधिक कपड़े पहनना, गर्म दिनों में शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन न करना, गर्मी में अत्यधिक व्यायाम, तेज धूप के समय फील्ड वर्क करना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं. अवसाद के इलाज के दौरान ली जाने वाली दवाएं भी इसके खतरे को बढ़ा देती हैं.

शुरुआती इलाज : रोगी को ठंडे स्थान पर ले जाएं. उसके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें या सीधे ठंडा पानी डालें. तापमान को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हवा दें. रोगी पेय लेने की स्थिति में है तो उसे ठंडे, शीतल पेय पिलाएं. रोगी की बगलों, गर्दन, पीठ आदि में बर्फ का पैक लगाएं.

क्या खाएं : खाने की ऐसी आदत बनाएं कि शरीर में पानी की कमी न रहे और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहे. पानी, फलों–सब्जियों के जूस, ठंडी शिकंजी, मट्ठा, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट जैसे तरल पदार्थों का सेवन करते रहें. तला–भुना, गरिष्ठ भोजन करने से बचें. सलाद, दही, फल, दाल आदि अधिक खाएं.

क्या है खतरा : हीट स्ट्रोक का खतरा किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग खासतौर पर हीट स्ट्रोक की रिस्क फैक्टर श्रेणी में आते हैं. इन्हें बचाव के लिए खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. बच्चे, वृद्ध, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, उच्च रक्तचाप, गुर्दे या दिल के रोगी, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले खिलाड़ी या मोटे लोग इसी श्रेणी के हैं.

घरेलू उपचार : धनिए को कुछ देर पानी में भिगो कर रखें. उसे अच्छी तरह मसल कर, छान कर उसमें थोड़ी चीनी मिला कर पीने से गर्मी के कारण होने वाली समस्याओं की आशंका कम हो जाती है. कच्चे आम को उबाल कर छान लें. इसमें चीनी, नमक और भुना जीरा मिला कर पेय बना कर पिएं. गर्मी से बचाव के लिए यह रामबाण है. ठंडे पानी में आलू बुखारे को मसल कर पीने से भी हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है. बेल के रस में चीनी मिला कर पिएं. शरीर को गर्मी की समस्या से राहत मिलेगी. मेथी की सूखी पत्तियों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इसे हाथ से मसल कर छान लें. इसमें थोड़ा शहद मिलाएं. थोड़ा–थोड़ा दो–दो घंटे के अंतराल में पिएं. प्याज हीट स्ट्रोक से शरीर की रक्षा करती है. प्याज, चीनी और जीरे को भून लें. इसे थोड़ा–थोड़ा नियमित रूप से खाएं, गर्मी से राहत मिलेगी.

रखें ध्यान : जब तापमान ज्यादा हो तो हीट स्ट्रोक के खतरे से बचे रहने के लिए बेहतर है कि बाहर न निकलें. ठंडी, वातानुकूलित जगहों पर ही रहने की कोशिश करें. बाहर जाना जरूरी हो तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें. कम से कम एसपीएफ 30 वाली सन्सक्रीन का प्रयोग करें. पर्याप्त पानी पिएं. व्यायाम के समय या किसी भी काम के लिए बाहर जाने पर पानी पीने में बिल्कुल लापरवाही न बरतें. अधिक शारीरिक श्रम वाली बाहरी गतिविधियां सुबह 10–11 बजे से पहले और शाम को 4–5 बजे के बाद करें. बाहर रहने पर थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें, भले ही आपको प्यास न लगी हो. हल्के रंगों के ढीले, सूती कपड़े पहनें. धूप में निकलें तो सनग्लास अवश्य लगाएं. छाते, चौड़े किनारे वाला हैट या स्कार्फ का प्रयोग करें. दिन में घर को ठंडा रखने के लिए पर्दों और सन कंट्रोल फिल्म का प्रयोग कर सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

पानी के बाजार के बीच सेवा का जज्बा

कुमार कृष्णन

जीवन प्राय: दो पहलुओं की ओर चक्कर काटता है. प्रथम अर्थसृजन और द्वितीय सेवा सृजन. हालांकि अर्थ सृजन जीवन की एक स्वाभाविक क्रिया बन गया है. जीवन के सारे विकल्प अर्थ सृजन की ओर चक्कर काटते रहते हैं. चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या आधुनिक आध्यात्म हो, इन सारे क्षेत्रों में अर्थसृजन की प्रधानता प्रबल हो गयी है, लेकिन अर्थसृजन के बीच सेवा सृजन का जो चित्र उभरकर सामने आता है, मानो वह जीवन और समाज के लिए इंद्रधनुष के रूप में होता है. सेवा सृजन का नाम हम आदर्श के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसका जन्म जीवन की विलक्षण प्रतिभा के कोख से होता है, क्योंकि सेवा सृजन में न अर्थ है, न काम है और न मोह है, न कोई अन्य लाभ. यह शुद्ध रूप से वास्तविक जीवन के मूल्यों की कोख से जन्मा एक विलक्षण आदर्श है. इसी आर्दश को मध्य प्रदेश के विदिशा के कुछ लोगों ने एक उदाहरण के रूप में पेश किया है. इसे देखकर, सुनकर रोमांचित हो जाना पड़ता है. यह अनुभव करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि समाज जीवित होकर मुस्कुरा रहा है.

सेवा का भाव संवेदना के स्तर पर निर्भर करता है. 32 वर्ष पहले विदिशा रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरते समय एक महिला गिर गई और ट्रेन के चपेट में आने से उसका हाथ कट गया. इस घटना ने संवेदनशील लोगों की संवेदना को झकझोरा. ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाजसेवी मोहनबाबू अग्रवाल, रामेश्वर दयाल बंसल, नरेंद्र ताम्रकार, लालजी जैन, डॉ सुरेश गर्ग और खीमजी भाई ने मिल कर रेलवे स्टेशन पर जल सेवा शुरू की. यह काम सार्वजनिक भोजनालय सेवा समिति के माध्यम से किया गया. अपने घरों से बाल्टियों में पानी भर कर इसकी शुरुआत की. इस काम को कोई नौजवान नहीं, बल्कि समाज के बुजुर्ग कर रहे हैं. रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की हर खिड़की तक पानी पहुंचाने का कठिन कार्य नगर के समाजसेवी बड़ी ही सेवा भावना से कर रहे हैं. इस सेवा का नाम ग्रीष्मकालीन जल सेवा दिया गया. भीषण गर्मी के दौरान ट्रेन की खिड़की–खिड़की जाकर प्यासे को जल उपलब्ध कराया जाने लगा. इनलोगों ने इस काम को स्थायी रूप देने के लिए जिला प्रशासन और भोपाल के रेल अधिकारियों से अनुमति मांगी और अनुमति मिल गयी. एक जुनून और ललक थी इनलोगों में भीषण गरमी में पानी पिलाने की. लू में जो जज्बा पहले था, वह आज भी है. इसके पीछे एक आस्था है, सेवा का भाव. न बैनर, न होर्डिंग, न आत्म प्रदर्शन, सिर्फ सेवा. धूप और गर्मी की परवाह किए बिना रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे जल सेवा करने का काम. जल सेवा से जुड़े बुजुर्ग समाजसेवियों को यात्रियों के सूखे कंठ तर करने में आनंद की प्राप्ति होती है.

जल सेवा के 32 साल पूरे हो चुके हैं और गुजरते समय के साथ यह सेवा हर साल

नये उत्साह के साथ न सिर्फ आगे बढ़ती जा रही है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम कर रही है. इस सेवा ने विदिशा की पहचान सेवानगरी के रूप में कायम की है. सेवा का अनूठा उदाहरण विदिशा स्टेशन पर देखने को मिलता है. लंबे सफर के दौरान ट्रेनों के यात्री बहुत परेशान होते हैं और ऐसे परेशानी भरे सफर में खिड़की के पास कोई आवाज देता है–ठंडा पानी. इसे जब पीते हैं तो मन को ठंडक और दिल को तसल्ली.

कहते हैं कि इरादे अगर नेक हो तो साधन की कमी नहीं होती है. अनेक लोगों ने पेयजल सप्लाई में काम आने वाली दो गाड़ियां, पानी की टंकियां और अन्य उपयोगी सामग्री भेंटकर इस अभियान को मजबूती प्रदान की. चार साल पहले ग्रीष्मकालीन जलसेवा को विस्तार देते हुए बारह माह निरंतर जलसेवा आरंभ की गयी. इस अभियान को और गति देने के लिए स्वयं का ट्यूब वेल लगवाया है, जिससे वह रात को सीमेंट की बड़ी–बड़ी टंकियां भरते हैं, यही पानी सुबह तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है. उसके बाद सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लगातार रेल यात्रियों को बोगी की खिड़की पर ही शीतल जल उपलब्ध कराया जाता है. यह सुविधा तीनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती है. सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र कहते हैं कि बड़े महानगरों के स्टेशनों पर भी वहां के लोग जो काम नहीं कर पाए, वह काम यहां हो रहा है. सेवा का यह अनूठा उदाहरण है.

इस सेवा को कायम रखने के लिए सार्वजनिक भोजनालय समिति ने जलसेवक तैयार किए. ये जलसेवक अपने समय के अनुसार जलसेवा देते हैं. इन जलसेवकों में रामेश्वर दयाल बंसल, मोहन अग्रवाल, राजेन्द्र शर्मा, बालमुकुन्द गुप्ता, किशनचंद अग्रवाल, वीपी चतुर्वेदी, हुकुमचंद नेमा, खिलान सिंह रधुवंशी, डॉ जीके माहेश्वरी, संतोष ताम्रकार, सुंदरलाल लक्षकार, राजेन्द्र रोंधे, सुभाष हसीजा, प्रेम राठी, हरिवंश सिंह जयहिंद, सत्यनारायण पाटोदिया, ओमप्रकाश पाटोदिया, अरुण शेबड़े, आर.एस स्वामी, शिवशंकर गुप्ता, खुशालचंद्र माहेश्वरी भाईजी', सुरेश माहेश्वरी, गणेशराम कुशवाहा, रमेश मोदी, राजराम शर्मा, सुरेन्द्र नामदेव, महेश कुमार शर्मा, शोभाराम साहू, बाबूलाल अग्रवाल, शत्रुघ्न दीक्षित, संजय प्रधान, बृजमोहन माहेश्वरी, घीसुलाल अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, श्रीलाल कक्का, जिनेश जैन, नंदकिशोर गुप्ता, जवाहर सिंह यादव, नंदकिशोर रैकवार, राजाराम सेन, भैयालाल विश्वकर्मा, नीलकंठ पंडित, रामलाल सेन, बिहारी सिंह रधुवंशी, रामस्वरूप गुप्ता, मर्दन सिंह दांगी, नाथुराम कुशवाहा, गुलाबचंद सैनी, मोहनबाबू चैहान, खुमान सिंह रघुवंशी, कैलाशचंद्र जैन, यशवंत सिंह रघुवंशी, भगवान सिंह धाकड़, हरिचरण गुप्ता, संदीप जैन, सचिन पंजाबी, हनि अरोड़ा, जगराम प्रजापति, कृष्णमुरारी श्रीवास्तव, राजेश रघुवंशी, राजेन्द्र रघुवंशी, देवदत्त शर्मा, रतनलाल साहू, मायाराम श्रीवास्तव, अजय जैन, जीत अरोड़ा और एकता सूद के नाम शामिल हैं. दुष्यंत कुमार पांडुलिपि स्मारक संग्रहालय द्वारा इस संस्था को 20 दिसम्बर, 2012 को सेवा भारती पुरस्कार से नवाजा गया है. भारत में रेल सेवा के विस्तार के साथ अंग्रेजों ने जरूरी इंतजाम किए. इसके तहत मुफ्त जल पिलाने के लिए पर्याप्त संख्या में पानी पांड़े की बहाली की. अंग्रेजों के जाने के बाद जब जगजीवन राम प्रथम रेलमंत्री हुए तो रेल से छुआछुत मिटाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया. इस काम के लिए उन्होंने दलितों को बहाल किया. अब इसकी संख्या नहीं के बराबर है. उत्तर भारत के अधिकांश स्टेशनों पर नल का पानी भी नदारद रहता है. लोगों को बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है.■

feedback@chauthiduniya.com

सऊदी अरब

बग़ावत के आसार

सऊदी अरब में शाह सलमान के बादशाह बनते ही देश कई प्रकार की समस्याओं में उलझ गया है. शाही परिवार की आंतरिक फूट, शियाओं के विरोध और अब आत्मघाती हमलों के अलावा विदेशी स्तर पर सरकार विरोधी गतिविधियों ने देश के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं. कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं की जड़ यमन पर हवाई हमला है.

वसीम अहमद

सऊदी अरब एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है, जिससे निकलने के लिए वह जितना भी हाथ-पैर मारता है, उतना ही ज़्यादा उलझता चला जा रहा है. देश की स्थिति बदतर होती चली जा रही है. जिस देश को कभी शांति का प्रतीक माना जाता था, आज वहां मसलकी विवादों, शाही परिवार में सत्ता को लेकर आंतरिक मतभेदों और सीमा पर क़बायली हमलों ने एक ख़तरनाक स्थिति पैदा कर दी है. सऊदी इतिहास में पहली बार किसी मस्जिद को आत्मघाती हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें 21 लोगों की जानें चली गईं और 80 से अधिक लोग घायल हो गए. शाही परिवार में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं और सऊद परिवार के शहज़ादे दो धड़ों में बंट गए हैं. एक धड़ा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ है, तो दूसरा धड़ा स्वर्गीय अब्दुल्लाह के बेटे मुतअब के साथ है. सत्ता को लेकर गुटबाज़ी का यह सिलसिल यहीं नहीं थमा है, बल्कि यमन पर हवाई हमले को लेकर कुछ वरिष्ठ मंत्री शाह सलमान की नीति के सख्त विरोधी हो गए हैं. ऐसे मंत्रियों में देश के आइकॉन कहे जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री सऊद फ़ैसल एवं पूर्व उत्तराधिकारी मुकरीन भी शामिल हैं. यमन पर हवाई हमले का विरोध करने की वजह से इन दोनों को पदमुक्त कर दिया गया है और अब यह सूचना आ रही है कि मुकरीन नज़रबंद हैं.

तमाम विरोधों के बावजूद शाह सलमान ने अपनी जिद के चलते और अमेरिका के इशारे पर यमन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ तो हासिल नहीं हुआ, बल्कि इस्लामी दुनिया में उनकी ज़बरदस्त बदनामी हुई है. इस हमले के चलते सऊदी अरब की आंतरिक और विदेशी, दोनों स्तर पर जबरदस्त आलोचना हो रही है. पूरा इस्लामी जगत नाराज़ है, क्योंकि शाह सलमान ने इस फ़ैसले के ज़रिये अपने राजनीतिक हितों के लिए एक मुस्लिम देश को तबाही के मुहाने तक पहुंचा दिया है. इस वजह से यमन में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं. स्वयंसेवी संगठन ऑक्सफाम के अनुसार, यमन में एक करोड़ 60 लाख लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं, जिसके चलते मलेरिया, कालरा और डायरिया जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ गया है. यह सब सऊदी हमले के चलते हुआ है. इसके अलावा इस जंग ने क्षेत्र में मसलकी विवाद भी भड़का दिए हैं.

दरअसल, सऊदी अरब हौतियों से यमन की राजधानी सनआ को ख़ाली कराना चाहता है. हौती ईरान से समर्थन प्राप्त शिया समूह है, जो राष्ट्रपति मंसूर हादी के महल पर क़ाबिज़ हो गया था. मंसूर हादी को सत्ता वापस दिलाने के लिए सऊदी अरब यह सारा खेल खेल रहा है. इस खेल की वजह से ईरान तो नाराज़ है ही, सऊदी अरब के अंदर 15 प्रतिशत शिया आबादी भी सख्त नाराज़ है. यह 15 प्रतिशत आबादी पहले भी सऊद परिवार को तख्त से बेदख़ल करने की कोशिश कर चुकी है. लिहाज़ा, 2011 में शिया बहुसंख्यक क्षेत्र क़तीफ़ में शाही परिवार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे. अभी हाल में भी एक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें शेख़ बाक़िर के समर्थन में सरकार के विरुद्ध नारे लगाए गए. शिया धर्मगुरु बाक़िर अलनमर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है. शेख़ बाक़िर की सज़ा-ए-मौत और यमन में हौतियों पर हमले को लेकर पड़ोसी देश बहरीन में भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ है और ख़ुद यमन क़बायली अब हमले से नाराज़ होकर सऊदी अरब के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सरकारी संपत्तियों को नुक़सान पहुंचा रहे हैं. सऊदी हमले का बदला लेने के लिए यमन के क़बायली ज़ोहरान, जाज़ान और नजरान, जो कि यमन के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनकी बस्तियों पर हमले करके सरकारी संपत्तियों को ज़बरदस्त नुक़सान पहुंचा रहे हैं. इन हमलों में कभी-कभी नागरिकों को भी नुक़सान पहुंचता है.

ख़ुलासा यह है कि क़तीफ़ में शियाओं के विरोध, पड़ोसी देश बहरीन में हुए प्रदर्शन और यमन की ओर से क़बायली हमलों ने सऊदी अरब के लिए आंतरिक-विदेशी, दोनों स्तरों पर एक ऐसा दलदल तैयार कर दिया है, जिससे निकलना उसके लिए कठिन से कठिन बनता जा रहा है. यही कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने खाड़ी चोटी कांफ्रेंस में मशविरा दिया था कि सऊदी अरब को यह समस्या बातचीत द्वारा हल करके जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर आना चाहिए.

सऊदी अरब हौतियों से यमन की राजधानी सनआ को ख़ाली कराना चाहता है. हौती ईरान से समर्थन प्राप्त शिया समूह है, जो राष्ट्रपति मंसूर हादी के महल पर क़ाबिज़ हो गया था. मंसूर हादी को सत्ता वापस दिलाने के लिए सऊदी अरब यह सारा खेल खेल रहा है. इस खेल की वजह से ईरान तो नाराज़ है ही, सऊदी अरब के अंदर 15 प्रतिशत शिया आबादी भी सख्त नाराज़ है. यह 15 प्रतिशत आबादी पहले भी सऊद परिवार को तख्त से बेदख़ल करने की कोशिश कर चुकी है. लिहाज़ा, 2011 में शिया बहुसंख्यक क्षेत्र क़तीफ़ में शाही परिवार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे. अभी हाल में भी एक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें शेख़ बाक़िर के समर्थन में सरकार के विरुद्ध नारे लगाए गए. शिया धर्मगुरु बाक़िर अलनमर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है.

सऊदी अरब के अख़बारों में इमाम अबु तालिब मस्जिद पर हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है. ईरान पर इस प्रकार के संदेह पहले से भी किए जाते रहे हैं. जैसा कि अमेरिका के सेना विशेषज्ञ ऑर्थर एच कोर्ड सुमान ने वर्ष 2005 में एक रिपोर्ट में कहा था कि सऊदी अरब को बाहरी ताक़तों से ज़्यादा आंतरिक ताकतों से ख़तरा है. यही शक्ति सऊदी की शहंशाहियत के लिए ख़तरनाक बनेगी. अलक़ायदा के ख़ात्मे के बाद शायद देश को शाह विरोधी ताकतों से मुक्ति मिल जाती, लेकिन ईरान के परमाणु संवर्धन और इराक में उसकी बढ़ती ताकत ने सऊदी राजनेताओं की नींद उड़ा दी. हो सकता है कि ईरान, जो सऊदी ख़ानदान का पहले से ही विरोधी था, सऊदी सरकार को कमज़ोर करने के लिए शियाओं को इस्तेमाल कर सकता है और शायद इसी मक़सद के लिए क़दीह की शिया मस्जिद इमाम अबु तालिब पर आत्मघाती हमले कराए गए हों, ताकि शिया और सुन्नी आपस में उलझ जाएं और देश फूट का शिकार हो जाए.

जानकारों का मानना है कि आत्मघाती हमले के लिए क़दीह का चयन करने के पीछे कोई साजिश हो सकती है. दरअसल, यह क्षेत्र सऊदी अरब के लिए अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण है. यहां पेट्रोल, खजूर, मेवा और मछलियों का भंडार है. इस क्षेत्र में हीरों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस गांव अलक़दीह में यह मस्जिद थी, वह शिया बाहुल्य है. लिहाज़ा ईरान के लिए यहां के नौज़वानों को मसलकी बुनियाद पर अपनी मुहिम में शामिल करना आसान है और दूसरा फ़ायदा यह है कि इस उपजाऊ क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर देने से सरकार को आर्थिक दृष्टि से बड़ा नुक़सान पहुंचाया जा सकता है. इस क्षेत्र को चुनने के पीछे एक कारण और भी हो सकता है. वह यह कि अरब क्रांति के मौक़े पर सीरिया में जो कुछ हुआ, उस तारीख़ को सऊदी अरब में लौटाना. यानी जिस तरह से 2011 में दमिश्क में 10 प्रतिशत सुन्नियों के क्षेत्र से बशर अलअसद के ख़िलाफ़ बग़ावत का आगाज़ हुआ था और यह बग़ावत फैलती हुई पास के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई थी और फिर कुछ महीनों में उसने पूरे देश को अपनी लपेट में ले लिया था.

इस बग़ावत में ईरान सुन्नियों के ख़िलाफ़ बशर अलअसद के साथ था, जबकि सऊदी अरब सुन्नियों का साथ दे रहा था. यहां तक कि उसने अमेरिका को सीरिया पर सैन्य हमले करने के लिए अनुशंसा भी कर दी थी, लेकिन अमेरिका क्षेत्र में किसी नई जंग की स्थिति में नहीं था. लिहाज़ा, वह जंग से बचता रहा. ईरान अब उसी तारीख़ को लौटा रहा है और सऊदी अरब के क्षेत्र क़तीफ़ में शिया बाहुल्य क्षेत्रों से उसी प्रकार शाही परिवार के ख़िलाफ़ बग़ावत बुलंद कराना चाहता है, जिस प्रकार सऊदी अरब ने सीरिया में सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र से शिया सरकार यानी बशर अलअसद के ख़िलाफ़ विद्रोह को हवा दी थी. अगर यह विश्लेषण सही है, तो समझ लेना चाहिए कि सऊदी अरब बेहद चिंताजनक परिस्थितियों से गुज़र रहा है, क्योंकि सीरिया में बशर अलअसद ने सुन्नी विद्रोह पर तो नियंत्रण कर लिया, लेकिन सऊदी अरब में तो शाही परिवार के अंदर ही विद्रोह ज़ोरों पर है. ऐसी स्थिति में अगर बग़ावत होती है, तो शाह सलमान के लिए हालात पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन, कुछ विद्वानों का कहना है कि सऊदी के शिया हालांकि शाही परिवार के विरोधी हैं, लेकिन वे ईरान के हाथों का खिलौना बनकर अपने देश को नुक़सान नहीं पहुंचा सकते. यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना को लेकर वे आक्रोशित और दु:खी तो हैं, लेकिन अनियंत्रित नहीं हुए और न इसके लिए सुन्नियों को दोषी ठहरा रहे हैं.

विद्वानों का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने वाला संगठन आईएसआईएस हो सकता है, जैसा कि उसने स्वीकार किया है और उसके एक सदस्य सालेह अब्दुल रहमान काशमी की पहचान भी हो चुकी है, जिसने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध रखा था. दरअसल, आईएसआईएस सऊदी अरब से इराक और सीरिया पर हुए सैन्य हमलों का बदला लेना चाहता है. सऊदी अरब आईएसआईएस के विरुद्ध सहयोगियों में शामिल है और इराक़ में हवाई हमले करके आईएसआईएस को नुक़सान पहुंचा चुका है. उसी नुक़सान का बदला लेने के लिए आईएसआईएस ने सऊदी अरब में ऐसी वारदात को अंजाम दिया. इस सिलसिले में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश आर्नेस्ट का कहना है कि अभी विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि इस घटना के पीछे कौन है. रही बात आईएसआईएस की, तो वह दबदबा क़ायम रखने के लिए इस प्रकार के झूठे दावे करता रहता है. ख़ैर, इस घटना को किसी ने भी अंजाम दिया हो, लेकिन यह एक शर्मनाक कृत्य है, जिसकी भारत के अनेक संगठनों समेत पूरी दुनिया की ओर से निंदा की जा रही है.

सऊदी अरब के बारे में अगर यह विश्लेषण सही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यमन पर हमला सऊदी अरब के गले की ऐसी फांस बन चुका है, जिसे न निगलते बने और न उगलते. इस हमले की वजह से पड़ोसी देशों में रोष है. इस्लामी जगत की ओर से आलोचना हो रही है, यमन की ओर से सीमावर्ती गांवों पर हमले हो रहे हैं, देश के अंदर जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है और शियाओं के विद्रोह में तेज़ी आ गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि शाही परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य-पदाधिकारी शाह सलमान के ख़िलाफ़ हो गए हैं. यह विरोध कभी भी अपना रंग दिखा सकता है. यमन पर हमले के बाद शियाओं समेत सुन्नियों की भी एक बड़ी आबादी सरकार से नाराज़ है. जाहिर है, यह नाराज़गी किसी तूफान का कारण बन सकती है, जिस पर सऊदी राजनेताओं को अभी से ही विचार करना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

बुद्ध ने पूछा कि और यदि कोई तुम पर धूल फेंक दे तो? मैं उसे भला ही कहूंगा क्योंकि उसने धूल ही तो फेंकी, थप्पड़ तो नहीं मारा. और यदि कोई थप्पड़ मार दे तो क्या करोगे? मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे थप्पड़ ही मारा, डंडा तो नहीं मारा. और कोई डंडा मार दे तो? मैं उसे धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने मुझे केवल डंडे से ही मारा, हथियार से नहीं, लेकिन मार्ग में तुम्हें डाकू भी मिल सकते हैं जो तुम पर घातक हथियार से प्रहार कर सकते हैं, तो क्या? मैं तो उन्हें दयालु ही समझूंगा, क्योंकि वे मारते ही हैं, मार नहीं डालते और यदि वे तुम्हें मार ही डालें तो?

आध्यात्मिक पथ पर प्रगति

चौथी दुनिया ब्यूरो

सदगुरु ने जब भी जब भी किसी की मदद की, अकस्मता की. जब वे यह देखते हैं कि व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने को अच्छा या निर्मल बनाने का प्रयत्न कर रहा है, पर ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वे उसकी सहायता करते हैं. जैसे श्री उपासनी बाबा–जिनके विषय में श्री साई बाबा के पास आए थे तो बहुत कुछ वे स्वयं करके आए थे. बाबा के पास आने के अनेक वर्ष पूर्व बहुत कम आयु में उन्होंने पूरे एक साल बिना भोजन किए साधना की थी और शरीर और मृत्यु के रहस्य को समझने का प्रयत्न किया था. वे एक ऐसी गुफा में जाकर रहे थे जहां पीना भी उपलब्ध नहीं था. उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया. मान–अपमान सहा. घर–परिवार सबको छोड़कर चार वर्षों तक खंडोबा मंदिर में रहे थे. कहने का मतलब यह है कि जिसने भी पाया, उसने पहले स्वयं प्रयत्न किया, उसके लिए कष्ट सहा और त्याग किया, तब जाकर वे सदगुरु की कृपा के पात्र बने.

बाबा ने कहा था कि पहले मन के छोट–छोटे बन्धनों से तो निकलो. वे जानते थे कि अधिकांश लोग आध्यात्मिक चेतना के निम्न स्तर पर हैं. इसीलिए पहले उन्होंने दक्षिणा मांग–मांग कर रुपये पैसे के मोह से निकलने की बात सिखाई. वे चाहते थे कि लोग पहले इसकी माया से तो निकलें. जब काका साहेब दीक्षित ने सब कुछ छोड़ा, तब जाकर उन्हें सब कुछ मिला.

आंतरिक पूजा

क्या औपाचारिक रूप से पूजा–पाठ आदि करना ही आध्यात्मिकता है?

हां भी और नहीं भी. चेतना के विभिन्न स्तर पर लोग विभिन्न प्रकार की पूजा–परिपाटी करते हैं. एक आदमी सोना, रूपया, फल आदि समस्त वस्तुएं चढ़ाकर किसी देव की पूजा कर सकता है और एक गरीब व्यक्ति तुलसी अक्षत फल और दूर्वा के साथ पूजा करता है. श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि अगर भाव पूरा हो, चाहे पूजा सरल हो, तो वह ईश्वर द्वारा ग्राह्य है. ईश्वर के प्रति ज्यादा वस्तुएं अर्पित करने के उपरांत भी भाव न हो तो पूजा पूर्ण नहीं होती. कई लोग तो इस प्रकार की पूजा न करके अंतर्मन में पूजा करते हैं. बाबा ने कहा है कि आंतरिक पूजा अर्थात भाव पूजा ही श्रेष्ठ है. अन्ततोगत्वा जिसके भाव शुद्ध एवं एकाग्र और चेतना शुद्ध है, तो वह चाहे किसी भी प्रकार की पूजा करे, वह ईश्वर द्वारा ग्राह्य है. यही वास्तव में आध्यात्मिकता का रास्ता है. यदि केवल भौतिक आवश्कताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की पूजा की जाती है, तो वह आध्यात्मिक नहीं है. वह सकाम पूजा है, जब कि ईश्वर निष्काम पूजा से संतुष्ट होते हैं. जो भी कुछ हमारे प्रारब्ध के कारण जीवन में घटित होता है. क्या हमने उसे सवीकार किया–चाहे वह दुख अथवा सुख हो. क्या हम ईश्वर की कृपा पाने के लिए योग्य बन पाए? अपने विषय में न सोचकर क्या दूसरों के हित के लिए कुछ कर पाए? जब तक ऐसा करने की शक्ति अपने में जागृत न कर पाएं, तब तक

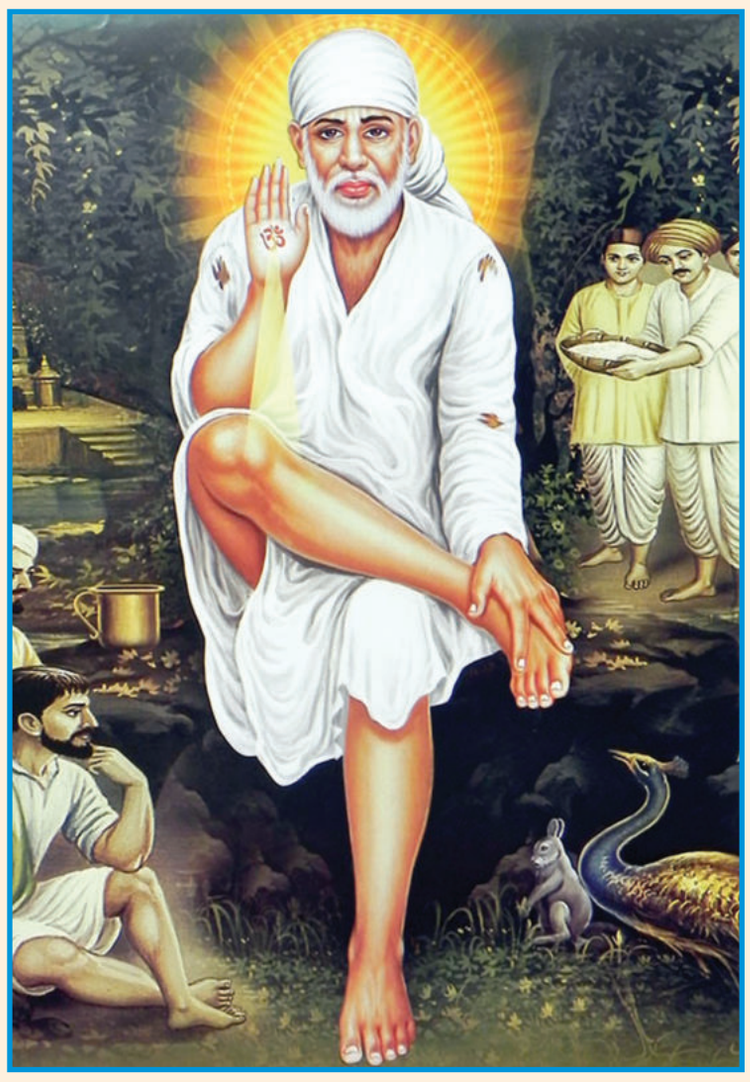

आध्यात्मिक मार्ग पर चलना संभव नहीं है.

बंधन मुक्ति

कोई प्राणी जीवात्मा से शिवात्मा कैसे बनता है?

जब कोई प्राणी निष्पृह होकर अर्थात कामना रहित होकर, संसार में रहकर भी सांसारिक आर्कषणों के प्रति विरक्त रहकर, किसी के लिए कुछ करने पर बदले में बिना कुछ चाहे करुणावश समाज के लिए त्याग करना शुरू करता है तो उसकी आत्मा क्रमश: महात्मा स्वरूप को धारण करने लगती है. फिर वह जीवात्म के बंधन में नहीं रहता. वह शिवात्मा बनता है, जो कि सर्वव्यापक, शांत और अद्वैत रूप है. शिवं शांतं अद्वैतम्

लेकिन यह एकाएक नहीं होता. कठोर साधना के बाद ही ऐसा भाव उत्पन्न होता है.

अध्यात्म मार्ग : दु:ख से निवृत्ति

बहुत सी पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि जो अध्यात्म–मार्ग पर चलेगा वह बहुत कठिनाई पाएगा. क्या यह बात सही है?

आध्यात्मिक जगत में जो जाएगा, उसे भौतिक दुनिया की विचारधारा और प्रणाली से अलग होना पड़ेगा, ेज कि समाज में रहते हुए आसना नहीं है. जैस कि लोभी व्यक्ति से यह कहा जाए कि वह अफनी कमाई का पच्चीस प्रतिशत ईश्वर या गरीबों के लिए दान करे, तो वह अनुभव करेगा कि उस पर अत्यंत संकट का पहाड़ टूट पड़ा है. लेकिन उसका विश्वास पक्का है, तो वह ऐसा कर भी देगा. आगे चलकर त्याग करते समय उसे कष्ट नहीं होगा, जो यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अन्य अर्थ दु:ख–यात्रा को झेलना है, तो यह बात सम्पूर्ण रूप से निराधार है. जो व्यक्ति विचार या मोह आदि बंधन में बंधा हुआ है , वस्तुत: उसी को कष्ट होता है. सत्यता तो यह है कि व्यक्ति धीरे–धीरे जैसे–जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो उसके दु:ख का अनुभव भी क्रमश: खत्म होता जाएगा. इस मार्ग पर तो वह बंधन ही हट जाता है और व्यक्ति हल्का हो जाता है. फिर दु:ख को अनुभव करने का प्रश्न ही नहीं उठता. यदि उसका दु:ख बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर न चलकर वह उसकी उल्टी दिशा में चल रहा है.

लोग संतों के जीवन में बाह्य रूप से दिखने वाले कष्ट एवं कठिनाइयां देखते हैं और उन पर दया भी करते हैं. संत जन तो बन्धन मुक्त हैं और वे सदैव अखंड आनंद की स्थिति में रहते हैं. उनको सामान्य आदमी जैसे दु:ख या सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वे अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियों पर सम्पूर्ण नियंत्रण पा चुके हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

प्रधानमंत्री जी वादा निभाएं

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पिछले एक वर्ष से सिर्फ मन की बात करते आ रहे हैं, जिसे सुन–सुन कर अब जनता उब चुकी है. जनता अब काम की बातें सुनना चाहती है. 2014 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी भाजपा और आपने चुनावपूर्व जो घोषणापत्र में जनता को सपना दिखाया था. कालाधान की वापसी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना और धारा 370 खत्म करने की बात करते थे. सरकार बनने के बाद इन सभी मुद्दों को भुलकर आपके सांसद और मंत्री जी लव जिहद, घर वापसी, गोरी चमड़ी और चार बच्चे पैदा करने की बात करने लगे है. यदि यही हाल रहा तो जो हश्र भाजपा का दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ, उससे भी बुरा हश्र भाजपा का बिहार विधानसभा के चुनाव में होने वाला है, क्योंकि नवगठित जनता परिवार के विलय के बाद भाजपा कहीं मुकाबले में नजर नहीं आएगी. इसलिए आप मन की बात को छोड़कर लोकसभा चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों पर काम करें.

–राकेश कुमार, खगड़िया, बिहार.

न्यायिक सुधार आवश्यक

फिल्म अभिनेता सलमान खान को हिट एण्ड रन मामले में 5 साल की सजा हुई, लेकिन इसमें निचली अदालत सेशन कोर्ट में ही 13 साल का समय लग जाना देश की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है. सड़क दुर्घटना हमारे देश का उपेक्षित विषय है, जिसमें हर साल लगभग डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं, इनमें 80 फीसद मौतें शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाने में होती है. अत: आवश्यक है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को तुरंत सख्त सजा दी जानी चाहिए. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, जिसका इस्तेमाल निष्पक्ष न्याय दिलावने के लिए हो, न्याय टालने के लिए नहीं.

–सत्य प्रकाश शिक्षक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

विनोद राय भारत रत्न के हकदार

देश की महान हस्तियों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किए जाने की परम्परा रही है. देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय वह शख्सियत हैं, जिन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम और कोल ब्लाक आवंटन घोटाले का पर्दाफाश किया और देश को कि किस प्रकार यूपीए सरकार ने लाखों करोड़ों का चूना लगया. अगर विनोद राय ने यह हिम्मत नहीं दिखाई होती, तो देश का खजाना यू हीं लुटता रहता. ऐसे महान साहसी व देशभक्त को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा.

–राज किशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

जनता की समस्याओं को हल करें

केजरीवाल और एलजी के बीच चल रही लड़ाई अहम की लड़ाई बन गई है. दोनों ही फैसले पर अड़े हुए हैं. आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी नजीब जंग को केन्द्र सरकार के इशारे पर काम करने का आर–ोप लगा रही है, तो वहीं केन्द्र का आरोप है कि केजरीवाल संविधान को नहीं मानकर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं. लड़ाई दिल्ली में मख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर शुरू हुई थी, मुख्य सचिव के.के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर गए थे, लेकिन उनके अब वापस आकर काम संभाल लेने के बाद भी अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर लड़ाई जारी है. के. के शार्म के छुट्टी के दौरान एलजी ने कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में शकुल्तना गैमलीन को नियुक्त किया था, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सहमत नहीं थे और वे बार–बार केन्द्र पर चोर दरवाजे से सरकार चलाने का आरोप लगा रहे हैं. दिल्ली की जनता की बहुत सारी समस्याए हैं इसलिए केजरीवाल को केन्द्र सरकार के साथ मतभेद भुलाकर, उसके साथ मिलकर दिल्ली की जनता की समस्याओं दूर करना चाहिए.

–रीतिका वर्मा, पालम, दिल्ली.

कब तक निशाना बनाया जाएगा

कवर स्टोरी– मुस्लिम आतंकवाद का असली चेहरा (25 मई–31 मई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. डॉ. कमर तबरेज से मैं सहमत हूं कि आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हज़ारों लोगों को भेड़–बकरियों की तरह जेलों में ठूंस दिया जाए, एक विशेष वर्ग को इसके लिए निशाना बनाया जाए. देश की कानून और पुलिस की यही समस्या है कि किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो और उसने गुनाह नहीं किया तो वह बेगुनाह होने का सबूत पेश करें. एक निर्दोष व्यक्ति को अपने बेगुनाह होने का सबूत पेश करना पड़ता है और शक के आधार उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है. आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता है, लेकिन कोई आतंकवादी घटना होने पर मुसलमानों को ही पकड़ा जाता है. कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वह निर्दोष साबित हुआ, लेकिन उसका भविष्य बर्बाद होने के बाद. इसलिए किसी भी धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पक्के सबूत होने पर उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

–शाहिद इकबाल, दरभंगा, बिहार

जनता की आवाज

चौथी दुनिया समाचार पत्र मैं तीन सालों से पढ़ रहा हूं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावित करने वाली होती हैं. इसमें कवर स्टोरी से लेकर आखिरी पेज तक प्रकाशित खबरें जनता से जुड़ी होती हैं. संतोष भारतीय का संपादकीय पढ़कर बहुत खुशी होती है कि वह जनता जुड़े हर मुद्दे को अपने संपादकीय के माध्यम से उठाते हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र की सभी खबरें तथ्यों पर आधारित और समाज से जुड़ी हुई होती हैं. चौथी दुनिया समाचार जनता की आवाज है.

–राहुल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

सच्चे साधु की पहचान

चौथी दुनिया ब्यूरो

महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दीक्षा देने के बाद कहा कि तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे. अच्छे लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और सहायता करेंगे. बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियां देंगे. तब तुम्हें कैसा लगेगा? एक गुणी शिष्य ने कहा कि मैं किसी को बुरा नहीं समझता. कोई मेरी निंदा करेगा या मुझे गालियां देगा तो मैं समझूंगा कि वह भला व्यक्ति है क्योंकि उसने मुझे सिर्फ गालियां ही दीं, मुझ पर धूल तो नहीं फेंकी.

बुद्ध ने पूछा कि और यदि कोई तुम पर धूल फेंक दे तो? मैं उसे भला ही कहूंगा क्योंकि उसने धूल ही तो फेंकी, थप्पड़ तो नहीं मारा. और यदि कोई थप्पड़ मार दे तो क्या करोगे? मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे थप्पड़ ही मारा, डंडा तो नहीं मारा. और कोई डंडा मार दे तो? मैं उसे धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने मुझे केवल डंडे से ही मारा, हथियार से नहीं, लेकिन मार्ग में तुम्हें डाकू भी मिल सकते हैं जो तुम पर घातक हथियार से प्रहार कर सकते हैं, तो क्या? मैं तो उन्हें दयालु ही समझूंगा, क्योंकि वे मारते ही हैं, मार नहीं डालते और यदि वे तुम्हें मार ही डालें तो? शिष्य बोला कि इस जीवन और संसार में केवल दुख ही है. जितना अधिक जीवित रहूंगा उतना दुख देखना पड़ेगा. जीवन से मुक्ति के लिए आत्महत्या करना तो महापाप है. शिष्य के वचन सुनकर बुद्ध बोले–तुम धन्य हो. वास्तव में तुम सच्चे साधु हो. सच्चा साधु किसी भी दशा में दूसरे को बुरा नहीं समझता. जो दूसरों में बुराई नहीं देखता, वही सच्चा परिव्राजक होने के योग्य है. मुझे विश्वास है तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

दिनकर के सम्मान की पहल

अनंत विजय

रामधारी सिंह दिनकर ने साफ़ तौर पर लिखा है, साहित्य के क्षेत्र में हम न तो किसी गोयबेल्स की सत्ता मानने को तैयार हैं, जो हमसे नाजीवाद का समर्थन लिखवाए और न किसी स्टालिन की ही, जो हमें साम्यवाद से तटस्थ रहकर फूलने–फलने नहीं दे सकता. हमारे लिए फरमान न तो क्रेमलिन से आ सकता है और न आनंद भवन से ही. अपने क्षेत्र में तो हम उन्हीं नियंत्रणों को स्वीकार करेंगे, जिन्हें साहित्य की कला अनंत काल से मानती चली आ रही है. यह था दिनकर का साहस और यह थी उनकी साफ़गोई. ये बातें दिनकर उस वक्त कह रहे थे, जब पूरा देश वामपंथ और नेहरू के रोमांटिसिज्म के प्रभाव में था. आज़ादी के बाद भारतीयता और राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, तो उस वक्त दिनकर ने एक किताब संस्कृति के चार अध्याय लिखी. पहले संस्करण पर उनकी भूमिका में पांच जनवरी, 1956 की तारीख है. इस किताब के प्रकाशन के अगले वर्ष साठ साल पूरे हो रहे हैं. इस मौक़े पर देश भर में साल भर तक दिनकर पर केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है. यह पहल की है पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने. साल भर चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया.

रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक हिंदी कविता के उत्तर छायावादी दौर के बेहतरीन कवि थे. उनकी कविता की खास बात यह कि उसका रेंज बहुत व्यापक है और एक कवि के रूप में दिनकर ने लगातार अपने आपको परिमार्जित किया. कविता के अलावा दिनकर ने गद्य लेखन भी किया. दरअसल, अगर हम देखें, तो नई कविता के दौर में और उसके बाद भी दिनकर जी की कविताओं को वह प्रतिष्ठा नहीं मिली, जिसकी वे हक़दार थीं. साजिशन उन्हें सरकारी कवि के तौर पर पेश करके उनकी अनदेखी की जाती रही, खास तौर पर जब प्रगतिशीलता का बोलबाला था. लेकिन कहते हैं कि प्रतिभा और श्रेष्ठ रचना को कोई रोक नहीं सकता. बाद के दिनों में नामवर सिंह भी यह कहने को मजबूर हो गए कि कुल मिलाकर दिनकर जी का रचनात्मक व्यक्तित्व निराला की तरह है. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के उन विरले रचनाकारों में से हैं, जिनकी कविताओं में एक साथ राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सामाजिकता, प्रेम, आध्यात्म यानी सभी कुछ मौजूद है. दिनकर जी ने विपुल लेखन किया. किसी खास विचारधारा को न मानने की वजह से उनके लेखन का उचित मूल्यांकन नहीं हो सका.

दिनकर की किताब–संस्कृति के चार अध्याय दरअसल एक बार फिर से बहस की मांग करती है. दिनकर ने अपनी इस किताब में भारत में चार क्रांतियों का ज़िक्र किया है. उनका मानना है कि देश की सांस्कृतिक क्रांति का इतिहास उन्हीं चार सांस्कृतिक क्रांतियों का इतिहास है. दिनकर के

मुताबिक, पहली क्रांति तब हुई, जब आर्य भारत आए और उनका संपर्क आर्येतर जातियों से हुआ. दूसरी क्रांति तब हुई, जब महावीर एवं बुद्ध ने स्थापित धर्मों के विरुद्ध विद्रोह किया और उपनिषदों की चिंता धारा को खींच कर वे अपनी दिशा में ले गए. संस्कृति के चार अध्याय में दिनकर ने कहा है कि तीसरी क्रांति तब हुई, जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और हिंदुत्व से उसका संपर्क हुआ. चौथी क्रांति तब हुई, जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ. संस्कृति के चार अध्याय में जिस तरह से सांस्कृतिक इतिहास को काल खंडों में विभाजित करके दिनकर ने लिखा है, वह इतिहासकारों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में अपने प्रकाशन के साठ सालों के बाद भी खड़ा है. दरअसल, दिनकर जब हिंदू और मुसलमान के बीच सांस्कृतिक एकता और समान संस्कृति की बात करते हैं, तो यह कथित प्रगतिशील इतिहासकारों को नागवार गुज़रता है. लिहाजा उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

इस किताब के प्रकाशन के छह साल के अंदर जब इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, तो उसकी भूमिका में दिनकर ने लिखा, घटनाओं को स्थूल रूप से कोई भी देख सकता है, लेकिन उनका अर्थ वही पकड़ता है, जिसकी कल्पना सजीव हो. इसलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी खंडित नहीं होते. दिनकर जी खुद को इतिहासकार नहीं मानते थे, बल्कि संस्कृति के चार अध्याय के बारे में तो उन्होंने लिखा, यह महल साहित्य और दर्शन का है. इतिहास की हैसियत यहां किराएदार की है. किराएदार का आदर तो मैं करता हूं, पर महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूं. दिनकर जी ने साफ़ किया है कि संस्कृति के चार अध्याय इतिहास नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक क्रांतियों को परखा है, वह पुनर्पाठ के लिए पुख्ता ज़मीन तैयार करता है. अपनी इस किताब में दिनकर ने भारत में हिंदू–मुसलमान संबंधों को बहुत गहनता से परखा है. दिनकर ने लिखा है, भारत में एक विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोंटकर एक जाति बना देता है, अनेक धर्मों को मिलाकर एक धर्म तैयार कर देता है और अनेक संस्कृतियों के मिश्रण से एक संस्कृति पैदा कर देता है.

नीग्रो, औष्टिक, द्रविड़ और आर्य, कम से कम ये चार जातियां थीं, जिनके परस्पर मिश्रण और मिलन से एक महाजाति पैदा हुई, जिसे हम हिंदू जाति कहते हैं. हिंदू कहलाने वाली संस्कृति इन चारों जातियों की संस्कृतियों के मिलन से पैदा हुई. यह समन्वित संस्कृति जब उपनिषधों के धरातल पर पहुंची, तब वहां से धर्म और विचार जैसी अनेक धाराएं फूट पड़ीं, जिनमें कुछ आस्तिक थीं, कुछ नास्तिक, कुछ वेद को मानने वाली, तो कुछ वेद को न मानने वाली. यह और तरह की बौद्धिक अराजकता थी, एक तरह का चिंतन का कोलाहल था, जिसे बांधकर एक ओर ले चलना आसान नहीं था. इसलिए एक ही काल में आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन की रचना होने लगी और सारा देश चिंतकों के तरह–तरह के विचारों से जगमगा उठा. दिनकर की इस अवधारणा के प्रकाशन के साठ सालों के बाद तक इस पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया. बजाय दिनकर की रचनाओं और अवधारणाओं पर बात करने के एक बार फिर से उन्हें एक जाति विशेष से जोड़कर देखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. दिनकर का साहित्य पढ़े बगैर लोगों ने साल भर चलने वाले कार्यक्रमों को बिहार चुनाव से जोड़कर भूमिहार जाति को रिझाने की भाजपा की कोशिश के तौर पर देखना और प्रचारित करना शुरू कर दिया है.

सवाल यही उठता है कि हमारा कथित प्रगतिशील बौद्धिक समाज हर चीज को किसी न किसी चश्मे से देखना शुरू कर देता है. हमारे यहां की बौद्धिक प्रगतिशीलता का आधार ही यही रहा है कि जो आपकी विचारधारा के साथ न चले या जो आपकी विचारधारा का अनुयायी न हो, उसे बदनाम करना शुरू कर दो. बदनाम भी इस हद तक कि उसे साहित्य की दुनिया में अस्पृश्य कर दो, संवाद ख़त्म कर दो. यह इतनी बड़ी साजिश होती है कि किसी भी रचनाकार पर संवाद की प्रक्रिया ही बाधित या बंद कर दो. नतीजा यह होगा कि न उसकी रचना पर संवाद होगा और न उसकी रचनाओं की आलोचना होगी. यह खेल लंबे समय तक चला. दिनकर जी को वामपंथियों के इस खेल का भलीभांति एहसास था, तभी तो वह बहुधा उन पर चोट भी करते चलते थे. दिनकर ने कहा था, किसी भी कृति को मार्क्सवादी सिद्धांतों की कसौटी पर कसकर उसे क्रांतिकारी अथवा श्रेष्ठ करने की चेष्टा अयुक्तियुक्त और अन्यायपूर्ण है. दिनकर हमेशा से समालोचना को कवित्व के बराबर मानते हैं. वह कहते हैं, जो लोग यह समझते हैं कि समालोचना सीखने की चीज है, वे ग़लती करते हैं. यह भी उसी प्रकार का जन्मजात है, जैसे कवित्व. तभी तो डॉ. नागेंद्र ने कहा था, यह उनके व्यक्तित्व की सजीवता का प्रमाण है कि उन्होंने किसी एक विचार पद्धति को नतशिर होकर स्वीकार नहीं कर लिया. दिनकर की साहित्य में उपेक्षा की यह बड़ी वजह है.

दिनकर की दो कृतियों पर हुए समारोह के बहाने से उनकी रचनाओं पर बात हो, सिर्फ़ सरकारी समारोह की तरह रस्म अदायगी न हो, तो यह दिनकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. जिस तरह से दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने भी दिनकर की रचनाओं पर बात नहीं की. प्रसून जोशी ने अवश्य उनकी कविताओं का सस्वर पाठ किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी एक कविता चिपका दी. मंच पर डॉ. बिंदेश्वर पाठक और ऊषा किरण खान की मौजूदगी की वजह समझ से परे रही. मंच पर बैठे प्रधानमंत्री कई बार असहज महसूस कर रहे थे, जब उनके व्यक्तित्व की तुलना दिनकर की कविता की मजबूती से की जा रही थी. धन्यवाद ज्ञापन में उनके लिए प्रयुक्त विशेषण उन्हें असहज कर गए. मंचासीन साहित्यकारों ने न तो संस्कृति के चार अध्याय पर कुछ कहा और न परशुराम की प्रतीक्षा पर. हैरत तो साठ साल पूरे होने को स्वर्ण जयंती कहने पर भी हुई. इन्हीं वजहों ने आलोचकों को अवसर दिया. आयोजकों को इस पर विचार करना चाहिए.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

समाजवाद के सच्चे सिपाही थे चंद्रशेखर

समीक्ष्य पुस्तक
राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर
संपादक
धीरेंद्र नाथ श्रीवास्तव
विचार संपादक
यशवंत सिंह
प्रकाशक
श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
मूल्य: 495 रुपये

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारतीय राजनीति में युवा तुर्क के रूप में विख्यात रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पहचान एक ऐसे समाजवादी नेता की थी, जिसके माध्यम से न केवल राम मनोहर लोहिया के विचार आगे आए, बल्कि जिसने देश की राजनीति में एक अलग मुकाम बनाया. प्रधानमंत्री के रूप में अपने छोटे–से कार्यकाल में उन्होंने इस बात का बोध कराया कि निहित स्वार्थों को त्याग कर कैसे पूरे राष्ट्र और समाज के लिए निर्णय लिए जाते हैं. चंद्रशेखर निर्विवाद रूप से राष्ट्र की धरोहर थे और रहेंगे. राजनीति का अर्थ उनके लिए राज करने की नीति नहीं था, बल्कि राजनीति उनके लिए जनसेवा और अन्याय विहीन भारत की स्थापना का माध्यम थी. वह एक दृढ़ नेता और नेक इंसान की तरह घृणा और अन्याय को मिटा देने का प्रयास करते रहे. वह जीवनपर्यंत जातिवाद, सांप्रदायिकता, ग़रीबी और बेबसी से जूझ रहे देश में नवीन अमृत संचार का प्रयास करते रहे. उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा. उन्होंने सदैव समाज के बारे में सोचा. घनघोर संकट के बीच अपनी मान्यताओं के लिए अकेले खड़े होने का गुण उन्हें समकालीन नेताओं से अलग करता है.

उनके जीवन पर बहुत कम किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हाल में श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित पुस्तक–राष्ट्रपुरुष चंद्रशेखर में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी बेबाकी से प्रकाश डालने की कोशिश की गई है. जिस तरह पांच तत्वों से शरीर बना है, उसी तरह इस किताब को भी पांच खंडों में विभाजित किया है, जिससे चंद्रशेखर का व्यक्तित्व परिभाषित होता है. पहले खंड में उनके भाषण, दूसरे में उनसे जुड़ी यादें और विचार हैं, तीसरे में उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, चौथे में उनकी कहानी–जिनकी यादों को चंद्रशेखर कभी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल पाए तथा पांचवें खंड में वह राष्ट्रपुरुष क्यों हैं, इसे रेखांकित किया गया है. किताब की भूमिका में दिनेश दीनू ने लिखा है कि चंद्रशेखर जी के पास जो जाता था, उसका स्वागत गुड़ और पानी से होता था. भारतीय जन संस्कृति की यह परंपरा उनकी चौखट पर हमेशा रही. इस पुस्तक में भी उसी गुड़ और पानी की मिठास है. यह किताब बताती है कि किस तरह उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के एक छोटे–से गांव इब्राहिम पट्टी से निकल कर एक शख्स देश का प्रधानमंत्री बन गया. बचपन के सामाजिक परिवेश का उनके व्यक्तित्व और विचारों पर कैसा प्रभाव पड़ा, इस पर किताब में विस्तार से चर्चा है. किताब में बताया गया है कि वह सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते थे. जैसे कि एक बार वह विवाह समारोह में गए. वहां वह ज़मीन पर बिछे गद्दों पर बैठ गए और उन्होंने उपस्थित महिलाओं से गाली (संस्कार गीत) सुनाने की फरमाइश की. उस वक्त वह राजनीतिज्ञ की जगह एक घरेलू चंद्रशेखर नज़र आ रहे थे. एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक महान सांसद, एक क्रांति का प्रतीक अपने पूरे आवरण को किस घर के बाहर किस तरह छोड़ आया था. आज के नेताओं से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उन्होंने अपना आर्थिक सलाहकार भले ही बनाया था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की चंद्रशेखर जी ने सदैव आलोचना की. पूरी ज़िंदगी उन्होंने समाजवादी सिद्धांतों को अपनी राजनीति का आधार बनाए रखा. वह कांग्रेस के बंटवारे के समय इन्हीं मूल्यों के तहत इंदिरा गांधी के साथ गए थे. उनका मानना था कि भारत जैसे देश में, जहां की दो–तिहाई आबादी खेती पर निर्भर है, वहां उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों की ज़रूरत नहीं है. वैश्वीकरण के भारतीय जीवन पर होने वाले असर को उन्होंने पहचान लिया था और जीवनपर्यंत वह इसका विरोध करते रहे. चंद्रशेखर का अर्थशास्त्र प्रचलित सैद्धांतिक खांचे से नहीं, बल्कि देश की हक़ीक़त से संचालित होता था. बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया जाता है, मगर हक़ीक़त में वह चंद्रशेखर ही थे, जिन्होंने संसद में इस बिल को मजबूती से लाने में भूमिका अदा की थी. वह तब कांग्रेस के महासचिव थे. प्रो. एसके गोयल ने यह बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर तैयार किया था, मगर लंबी बातचीत के बाद चंद्रशेखर ने इस पर एक मजबूत प्रस्तुति बनाई और इसे पार्टी की तरफ़ से पेश करने का निर्णय लिया. देश के लिए वैकल्पिक आर्थिक नीति लाने का श्रेय भी चंद्रशेखर को जाता है, जिसके आधार पर अपने पहले कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियां बनाईं.

सामाजिक रूप से वह कितने सचेत थे, इस किताब में कई उदाहरण हैं. इंदिरा गांधी द्वारा जयप्रकाश नारायण को जेल में डालने की सार्वजनिक रूप से आलोचना करके वह रातोंरात लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रतीक बन गए थे. इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया था, लेकिन जनता पार्टी के गठन के समय वह अध्यक्ष पद के सबसे निर्विवाद नाम थे. उन्होंने इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध किया था, वह स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने के सख्त ख़िलाफ़ थे. उस वक्त सारा विपक्ष इंदिरा जी के क़दम की सराहना कर रहा था, लेकिन चंद्रशेखर ने उसका विरोध किया था. उन पर इसे लेकर राजनीतिक हमले किए गए, लेकिन वह अपने मत से टस से मस नहीं हुए. इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए. बावजूद इसके वह राजनीतिक नफ़ा–नुक़सान का आकलन किए बगैर अपने सहयोगियों के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में घूमते रहे.

चंद्रशेखर भारत की विरासत को समझते थे और मानते थे कि इस साझी विरासत को संभालना देश के हर व्यक्ति का दायित्व है. वह सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ थे. उन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद संसद में कहा, यह जो गिराई गई है, वह महज मस्जिद नहीं थी, यह भारत की गौरवशाली परंपरा थी, भारत का इतिहास था, भारत का सह–अस्तित्व था और भारत की मानवीय परंपरा थी, जिसे हवाओं में उड़ा दिया गया. भारत के करोड़ों नागरिकों का हृदय टूटा है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकेगा.

बिना झुके, बिना समझौते के खरी–खरी सीधी बात करने वाला एक साधारण इंसान देश की राजनीति के लिए कैसे अपरिहार्य हो जाता है, यह किताब उसे विस्तृत तरीके से बताती है. चंद्रशेखर वास्तव में राष्ट्रपुरुष थे. यदि वह लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहते, तो आज देश की दशा–दिशा कुछ और होती. संसद में जब चंद्रशेखर बोलते थे, तो पूरा सदन उनकी बात शांत होकर सुनता था. उनके बोलने के दौरान शायद ही कभी संसद में टोका–टाकी हुई हो. उनके जैसे नेता की कमी देश को हमेशा खलेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

जियोनी ईलाइफ ई8 में 4.6 इंच क्यूएचडी 1440x2560 रेजोल्यूशन एमओएलइडी डिस्प्ले दिखाया गया है. डिवाइस अमीगो यूआई पर आधारित एंड्रायड 5.0 लॉलीपॉप पर चलती है, इसमें 2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर प्रोसेसर 3जीबी रैम के साथ उपलब्ध है. यह स्मार्टफोन 2जी, 3जी, 4जी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

अगर आपका फोन खो जाए, तो अपनाएं ये तरीके

श्याम सुन्दर प्रसाद

आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आपका फोन खो जाये तो आप काफी परेशान हो जायेंगे, क्योंकि इसके बाद न तो आपको केवल दूसरा फोन खरीदने का झंझट आ जाता है, बल्कि फोन के साथ आपके काफी सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ निजी तस्वीरें, फोन नंबर, एड्रेस, वीडियो, फ़ोन डाटा जो उसमें स्टोर होता है. यह सब दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है और आपसे जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं और तस्वीरों का दुरूपयोग कर सकता है. अगर आप थोड़ी से सावधानी बरतें तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आप ऐसी स्थिति में अपने डाटा गलत हाथों जाने और उसका दुरूपयोग होने से बचा सकते हैं.

आपकी मदद के लिए कुछ जानकारियां

आपको अपने फोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको अपना खोया मोबाइल पाने में आसानी हो. इसलिए आपको आपके मोबाइल का आईएमईआई नंबर की जानकारी हो. अगर आपके पास आईएमईआई नंबर की जानकारी नहीं है, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल पर टाइप करें *06, यह नंबर टाइप करते ही आपकी स्क्रीन पर आईएमईआई नंबर(International Mobile Equipment Identity) आ जाएगा, जिसे आप हमेशा के लिए लिखकर सुरक्षित रख लें. अगर आपका मोबाइल चोरी होता है, तो आईएमईआई नंबर के द्वारा चोरी हुए मोबाइल की जानकारी आसानी से पाई जा सकती है. आप हमेशा अपने फोन को स्क्रीन पैटर्न या पासवर्ड एनेबल लॉक करें, फ़ोन खो जाने पर फ़ोन को वापस खोजने में तो यह कोई मदद नहीं करेगा पर फोन के खो जाने पर स्क्रीन लॉक होने की वजह से कोई आपकी निजी जानकारियों को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता है.

एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम

ऐंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर गूगल की ऐसी सर्विस है, जिसके जरिए आप अपना ऐंड्रॉयड फोन या टैबलेट कहीं रखकर भूल गए हैं, या आपका फ़ोन खो गया हो तो इसके माध्यम से आपके फोन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर लोकेशन ऑप्शन में जाकर इसे इनेबल कर दे और आप इससे हमेशा इनेबल मोड पर ही रखें फिर आप गूगल के ओर से दी जा रही सर्विस एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के माध्यम से अपने खोए हुए फोन को ट्रैक कर सकते हैं. इसके लिए आप गूगल में एंड्रायड डिवाइस मैनेजर लिखकर सर्च करे या यह लिंक डायरेक्ट यूआरएल में लिखे https://www.google.com/android/devicemanager और फिर अपने उसी जीमेल के ईमेल एड्रेस से लॉगिन करें जिसका प्रयोग आप प्ले स्टोर पर करते हैं. लॉगिन करते ही आपको आपके फ़ोन डिवाइस दिखेगी, जिसमें तीन ऑप्शन दिखेंगे. पहला, रिंग योर डिवाइस इसका प्रयोग आप अपने साइलेंट पर रखे फ़ोन को खोजने के लिए भी कर सकते हैं, यदि आपने अपना फ़ोन साइलेंट मोड में भी रखा होगा, तो भी आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो फुल वॉल्यूम में रिंग टोन बजेगी. दूसरा, यदि आपका फ़ोन कहीं खो गया है, तो ये गूगल मैप के माध्यम से यह बताएगा कि आपका फ़ोन अभी किस लोकेशन में है. साथ ही यहां पर ऐसे भी ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप अपने खोये हुए फ़ोन को आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से पासवर्ड लॉक कर सकते हैं, इसके बाद फोन नए पासवर्ड दर्ज करने के बाद ही दोबारा ऑन होगा. आपको एक ऑप्शन यह भी मिलेगा कि आप अपने फ़ोन में मौजूद जरुरी और निजी सामग्री और जानकारी को डिलीट भी कर सकते हैं या परमानेंटली लॉक कर सकते हैं.

आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम

आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक ऐप का इस्तेमाल करके यूजर्स अपने फोन की ट्रैकिंग और लॉकिंग की सेटिंग्स बदल सकते हैं. Find My iPhone (iOS) नाम का यह ऐप एप्पल आईट्यून स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में आईओएस 5 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. इसके साथ ही ऐप का इस्तेमाल करने के लिए एप्पल की icloud सर्विस का इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा. यह सर्विस www.iCloud.com से डाउनलोड की जा सकती है. इस सर्विस को आईफोन में डाउनलोड करने के बाद अपने फोन से एप्पल आईडी बनानी होगी. इसके बाद जब भी आपका फोन खो हो जाए या चोरी हो जाए तो वापस एप्पल की icloud सर्विस से लॉग इन होते ही Find my iPhone पर क्लिक करना होगा. ऐसा करते ही वेबसाइट आपके फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेगी और इस सर्विस की मदद से खोए हुए अपने फोन का सभी डाटा डिलीट किया जा सकता है.

विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम

विंडोज फोन में मौजूद एंटी थेफ्ट फीचर को भी फाइंड माई फोन कहा जाता है इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको www.windowsphone.com पर जाकर साइन इन करना होगा. साइन इन करने के लिए उसी विंडोज लाइव आईडी का इस्तेमाल करना होगा, जिसके जरिए फोन में लॉगइन किया गया था. फोन में ब्राउजर साइन इन करते ही फोन की लोकेशन गूगल मैप्स के जरिए डिस्प्ले करने लगेगा, ऐसे में खोए हुए फोन को ट्रैक करना ज्यादा आसान हो जाएगा, फोन की लोकेशन का प्रिंटआउट भी निकाला जा सकता है. ब्राउजर की मदद से आप अपने विंडोज फोन को रिंगिंग मोड पर भी डाल सकते हैं. अगर फोन कहीं दूर है या खो गया है तो उसका पासवर्ड लॉक भी कर सकते हैं, जिससे की कोई दूसरा उसका प्रयोग ना कर सके.

ब्लैकबेरी स्मार्टफोन

ब्लैकबेरी का एंटी-थेफ्ट प्रोग्राम BlackBerry Protect कहलाता है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यह सॉफ्टवेयर भी ब्लैकबेरी अकाउंट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है. अकाउंट की मदद से फोन में मैसेज भेजे जा सकते हैं. उन्हें लॉक किया जा सकता है, कहीं दूर बैठे हुए फोन का सारा डाटा डिलीट किया जा सकता है. ब्लैकबेरी प्रोटेक्ट की एक खास बात यह भी है कि एक अकाउंट के जरिए 7 अलग-अलग डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है. आज कल बाजार में बहुत से अलग-अलग थर्ड पार्टी ऐप्प भी मौजूद हैं, जिसके माध्यम से आप अपने खोए हुए फोन को खोजने, लॉक करने, या डाटा डिलीट करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं. उनमें से एक गूगल लैटिट्यूड क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्विस है जिसे आईओएस, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, सिंबियन और विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इस ऐप की मदद से जहां भी आपका स्मार्टफोन मौजूद होगा उसकी जानकारी गूगल मैप्स के जरिए मिलेगी. इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स कई बार बैटरी ज्यादा खर्च होने की शिकायत जरूर कर चुके हैं, लेकिन इस ऐप से कई बार फोन की असली लोकेशन की जानकारी बड़े ही सटीक ढ़ंग से मिलती है. ऐसे ही कुछ अन्य एप्स हैं Where's My Droid, Plan B, Android Lost Free, SeekDroid Lite, AntiDroidTheft, Cerberus, Prey, Lookout Mobile Security.

फ़ोन चाहे कोई सा भी हो या आप कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हों, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए और उसका इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम उस डिवाइस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे. ■

smart7973@gmail.com

सोनी का एक्सपीरिया जेड3+ स्मार्टफोन

सोनी ने एक्सपीरिया जेड4 का ग्लोबल वेरियंट एक्सपीरिया जेड3+ प्लस लॉन्च कर दिया है. एक्सपीरिया जेड3+ डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स के मामले में एक्सपीरिया जेड4 से काफी हद तक मिलता-जुलता है. कम्पनी इसे एक स्लिम, स्लीक और स्टाइलिश हाई परफॉर्मिंग स्मार्टफोन बता रही है. ऐंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप आधारित सोनी एक्सपीरिया जेड3+ में 5.2 इंच की फुल एचडी स्क्रीन है जो 1080x1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. ट्राइल्यूमिनस स्क्रीन है जिसके साथ एक्स-रिऐलिटी नाम का मोबाइल पिक्चर इंजन कपल्ड है. दूसरे फ्लैगशिप्स की तरह जेड3+ में भी 64 बिट ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर है. इसके साथ 3जीबी रैम को कपल किया गया है. यह हैंडसेट मेटल फ्रेम में है. एक्सपीरया जेड3+ में 20.7 मेगापिक्सल ऑटोफोकस प्राइमरी कैमरा है. इस कैमरे में 1/2.3 इंच एक्समोर आरएस बीएसआई सेंसर, बायॉन्ज़ इमेज प्रोसेसर, और एक पल्स्ड लेड फ्लैश है. सोनी एक्सपीरिया जेड3+ में 5 मेगापिक्सल फ्रंट-फेसिंग कैमरा है. इसमें 25एमएम का वाइड-ऐंगल लेंस भी लगाया गया है. इस हैंडसेट में 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128 जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकता है. इस फोन में 2930 एमएएच की बड़ी बैटरी दी गई है. ■

आईबॉल ने उतारा आईबॉल स्लाइड आई701 टैबलेट

अगर आप के पास बजट कम है और आप कम बजट में अच्छा टैबलेट खरीदना चाहते हैं, तो आपके खुशखबरी है. आईबॉल ने अपना नया टैबलेट आईबॉल स्लाइड आई701 लॉन्च किया है. विंडोज सिस्टम पर चलने वाला ये टैबलेट बेहद दमदार है. यह फोन विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि इसे बाद मेंविंडोज 10 में भी अपग्रेड किया जाएगा. विंडोज 10 इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है. इसमें एक साल के लिए फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब्सक्रिप्शन है और 1टीबी का ऑन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज भी. इस टैबलेट में क्वॉड कोर इंटेल एटम प्रोसेसर और 1जीबी रैम भी है. साथ ही 16 जीबी इनबिल्ट मेमोरी भी मिलेगी. इसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 0.3 मेगापिकस्ल का फ्रंट कैमरा. इस टैबलेट की बैटरी 3200 एमएएच की है. इसकी कीमत सिर्फ 4,999 रुपये है. ■

जियोनी ईलाइफ ई8 में 100 मेगापिक्सल का कैमरा

जियोनी ईलाइफ ई8 नाम से एक ऐसा स्मार्टफोन उतारने जा रही है, जिसमें 100 मेगापिक्सल कैमरे की तकनीक उपलब्ध होगी.

जियोनी ईलाइफ ई8 में लॉसलैस जूम सेंसर तकनीक के साथ 23 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. यह तकनीक 4के, क्वालिटी के वीडियो और 100 मेगापिक्सल क्वालिटी वाली तस्वीरें शूट करने में समर्थ है. जियोनी ईलाइफ ई8 में 4.6 इंच क्यूएचडी 1440x2560 रेजोल्यूशन एमओएलइडी डिस्प्ले दिखाया गया है. डिवाइस अमीगो यूआई पर आधारित एंड्रायड 5.0 लॉलीपॉप पर चलती है, इसमें 2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर प्रोसेसर 3जीबी रैम के साथ उपलब्ध है. यह स्मार्टफोन 2जी, 3जी, 4जी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. ईलाइफ ई-8 के लिए अन्य स्पेसिफिकेशन जो लिस्ट किए गए है वो है- 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन में 3520एमएएच की बैटरी है. ■

महिंद्रा की एसयूवी 500 हुई लॉन्च

महिंद्रा ने एसयूवी 500 के नए मॉडल को भारत में लॉन्च किया है. इस दमदार गाड़ी के जो अलग अलग वेरिएंट बाजार में उपलब्ध होंगे. नई महिंद्रा एसयूवी 500 नए डिजाइन और खूबियों के साथ बाजार में आई है. इसमें आगे और पीछे के बंपर को नया डिजाइन दिया गया है. साथ ही गाड़ी की विंडो और हेडलाइट को भी नया रूप दिया गया है. इसके अलावा धुंध के लिए अलग तरह की लाइट, अलोय व्हील और साथ ही दो नए कलर पर्ल व्हाइट और सनसेट ऑरेंज भी बाजार में उतारे गए हैं . गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर को भी नए अंदाज में पेश किया गया है. गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हुई प्लास्टिक की क्वालिटी भी पहले से बेहतर है और एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हुए बड़े टचस्क्रीन भी दिए गए हैं. रिवर्स पार्किंग कैमरा और गाइडलाइन सेन्सर भी दिए गए हैं. हाईएंड मॉडल में ड्राइवर की सीट को पावर एडजस्ट किया जा सकता है साथ ही सनरूफ भी दी गई है. इसका इंजन 2.2 लीटर का है जो 140पीएस की पावर देने में सक्षम है. अब गाड़ी की पावर डिलीवरी और स्मूथ हो गई है. इसकी कीमत 11.21 लाख से 14.99 लाख तक है. ■

धोनी ने मांगे 60 करोड़ तो मिल्खा सिंह ने सिर्फ 1 रुपये!

कैप्टन कूल धोनी की भी बायोपिक बन रही है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. आईपीएल-8 के दौरान कई मैचों में स्टेडियम में दिखे सुशांत का लुक धोनी जैसा ही था. ये फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज हो सकती है.

भाग मिल्खा भाग और मैरी कॉम जैसी फिल्मों की सफलता के बाद अब कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज पर फिल्म में बन रही हैं. कुछ दिनों पहले ही पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बन रही फिल्म अजहर का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है. इसमें एक्टर इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा कैप्टन कूल धोनी की भी बायोपिक बन रही है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. आईपीएल-8 के दौरान कई मैचों में स्टेडियम में दिखे सुशांत का लुक धोनी जैसा ही था. ये फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज हो सकती है. खबरों के अनुसार इस फिल्म के लिए धोनी ने 80 करोड़ रुपये मांगे हैं. खबर है कि टीम इंडिया के सबसे चर्चित क्रिकेटर धोनी ने अपनी लाइफ पर फिल्म बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये रॉयल्टी की डिमांड की है.

इसमें फिल्म की कमाई के शेयर भी शामिल हैं. सूत्रों की मानें तो धोनी को 10 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. वहीं, पूर्व क्रिकेटर मो. अजहरुद्दीन ने कितनी रॉयल्टी ली है, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकता कपूर के साथ कई मीटिंग्स के बाद अजहर ने अपनी लाइफ पर फिल्म बनाने की रजामंदी दी थी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

खेल पर लगातार काम करें खिलाड़ी : सचिन

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे बल्लेबाजों को विश्वस्तरीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए अपने खेल पर लगातार काम करना चाहिए और जब वह खेलते थे, तब लगातार ऐसा किया करते थे. तेंदुलकर ने कहा कि यह बल्लेबाज का कर्तव्य है कि वह अपने खेल पर काम करता रहे, क्योंकि ये विश्वस्तरीय गेंदबाज लगातार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. इस स्टार बल्लेबाज से पूछा गया कि लेसिथ मालिंगा की टखने को निशाना बनाकर फेंके गये यार्कर को कैसे खेलना चाहिए, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बाल नहीं बॉल (गेंद) को देखो. एक खिलाड़ी के रूप में दिल्ली के अपने दौरों की याद करते हुए तेंदुलकर ने कहा कि भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में मेरा पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिरोजशाह कोटला में खेला गया था और हमने वह मैच जीता था. तेंदुलकर ने अपना 35वां शतक भी दिल्ली में बनाया था. इससे उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा था और वह शतक भी उन्हें याद है. तेंदुलकर ने गुड़गांव के साइबर हब में प्रचार कार्यक्रम में कहा कि वह 2005 की बात है और हम श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे.■

सचिन का क्रेज बना अंजली का सिरदर्द

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर कार और स्पीड के प्रति कम उम्र से ही क्रेजी रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन एक बार उनके इसी शौक ने सचिन और उनकी पत्नी अंजली के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी. कुछ साल पहले जब सचिन इंग्लैंड में थे, तब बीएमडब्ल्यू कार की टेस्ट ड्राइव के दौरान उन्होंने इतनी तेज कार चलाई थी कि उनका और अंजली का दिन भर सिरदर्द होता रहा था. इसका खुलासा खुद सचिन ने हाल ही में एक गेम लॉन्च इवेंट के दौरान किया. सचिन के अनुसार बात कुछ साल पहले की है. हम इंग्लैंड में थे. बीएमडब्ल्यू वालों ने मुझे अपनी एक लिमिटेड एडिशन कार टेस्ट ड्राइव के लिए दी. उन्होंने मुझे फीडबैक देने के लिए कहा, खासकर ब्रेक्स के बारे में. तो इस ड्राइव पर चलने के लिए मैंने अंजली को भी मना लिया. मैंने ड्राइव शुरू की और स्पीड तेज कर दी. मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं किस स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था. चूंकि उन्होंने मुझे ब्रेक चेक करने के लिए कहा था इसलिए मैंने पूरी स्पीड में गाड़ी चलाई और फिर ब्रेक लगा दिया. वो जबरदस्त अनुभव था. मैंने और अंजली ने वो महसूस किया था. ये ऐसा अनुभव रहा, जो मुझे आज भी याद है.■

अभिनव बिंद्रा ने कटाया ओलंपिक का टिकट

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा म्यूनिख में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर रायफल फाइनल में 2016 रियो ओलंपिक गेम्स के लिए ओलंपिक का टिकट कटा लिया है. बिंद्रा ने जर्मनी के होचब्रुक में 1972 ओलंपिक शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर रायफल इवेंट में 627.5 का स्कोर किया. बिंद्रा देश के लिए रियो ओलंपिक का कोटा जीतने वाले चौथे भारतीय शूटर हैं. उनसे पहले पिस्टल शूटर जीतू राय और रायफल शूटर अपूर्वी चंदेला क्रमशः वर्ल्ड चैंपियनशिप और चोंगवोन वर्ल्ड कप में ओलंपिक कोटा जीत चुके हैं.■

भारतीय अंपायरों को नहीं मिलता सम्मानः टफेल

साइमन ने अपने साक्षात्कार में साफतौर पर कहा है कि भारतीय खिलाड़ी भी अपने घरेलू अंपायरों पर भरोसा नहीं रखते हैं और भले ही भारतीय अंपायर आईसीसी पैनल में न हों, लेकिन उनमें भरपूर क्षमता है और पिछले कुछ समय में इस दिशा में काफी तरक्की देखने को मिली है.

मैदान पर अपने सटीक निर्णय के लिये मशहूर अंतरराष्ट्रीय अंपायर साइमन टफेल ने कहा है कि भारतीय प्रशंसकों और खिलाड़ियों में घरेलू अंपायरों के लिये सकारात्मक रुख और भरोसे की कमी दिखती है, जिसे बदलने की जरूरत है. क्रिकेट में सबसे मजबूत टीमों में एक भारत और दुनिया के सबसे अमीर और रसूख वाले क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का इस खेल में भले ही सबसे अधिक दबदबा हो, लेकिन भारत का एक भी अंपायर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के एलीट अंपायर पैनल का हिस्सा नहीं है. साइमन ने अपने साक्षात्कार में साफतौर पर कहा है कि भारतीय खिलाड़ी भी अपने घरेलू अंपायरों पर भरोसा नहीं रखते हैं और भले ही भारतीय अंपायर आईसीसी पैनल में न हों, लेकिन उनमें भरपूर क्षमता है और पिछले कुछ समय में इस दिशा में काफी तरक्की देखने को मिली है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को देखकर निराशा होती है कि खिलाड़ियों और प्रशंसकों में ही अपने अंपायरों के प्रति सकारात्मक रुख नहीं है. आईसीसी अंपायर एंड परफॉर्मेंस प्रबंधक के तौर पर भारतीय अंपायरों को प्रशिक्षण दे रहे टोफल ने कहा कि घरेलू अंपायरों को अपने ही खिलाड़ियों से वह सम्मान नहीं मिलता, जो मिलना चाहिये.■

उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी-11 में जगह मिलेगी : सरफराज खान

आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबके दिलों पर राज करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) के सबसे युवा बल्लेबाज सरफराज खान का कहना है कि इस बार आईपीएल में इस बार दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों से सजी आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में जगह मिलने की उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह जरूर सोचा था कि जिस दिन मौका मिलेगा, अंतिम 11 में जगह पक्की कर लेंगे. 17 साल के सरफराज ने कहा कि क्रिस गेल, डीविलियर्स और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के बीच उन्हें प्लेइंग-11 में जगह मिलने का यकीन नहीं था और नंबर 6 की बेहद अहम जगह पर मौका दिए जाने से उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. सरफराज ने कहा कि आईपीएल का उनका पहला सत्र बहुत अच्छा रहा. इस दौरान सभी सीनियर खिलाड़ियों ने उनकी बहुत मदद की. आरसीबी की ओर से 50 लाख रुपये में खरीदे गये इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने का जल्दी किसी को मौका नहीं मिलता है. उस नंबर पर आम तौर पर सीनियर और अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है. मैं खुशनसीब हूं कि मुझे उस स्थान पर बल्लेबाजी का मौका मिला.■

वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर फ्लेचर गिरफ्तार

वेस्ट इंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर को यहां डोमिनिका एयरपोर्ट पर हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. 27 वर्षीय फ्लेचर अपनी घरेलू टीम विंडवर्ड आइलैंड के साथ डोमिनिका में अभ्यास करने आए थे. इसके बाद वह कहीं जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें अरेस्ट किया गया. टीम के मैनेजर लोकार्ट सेबस्टियन ने कहा कि मुझे फ्लेचर की गिरफ्तारी की जानकारी है और बतौर टीम मैनेजर मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए उनका समर्थन करूंगा. फ्लेचर वेस्ट इंडीज की ओर से कुल 15 वनडे मैच और कुल 75 टी20 मैच खेल चुके हैं. उन्होंने अपना आखिरी टी20 मैच इस वर्ष जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. इसके साथ ही, उनके खाते में प्रथम श्रेणी के 60 मैच भी दर्ज हैं.■

बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की पहली पसंद भारत

10 जून से टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक बांग्लादेश को भारत दौरा करने का मौका नहीं मिला है. साल 2000 में टेस्ट खेलने का दर्जा प्राप्त करने के बाद से करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक बांग्लादेश को यहां खेलने के लिए इनविटेशन नहीं दिया है. वहीं, बांग्लादेश के वनडे कप्तान मशरफे मुर्तजा ने भारत में खेलने की इच्छा जाहिर की है. भारत में खेलने के बारे में पूछे जाने पर एक इंटरव्यू के दौरान मुर्तजा ने कहा कि हम भारत में इंटरनेशनल सीरीज खेलना चाहते हैं. हम इसका इंतजार कर रहे हैं. हो सकता है कि एक वक्त हम भी भारत जाकर खेलें. बांग्लादेश ने भारत में अब तक मात्र तीन वनडे मैच खेले हैं, जबकि टेस्ट मैच एक भी नहीं खेला है. बांग्लादेश ने यहां 1990-91 में एशिया कप और 1998 में कोका-कोला ट्रायंगुलर सीरीज खेली थी.■

अभिताभ के खिलाफ एक करोड़ का केस

अभिताभ बच्चन हमेशा अपने चाहने वालों के साथ अपनी कविताएं और लेख शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस बार बिग बी एक कविता शेयर कर कानूनी मामले में फंस गए है. एक रिपोर्ट के मुताबिक महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट पर किसी विकास दूबे नाम के शख्स ने कोर्ट का कुत्ता नाम की एक कविता पोस्ट की और बिग बी ने इस कविता को विकास दुबे के नाम से ट्विटर और फेसबुक पर शेयर कर दिया और लिखा कि मेरे एक फॉलोवर विकास दुबे की एक और शानदार कथा. असल में यह कविता विकास दुबे नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) के यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जगबीर राठी की थी. जगबीर राठी ने जब अपनी कविता को किसी और के नाम से शेयर किए हुए पाया तो उन्होंने अमिताभ को इसकी सही जानकारी ई–मेल करके और ट्विटर, फेसबुक पर दी. लेकिन किसी के इस बारे में जवाब ना मिलने पर जगबीर राठी ने कानून का सहारा लिया. जगबीर राठी ने अमिताभ बच्चन को लीगल नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब और 1 करोड़ रुपये की मांग की है.■

मेरे अतीत से मुझे डराना सही नहीं है: सनी लियोनी

सनी लियोनी भले ही बॉलिवुड की सबसे पसंदीदा ऐक्ट्रेस बन चुकी हों, लेकिन पॉर्न स्टार वाला अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. सनी कई बार कह चुकी हैं कि बिग बॉस में आने से पहले ही उन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री से नाता तोड़ लिया था. इसके बावजूद, एक बार फिर उन्हें सफाई पेश करनी पड़ी. मामला मुंबई का है, जहां पिछले दिनों कथित तौर पर उन्हें फ्लैट में अश्लीलता फैलाने के चलते मकान मालकिन ने निकाल दिया था. इसके बाद, ठाणे पुलिस को बयान देने पहुंची सनी लियोनी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी. सनी लियोनी ने पुलिस से कहा कि उनके अतीत को वर्तमान से जोड़ना सही नहीं है.

पुलिस को दिए बयान में लियोनी ने कहा कि जो आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, वे तब की हैं जब मैं अमेरिका की पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी. बॉलिवुड का हिस्सा बनने के साथ ही मैंने उस इंडस्ट्री से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया है. मैं जब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं, तो मेरे अतीत से मुझे डराना सही नहीं है. दरअसल, मुंबई के डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज होने के 13 दिन बाद फिल्म स्टार सनी लियोनी बुधवार को ठाणे पुलिस कमिश्नर के सामने हाजिर हुई थीं. उन्होंने डीसीपी पराग मनेरे से मुलाकात की और फिर सायबर सेल के पीआई जगदीश सावंत ने उसका बयान दर्ज किया.■

प्रियंका ने रंगभेद की वजह से छोड़ा अमेरिका

देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वह अमेरिका में इस हद तक नस्लभेद की शिकार हुईं कि उन्हें अमेरिका छोड़ने का फ़ैसला करना पड़ा.

प्रियंका ने बताया कि जब वो 12 साल की थीं तब वो स्कूली पढाई करने के लिए अमेरिका गई थी लेकिन फिर कथित रंगभेदी भावनाओं से आहत होकर स्वदेश लौट गई थीं. प्रियंका कहती हैं कि मैंने ज़िन्दगी में बहुत नस्लभेद सहा है. मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे सब ब्राउनी कहकर बुलाया करते थे और लोग मुझे कहा करते थे कि घर जाओ और करी बनाओ. मैंने देखा था कि लोग भारतीयों को हमेशा एक अलग तरह से देखते थे. उनका कहना है कि हम भारतीय सिर हिलाकर बात करते हैं. हमारा मज़ाक उड़ाया जाता है. हम घर पर जो खाना बनाते हैं, उस खाने की महक का मज़ाक उड़ाया जाता है. और तो और हमारी विचार शैली का भी मज़ाक उड़ाया जाता है. इन्ही तानो से तंग आकर मैंने अमेरिका छोड़ा और भारत आ गई. प्रियंका अमरीका में दो से तीन साल रहीं. आज वो अमेरिका में एक हॉलीवुड प्रोडक्शन का हिस्सा है. प्रियंका के अनुसार उन्हें अमेरिका में बदलाव नज़र आता है. प्रियंका चोपड़ा इस समय अपने पहले हॉलीवुड धारावाहिक क्वान्टिको में एलेक्स वीवर नाम की एक एफ़बीआई एजेंट की भूमिका निभा रही हैं. यह पहला मौका है जब प्रियंका किसी हॉलीवुड टीवी सीरीज़ में काम कर रही हैं. प्रियंका ने कहा क्वान्टिको एफ़बीआई के ख़ास सदस्यों की कहानी है जो अलग–अलग वजहों और इरादों से एफ़बीआई से जुड़ते हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अनुष्का के फैन हुए रणवीर

अनुष्का शर्मा के पूर्व बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह एक बार फिर उनके फैन हो गए हैं. रणवीर मीडिया से लेकर ट्विटर तक पर अनुष्का के तारीफों के पुल बांध रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अनुष्का की तारीफ में कहा कि अनुष्का के साथ दिल धड़कने दो में काम करना बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा. वह बतौर ऐक्ट्रेस और बतौर इंसान काफी बेहतर हुई हैं. काफी समय बाद उनके साथ काम करना यादगार रहा. मैं यह बात कभी भुला नहीं सकता कि अनुष्का मेरी पहली कोस्टार हैं. मैंने अपनी डेब्यू फिल्म उनके साथ की थी. इसके बाद रणवीर ने फिल्म में अनुष्का के डांस नंबर गर्ल्स लाइक टू स्विंग शेयर करते हुए तारीफ कर डाली. अनुष्का स्टारर बैंड बाजा बारात से करियर की शुरूआत करने वाले रणवीर जोया अख्तर डायरेक्टेड फिल्म दिल धड़कने दो में एक बार फिर अनुष्का के साथ नजर आने वाले हैं. उन दिनों दोनों के क्लोजनेस की बातें होती थीं.■

सलमान को कटरीना की याद आई

अपनी अगली फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए कश्मीर लौटे सलमान को अचानक कटरीना की याद आ गई है. हालांकि, सलमान कश्मीर की खूबसूरती में कुछ जयादा ही गुम थे. कश्मीर की खूबसूरत वादियों से इम्प्रेस सलमान ने इसे सबसे अनोखी जगह बताते हुए कश्मीर को धरती का जन्नत बताया. उन्होंने कहा कि कश्मीर बहुत अमीर...प्राकृतिक संपदा के मामले में यह बहुत अमीर है... माशाअल्लाह माशाअल्लाह.

यह बोलते ही न जाने सलमान को अचानक क्या याद आया कि अगले ही मिनट उन्होंने यह भी कह डाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह से याद आया कि कटरीना कैफ भी कश्मीर से हैं. इतना ही नहीं कश्मीर की खूबसूरती पर फिदा सलमान ने रविवार को घाटी में सिनेमाघर दोबारा खोलने की वकालत भी की थी, जिसके बाद एक अलगाववादी संगठन ने उनपर कश्मीर में अश्लीलता फैलाने का आरोप तक लगा दिया है. सलमान यहां की खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो चुके हैं. ■

फिल्म रंगून में नज़र आएंगी कंगना

यह विशाल भारद्धाज का ड्रीम प्रोजैक्ट माना जा रहा है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और सैफ अली खान भी अनोखे किरदार में नजर आएंगे.

एक्ट्रेस कंगना रनोट अब विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून में सैफ अली खान और शाहदि कपूर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. यह फिल्म एक लव ट्रॉयएंगल की कहानी पर आधारित है. यह विशाल भारद्वाज का ड्रीम प्रोजैक्ट माना जा रहा है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और सैफ अली खान भी अनोखे किरदार में नजर आएंगे. विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म के बारे में कहा है कि यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और बड़े बजट के साथ–साथ इस फिल्म में मेरा सबसे बेहतरीन संगीत भी होगा. विशाल ने आगे कहा कि यदि आप मणिपुर के इंफाल में स्थित कब्रिस्तान या शमशान में जाकर देखें तो आपको बहुत सारे युवा सैनिकों की कब्र मिलेगी जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ लड़े थे. ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया था. तो इस फिल्म की कहानी दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है. शाहिद कपूर पहली बार कंगना रनोट के साथ नजर आएंगे. इसके अलावा विशाल भारद्वाज भी पहली बार कंगना के साथ काम करने जा रहे हैं. इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज मिलकर प्रोड्यूस करेंगे. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार झारखंड

08 जून –14 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

तीसरी ताकत की क़वायद

सरोज सिंह

सूबे में जनता परिवार के गठन और एनडीए के विस्तार की अटकलों के बीच एक नई तीसरी ताकत का गठन कर चुनावी जंग को और भी दिलचस्प बनाने की कवायद जोर–शोर से शुरू हो गई है. इस कवायद की शुरुआत इसलिए भी जरूरी हो गई क्योंकि बिहार की राजनीति अभी भी कई तरह के अगर और मगर में फंसी हुई है. आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं को भी यह साफ नहीं है कि चुनाव में उनकी लड़ाई किससे होनी है? हो सकता है आज जिसे वह दोस्त मान रहे हों वह कल दुश्मन के खेमे में नज़र आए. चूंकि चुनाव में वक्त काफी कम बचा है इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है और हर कोई यह चाह रहा है कि जल्द से जल्द तस्वीर साफ हो ताकि चुनावी जंग की तैयारी शुरू की जा सके. बस इसी पृष्ठभूमि में बिहार में एक तीसरी ताकत को मजबूत करने की तैयारी हो रही है. अभी तक यह मान कर चला जा रहा था कि सूबे में लड़ाई दो तरफा होगी मतलब एक तरफ जनता परिवार होगा और दूसरी तरफ एनडीए. लेकिन इसके अलावा एक तीसरी हवा भी चलने लगी है. सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने भी इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं. लालू प्रसाद दो तीन बातें बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं. वह कह रहे हैं कि पहला लक्ष्य भाजपा को रोकना है. वह यह भी कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू ने 145 सीटों का जो दावा किया है उसमें कुछ गलत भी नहीं है. इसके अलावा मांझी को साथ लेने की बात भी वह कर रहे हैं. अगर इन बातों को जदयू के नजरिये से देखें तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दो छोर पर नजर आते हैं. मांझी किसी भी हालत में नीतीष कुमार को स्वीकार नहीं है. 145 सीटों पर राजद का दावा भी जदयू को अव्यवहारिक लगता है. इसके अलावा जदयू यह भी चाहता है कि चुनाव नीतीश कुमार को नेता मानकर लड़ा जाए. अगर इन सब बातों को लेकर बात बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद चाहेंगे कि कांग्रेस, वामदल और जीतनराम मांझी को लेकर एक बड़ी तीसरी ताकत का गठन कर चुनावी अखाड़े में उतरा जाए. लालू प्रसाद को लगता है कि अगर इस तरह की कोई कहानी बन जाती है तो बिहार में भाजपा को वह चारों खाने चित कर सकते हैं. इसके पीछे राजद के रणनीतिकारों का तर्क है कि इस समीकरण में लालू प्रसाद का माय यानि की मुसलमान और यादव समीकरण पूरी तरह एकजुट हो जाएगा. जीतन राम मांझी और वाम दल के भी साथ आ जाने से महादलित और अतिपिछड़ा वोटों का भी मजबूत लाभ इस खेमे को मिल सकता है. इस तरह के समीकरण में अगड़ी जातियों के कुछ वोटों का फायदा भी सीट के हिसाब से लालू प्रसाद को मिल सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई मोर्चा बनता है तो इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी और लालू प्रसाद अपने लोगों को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि राजद ने लगभग सौ सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने का मन बनाया है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के गठबंधन को लालू प्रसाद अपने हिसाब से आसानी से अपने मन और मिजाज़ के हिसाब से चला सकते हैं. तीसरी ताकत की एक तस्वीर नीतीश कुमार भी बना सकते हैं. लालू प्रसाद से बात बिगड़ने की स्थिति में नीतीश कुमार कांग्रेस और पप्पू यादव के साथ मिलकर एक गठबंधन बना सकते हैं. पप्पू यादव इन दिनों खुले दिल से नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं. जदयू के रणनीतिकारों को लगता हैं कि सबसे अच्छी स्थिति तो लालू प्रसाद के साथ बड़ा मोर्चा है. अगर किसी वजह से बात नहीं बनी तो कांग्रेस और पप्पू यादव का साथ पार्टी की चुनावी नैया को पार लगा सकता है. व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार अभी भी बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता है. जदयू चाहती है कि नीतीश के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने से बात बन सकती है. इसलिए प्लान बी के तहत इस संभावना को खुला रखा गया है. इस खेमे को वामदलों का भी साथ मिलने की उम्मीद है. तीसरी ताकत की इन दो तस्वीर के अलावा जो तीसरी तस्वीर उभर रही है उसके मुख्य किरदार पप्पू यादव और जीतनराम मांझी हैं. जानकार बताते हैं कि पप्पू यादव और जीतनराम मांझी आगे की राजनीति के मद्देनजर चाहते हैं कि चुनावी जंग में अकेले ही उतरा जाए ताकि संगठन को मजबूत बनाने का मौका मिल सके. दोनों नेता खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि 2015 की लड़ाई में उनके लिए संभावना, खासकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की, कम है. इसलिए इस चुनाव में वह अपनी ताकत को मजबूत करने और अपने–अपने संगठन का विस्तार करने के लिहाज से उपयोग में लाना चाहते हैं. दोनों नेता जानते हैं कि अभी उनकी ताकत किसी को बनाने की है, खुद बनने की नहीं है इसलिए जितना हो सके इसका फायदा उठाने के अवसर खोजे जाएं. सूत्रों पर भरोसा करें तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर भाजपा या लालू प्रसाद के साथ जीतन राम मांझी की बात नहीं बनी तो पप्पू यादव के साथ मिलकर मांझी तीसरी बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे. दोनों नेता पहले से ही एक दूसरे के काफी करीब हैं. दोनों को भरोसा है कि चुनाव टिकट से वंचित बहुत सारे नेता टिकट के लिए उनका दामन थाम सकते हैं. पप्पू यादव को भरोसा है कि कांग्रेस उनका साथ दे सकती है. हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी कहते हैं कि हमने सारे विकल्प खुले रखे हैं और किसी भी फैसले के लिए जीतन राम मांझी को अधिकृत कर दिया गया है. बिहार की जनता हमारी तरफ देख रही है और हम हर हाल में सूबे में एक मजबूत विकल्प देंगे और सरकार बनाएंगे. लालू और नीतीश को भगोड़ा सेनापति बताते हुए शकुनी चौधरी कहते हैं कि भाग रही सेना से क्या लड़ना? उन्होंने तो पहले ही हार मान ली है. हम सूबे में एक बेहतर विकल्प देंगे यह तय है. इधर हम से जुड़े साधू यादव चाहते हैं कि तीसरी ताकत की लड़ाई गरीब जनता दल के बैनर तले लड़ी जाए. गौरतलब है कि जीतनराम मांझी और पप्पू यादव के मोर्चे को अभी चुनाव आयोग से राजनीतिक दल की मान्यता नहीं मिली है. साधू यादव ने मांझी को न्योता दिया है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं और इसी पार्टी के बैनर तले चुनावी अखाड़े में उतरें. जानकार बताते हैं कि अगर चुनाव आयोग ने मांझी के हम को राजनीतिक दल के तौर पर जल्द मान्यता नहीं दिया तो मांझी साधू यादव के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. इधर भाजपा ने मांझी और पप्पू यादव के लिए दरवाजा खुला रखने का संकेत देकर एनडीए के विस्तार की इच्छा जताई है. इसी संदर्भ में जीतनराम मांझी नरेंद्र मोदी से भी मिल आए हैं. इसलिए मौटे तौर पर यह साफ है कि हर दल और नेता ने अपना प्लान बी तैयार कर रखा है और जैसे ही सूबे की राजनीति से अगर और मगर पर से परदा हटेगा तीसरी ताकत की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखने लगेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

लालू प्रसाद दो तीन बातें बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं. वह कह रहे हैं कि पहला लक्ष्य भाजपा को रोकना है. वह यह भी कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू ने 145 सीटों का जो दावा किया है उसमें कुछ गलत भी नहीं है. इसके अलावा मांझी को साथ लेने की बात भी वह कर रहे हैं. अगर इन बातों को जदयू के नजरिये से देखें तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दो छोर पर नजर आते हैं. मांझी किसी भी हालत में नीतीष कुमार को स्वीकार नहीं है. 145 सीटों पर राजद का दावा भी जदयू को अव्यवहारिक लगता है. इसके अलावा जदयू यह भी चाहता है कि चुनाव नीतीश कुमार को नेता मानकर लड़ा जाए. अगर इन सब बातों को लेकर बात बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद चाहेंगे कि कांग्रेस, वामदल और जीतनराम मांझी को लेकर एक बड़ी तीसरी ताकत का गठन कर चुनावी अखाड़े में उतरा जाए. लालू प्रसाद को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार में भाजपा को वह चारों खाने चित कर सकते हैं.

एक नज़र

गठबंधन नहीं होगा लाभकारी

जनता परिवार के विलय और गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रालोसपा युवा नेता अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि एनडीए के समक्ष यह गठबंधन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जनता उनकी चाल समझ चुकी है. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के डर से जनता परिवार के नेताओं ने हाथ मिलाया है. जबकि आजतक इन दलों के नेता एक-दूसरे का विरोध करते रहे हैं. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और विलय से जुड़े मुद्दों पर सूबे की जनता को इन नेताओं ने कन्फ्यूज कर रखा है. अमरेन्द्र सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की छवि के बारे में कहा कि विलय से लूटपाट चोरी, अपराध, अपहरण जैसी समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है. बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमे सत्ता दल जदयू के शीर्ष नेता और राज्य के मुखिया नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में केन्द्रित दो दलों के विलय के इच्छुक है क्योंकि इनकी पार्टी का बंटाधार होनेवाला है.

– रजनीकांत पाण्डेय

मंत्री ने दी सांत्वना

केन्द्र सरकार के पेयजल व स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भूकम्प से पीड़ितों एवं मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया. उन्होंने मोतिहारी परिसदन में प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि इसके लिए केन्द्र सरकार तत्पर है. उन्होंने कहा कि भूकम्प से मरने वालों को अभी तक चार लाख रुपये मिल चुके हैं. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी को पक्का घर देगी अगर इसके लिए राज्य सरकार भूमि दे. साठ प्रतिशत लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे शौच करते है इसके लिए केन्द्र सरकार दृढ़ संकल्पित है और 2020 तक सभी को शौचालय निर्माण करा देगी. इसके लिए बड़े पैमाने पर शौचालय एवं पेयजल के लिए दी जाएगी. वह तब ही संभव होगा जब केन्द्र और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करेंगी. उन्होंने कहा कि वर्षा के कारण हुई फसल क्षति का जायजा लेने केन्द्र सरकार की टीम पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट केन्द्र सरकार तक पहुंच चुकी है. किसानों को संकट से निपटाना केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों का काम है. इस बार बिहार में भाजपा की ही सरकार बनेगी. इसे कोई नहीं रोक सकता. मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनिल मणि तिवारी, राजेन्द्र गुप्ता, महेश्वर सिंह, अरुण गुप्ता, सुरेश सहनी, डॉ. लालबाबू, राजा ठाकुर, मोहिबुल हक, अरुण यादव, पंकज कुमार सिन्हा सहित अनेक नेता उपस्थित थे.

– इंतेजारुल हक

विकलांगो को मिले कृत्रिम अंग

गया की रेड क्रास सोसायटी में आयोजित विकलांगता शिविर में जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने 125 विकलांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए. इस अवसर पर डीएम ने कहा कि मगध की धरती को विकलांगता विहिन करने का संकल्प लिया गया है. उन्होंने कहा कि जिस भी विकलांग को कृत्रिम अंग की जरूरत है, वे रेडक्रास में निबंधन कराये, उन्हें कृत्रिम अंग दिये जाएंगे. डीएम ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि रेडक्रास में विकलांगो को भेजकर निबंधन करायें और उन्हें कृत्रिम अंग तथा पेंशन देने की व्यवस्था करें. डीएम ने शिविर के आयोजन के लिए राजस्थान के सीकर नागरिक परिषद, महावीर सेवा सदन, रूपा फाउंडेशन तथा रेडक्रॉस सोसायटी गया को धन्यवाद दिया. इस अवसर पर कृत्रिम अंग प्राप्त करनेवाले विकलांगों ने भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया.

बेगूसराय

साहेबपुर कमाल में बिछने लगी बिसात

सुरेश चौहान/पंकज झा

जमशेद अशरफ

राकेश कुमार

श्रीनारायण यादव

बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधान सभा क्षेत्र में आगामी विधान सभा का चुनाव काफी दिलचस्प होगा. राजद, भाजपा, माले एवं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच चुनावी दंगल होने का आसार है. वर्तमान में साहेबपुरकमाल विधान सभा सीट राजद की झोली में है और राजनीति के माहिर खिलाड़ी सूबे के पूर्व नगर विकास मंत्री श्रीनारायण यादव यहां के विधायक हैं. गत विधान सभा चुनाव में यह सीट जदयू के पास रहा था. प्रदेश के पूर्व मंत्री परवीन अमानुल्लाह यहां की विधायक थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद होने के कारण परवीन अमानुल्लाह ने मंत्री, विधायक एवं जदयू की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया. रिक्त हुए विधान सभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ. इस उप चुनाव में भाजपा-लोजपा-रालोसपा गठबंधन ने भाजपा के शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया. अमर कुमार सिंह विधान सभा उप चुनाव के समय जद यू से पाला बदल भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा ने उन्हें इस उप चुनाव में अपने गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया. दूसरी ओर राजद ने अपने पुराने सिपहसलार श्रीनारायण यादव को चुनावी मैदान में उतारा. इस उप चुनाव में राजद के श्रीनारायण यादव 33018 मत प्राप्त कर विजयी हुए. भाजपा गठबंधन प्रत्याशी अमर कुमार सिंह 25726 मत प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहे. क्षेत्र के पूर्व जदयू सांसद मोनाजिर हसन की पत्नी जदयू प्रत्याशी शबनम परवीन 21869 मत प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहीं.

साहेबपुरकमाल विधान सभा क्षेत्र में राजद की स्थिति अच्छी है. राजद के श्रीनारायण यादव यहां के विधायक हैं. आगामी विधान सभा चुनाव में भी श्रीनारायण यादव ही राजद के एकमात्र सशक्त दावेदार हैं. क्षेत्र में श्रीनारायण यादव के कलेवर का राजद में कोई दूसरा नेता नहीं है. भाजपा के जमदेश अशरफ एवं शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार प्रमुख दावेदार हैं. लेकिन ये दोनों संभावित प्रत्याशी दलबदलू हैं. शशिकांत कुमार साहेबपुरकमाल विधान सभा के उप चुनाव से पूर्व जदयू से नाता तोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और वे भाजपा-लोजपा-रालोसपा गठबंधन के प्रत्याशी बनाये गए और द्वितीय स्थान पर रहे. जमशेद अशरफ लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से भाजपा में आए. नामचीन उद्योगपति जमशेद अशरफ लक्ष्मी की चकाचौंध के बल पर राजनीति में अपना भाग्य आजमाने के लिए सूरजभान सिंह के जरिये लोजपा की सदस्ता ग्रहण की. तत्कालीन बलिया विधान सभा चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी बने लेकिन दाल नहीं गली. फिर उन्होंने लोजपा से नाता तोड़ जदयू का दामन थामा और पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और विजयी हुए. नीतीश कुमार सरकार में जमशेद अशरफ निबंधन एवं आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाए गए. नीतीश कुमार से मनमुटाव होने पर मंत्री पद खोना पड़ा. गत विधान सभा चुनाव में जदयू से नेह तोड़ कांग्रेस से नाता जोड़ा. पार्टी ने उन्हें तेघड़ा विधान सभा सीट से प्रत्याशी बनाया. लेकिन वे जीत नहीं पाए. विधायक बनने की ललक या अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए जमशेद अशरफ कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है. संभावना है कि भाजपा अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए आगामी विधान सभा चुनाव में साहेबपुरकमाल विधान सभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाए. इस विधान सभा क्षेत्र में कभी कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी. लेकिन पार्टी के अन्दर व्याप्त गुटवाजी ने इसे ले डुबोया. आगामी विधान सभा चुनाव में पार्टी के पूर्व विधायक शमशू जोहा पूर्व प्रत्याशी राकेश कुमार एवं रविन्द्र कुमार सिंह में से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है. इस विधान सभा क्षेत्र में भाकपा (माले) की स्थिति जिले में सबसे अच्छी है. किसान, मजदूर एवं आम जनता की समस्याओं को लेकर माले ने जर्वदस्त जन आन्दोलन, धरना, प्रदर्शन का आयोजन कर क्षेत्र में अपनी गहरी पैठ बना ली है. आगामी विधान सभा चुनाव में माले भी अपना प्रत्याशी दे सकता है. चन्द्रदेव वर्मा या दिवाकर को प्रत्याशी बनाया जा सकता है. यदि राजद-जदयू का विलय हो जाता है या राजद-जदयू-कांग्रेस-भाकपा का गठबंधन बनता है तो राजद के वर्तमान विधायक श्रीनारायण यादव गठबंधन के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं. भाजपा-लोजपा- रालोसपा गठबंधन से भाजपा के जमशेद अशरफ को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है. यदि ऐसा होता है तो श्रीनारायण यादव एवं जमशेद अशरफ में कांटे का संघर्ष होगा और चुनाव परिणाम गठबंधन धर्म के निर्वहन पर निर्भर करेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

प्राथमिकी दर्ज होते ही भूमिगत हुए आरोपी प्राचार्य

सुनील सौरभ

तत्कालीन कुलपति प्रो. अरुण कुमार ने प्राचार्यों की नियुक्ति को सही ठहराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को वैधानिक रूप से जायज ठहराने के लिए कुलधिपति सह राज्यपाल को पत्र भी लिखा था. जिसमें डॉ. दलवीर सिंह को अल्पसंख्यक बताते हुए प्राचार्य पद पर नियुक्ति की गयी थी. जबकि इस नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है.

मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति में अनियमितता पर पटना हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद आरोपी बने सभी प्राचार्य छुट्टी लेकर भूमिगत हो गये हैं. ये सभी प्राचार्य ऐसे हैं जिन्हे तत्कालीन कुलपति अरुण कुमार ने नियुक्त किया था, लेकिन उन्हें वर्तमान कुलपति प्रो. एम. इश्तेयाक ने कॉलेजों में पदस्थापित किया था. इससे पूर्व 22 प्राचार्यो की नियुक्ति में भी तत्कालीन कुलपति अरुण कुमार ने बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतते हुए नियुक्ति की थी. यह मामला भी पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है. फिलहाल 15 प्राचार्यों समेत तत्कालीन कुलपति अरुण कुमार, रजिस्ट्रार डीके यादव समेत 25 लोगों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किये गये प्राथमिकी मे नामजद किया गया है. इनमें से अधिकांश लंबी छुट्टी लेकर भूमिगत हो गये हैं. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चयनित प्राचार्यो में वेंटिग फॉर पोस्टिंग मे रखे गये डॉ. ब्रजेश राय, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक हैं, विश्वविद्याालय आकर कार्य कर रहें हैं. बताया जाता है कि तत्कालीन कुलपति अरुण कुमार ने कुलपति का प्रभार मिलते ही मगध विश्व विद्यालय में अनियमितताओं तथा गड़बड़ी का सिलसिला आरंभ कर दिया था. क्योंकि तत्कालीन कुलाधिपति का चहेता कुलपति उन्हें कहा जाता था. अरुण कुमार के कार्यकाल में ही दो बार प्राचार्यो की नियुक्ति हुई और बड़े पैमाने पर चांदी के जूते की मार पर नियम-कानून को ताक पर रख दिया गया. दोनों बार की गयी नियुक्ति में चार ऐसे लोग हैं, जिनपर दोनो बार प्राथमिकी दर्ज हुई है. जिनमें पूर्व कूलपति अरुण कुमार, पूर्व कुलसचिव डॉ. डी.के.यादव, बैठक शाखा के प्रभारी एमएस इस्लाम, वरीय प्राचार्य सह चयन समिमि के सदस्य डॉ. श्रीकांत शर्मा को दोंनो बार नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

तत्कालीन कुलपति प्रो. अरुण कुमार ने प्राचार्यों की नियुक्ति को सही ठहराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को वैधानिक रूप से जायज ठहराने के लिए कुलधिपति सह राज्यपाल को पत्र भी लिखा था. जिसमें डॉ. दलवीर सिंह को अल्पसंख्यक बताते हुए प्राचार्य पद पर नियुक्ति की गयी थी. जबकि इस नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है. इसी प्रकार पटना हाई कोर्ट के अपर महाधिवक्ता के मंतव्य को गलत अर्थ देकर प्राचार्य बहाली का विज्ञापन जारी किया गया था.

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया कि शिक्षा विभाग को प्राचार्य नियुक्ति के मामले में अंधेरे मे रखा गया, सिंडीकेट की बैठक गैरकानूनी तरीके से बुलाकर चयन समिति का गठन कर दिया गया. डॉ. श्रीकांत शर्मा प्राचार्यो के वरीय कतार मे 5वें नम्बर पर थे. पहले नम्बर वाले की नियुक्ति नहीं कर डॉ. शर्मा को कर दिया गया. डॉ. शशि प्रताप शाही वरीय कतार में छठवें नम्बर पर थे. पहली कतार वाले को छोड़ कर उन्हें नियुक्त किया गया. इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए दर्ज की गई प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 193, 409, 420, 467, 471, 120 वीं, 201/34 तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7,13(2),13(1)(डी) और 12 लगायी गयी है. प्राथमिकी में नामजद किये गये में शामिल हैं-मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सह चयन समिति के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार, तत्कालीन कुलसचिव डीके यादव, तत्कालीन उप कुलसचिव मोहम्मद फहीमउद्दीन, तत्कालीन बैठक पदाधिकारी शमसुल इस्लाम, सामान्य शाखा के सहायक यूएन सहाय, सदस्य चयन समिती डॉ. कुमारेश प्रसाद सिंह, समिती विशेषज्ञ डॉ. दुर्गा प्रसाद गुप्ता और नरेन्द्र कुमार राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य वालेश्वर पासवान, चयन समिति सदस्य सुधीर कुमार मिश्रा, प्रो श्रीकांत शर्मा, प्राचार्य पद नियुक्ति किये गये प्रवीण कुमार, शीला सिंह, वेद प्रकाश चतुर्वेदी, अरुण कुमार रजक, इन्द्रजीत प्रसाद राय, रेखा कुमारी, उपेन्द्र कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद सिंन्हा, डॉ. पूनम, डॉ. उषा सिन्हा, डॉ. शशि प्रसाद शाही, डॉ कृष्णनन्दन प्रसाद , डॉ. ब्रजेश राय और डॉ. दलवीर सिंह. निगरानी की कारवाई से सभी आरोपी भूमिगत हो गये है. वहीं कॉलेजों मे पठन-पाठन पुरी तरह ठप हो गया है. प्राचार्य बहाली में गड़बड़ी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक आरोपी शमसुल इस्लाम के बारे में बताया जाता है कि बीए पास में से हैं. आगे की डिग्री किसी तरह लेकर प्राचार्य बन गये और गया कॉलेज में वर्तमान कुलपति ने पदस्थापन भी कर दिया. कुछ लोगों ने प्राचार्य बहाली में गड़बड़ी होने और उन्हें जानने के बाद भी प्राचार्यो को पदस्थापन करने पर वर्तमान कुलपति को भी इस मामले में आरोपी बनाने की मांग कर रहें हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

जाति-पार्टी पर भारी हो सकती है गुटबाजी

2015 के विधान परिषद व विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी जिले में राजनीतिक चहलकदमी बढ़ गयी है. दोनों ही चुनाव के संभावित प्रत्याशियों ने अपने-अपने स्तर से चुनावी अभियान का अघोषित तौर पर श्रीगणेश कर दिया है. कोई दलगत समर्थन के बूते चुनावी मैदान में ताल ठोंकने को आतुर है तो कोई धनबल व बाहुबल के भरोसे पर ऐंठ रहा है. विधान परिषद चुनाव में पंचायत व नगर निकाय के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है तो विधानसभा में आम मतदाताओं का निर्णय सर्वोपरि होता है. परंतु दोनों चुनाव के लड़ाई का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाता है. विधान परिषद चुनाव में जहां खरीद फरोख्त की परंपरा सर्वविदित है, वहीं विधानसभा में दलगत, जातिगत आधार के साथ पैसा के खेल अब आम हो गया है. यह अलग बात है कि चुनाव आयोग की सख्ती के बाद वोटों के सौदागर की परेशानी कुछ बढ़ गयी है. बावजूद इसके चुनावी तैयारी में पैसों का खेल अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है.....

वाल्मीकि कुमार

अर्जुन राय

बैद्यनाथ प्रसाद

देवेशचंद्र ठाकुर

दिलीप राय

डॉ रंजू गीता

गुड्डी देवी

जयनंदन प्रसाद यादव

नगीना देवी

नवल किशोर राय

राजेश चौधरी

राम कुमार शर्मा

राम नरेश प्रसाद यादव

सीताराम यादव

सुनील कुमार पिंटू

सूर्यदेव राय

सूबे बिहार की राजनीति में चल रही उलट-पलट ने दलगत संभावित प्रत्याशियों से लेकर आम मतदाताओं तक का मानसिक संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया है. सत्ता की चाह में बैठे पार्टी नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में नैतिकता को ताक पर रखने में कोई कसर नही छोड़ी है. कल तक साथ रहने वाले दल के नेता अब एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज नहीं कर रहे है. इतना ही नहीं चुनाव में एक दूसरे को सबक सिखाने का दंभ भरते हुए क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराने लगे है. यह सबकुछ खास तौर से भाजपा व जदयू के बीच उत्पन्न राजनीतिक तनाव व तकरार के बाद खुल कर सामने आने लगा है. पिछले चुनाव में एक साथ जंगल राज से मुक्ति व बिहार के विकास के संकल्प के साथ सत्ता की चौखट चूमने वाली भाजपा व जदयू अब एक दूसरे को औकात दिखाने के मूड में है. इतना ही नहीं राजद सुप्रीमो को जंगलराज का सेनापति की उपाधि देने वाली जदयू फिलहाल राजद के साथ मिलकर चुनाव में भाजपा को किनारे लगाने की जुगत कर रही है. यह बात अलग है कि प्रयास के बाद भी कतिपय कारणों से दोनों ही दल के बीच तालमेल की संभावना नहीं बन पा रही है. दूसरी ओर आम मतदाताओं में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गयी है कि जब पार्टी नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर तुले हैं तब मतदाताओं को किसी भी नेता के झांसे में आने से बचना चाहिए. मताधिकार का प्रयोग अपनी मर्जी से करने का मन बना लेना चाहिए. कारण कि अब का राजनीतिक साथी का सफर अगली बार फिर कहां और किस मंजिल पर होगा कहना मुश्किल हो गया है. चुनावी मौसम की दस्तक के साथ ही सीतामढ़ी में जातिगत, दलगत बयार के साथ गुटबाजी का दौर भी चर्चा का केंद्र बनने लगी है. राजनीतिक गलियारा में पैठ रखने वालों की माने तो अबकी बार चुनाव में जाति - पार्टी के साथ ही राजनीतिक गुटबाजी का खेल की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है.

भारत - नेपाल सीमा पर अवस्थित सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें एक बेलसंड विधानसभा क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है. वर्तमान में सीतामढ़ी, रीगा, परिहार व बथनाहा विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है. इस क्षेत्र से क्रमश: सुनील कुमार पिंटू, मोतिलाल प्रसाद, राम नरेश प्रसाद यादव व दिनकर राम विधायक है. जबकि बाजपटटी, सुरसंड, बेलसंड व रुन्नीसैदपुर सीट पर जदयू का कब्जा है. इस क्षेत्र से क्रमश: डॉ रंजूगीता, शाहिद अली खान, सुनीता सिंह चौहान व गुड्डी देवी विधायक है. इनमें शाहिद अली खान ने हाल के महीनों में जदयू से पाला बदल कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी का दामन पकड़ लिया है. जातिगत आधार पर सीतामढ़ी के उक्त सीटों पर सीतामढ़ी व रीगा सीट पर वैश्य, बाजपट्टी व परिहार सीट पर यादव, बथनाहा सीट पर पिछड़ा, सुरसंड सीट पर अल्पसंख्यक, रुन्नीसैदपुर सीट पर भूमिहार व बेलसंड सीट पर राजपूत बिरादरी का प्रतिनिधित्व है. जानकारों की माने तो इनमें शाहिद अली खान को छोड़ कर तकरीबन सभी की मौजूदा दल से ही चुनावी मैदान में पुन: वापसी की संभावना है. शाहिद अली खान किस दल से चुनावी समर में अपना भाग्य आजमायेंगे इस पर सभी की नजर टिकी है. अब तक चुनावी गणित का हिसाब जाति व पार्टी के सूत्र पर काम करता रहा है. परंतु इस बार के चुनाव में तनिक बदलाव की आशंका व्यक्त की जाने लगी है. चर्चा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दावेदारी को लेकर परेशान हाल कुछ राजनीतिक दल के नेता अपनी राजनीतिक ताकत से नेतृत्व को अवगत कराने और आगे का रास्ता साफ करने की मंशा पाले हैं. अगर इनकी राजनीतिक चाल में कोई रोक नहीं लगी तब संभव है कि दलगत प्रत्याशी की परेशानी बढ़ सकती है.

अब पहले चर्चा विधान परिषद चुनाव पर करना मुनासिब लगता है. सीतामढ़ी - शिवहर सीट से विधान परिषद के स्थानीय निकाय से बतौर पार्षद भाजपा के बैद्यनाथ प्रसाद है. पिछले चुनाव में जदयू से मिले जोरदार समर्थन के बूते इनको जीत की माला नसीब हुई थी. परंतु अबकी बार जदयू - भाजपा के रिश्ते में दरार के कारण इनको रून्नीसैदपुर से जदयू की विधायक गुड्डी देवी के पति सह वरिष्ठ जदयू नेता राजेश चौधरी के अलावा युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप राय व अमिताभ गुंजन समेत अन्य संभावित प्रत्याशियों के बीच से सीट निकालने की चुनौती है. राजनीतिक गठजोड़ नहीं हो पाने की स्थिति में जदयू, राजद व भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में सभी अपना प्रयास कर रहे है. जानकारों की माने तो राजनीतिक गठजोर की स्थिति में विधान परिषद चुनाव में भाजपा को नुकसान की पूरी संभावना से इंकार नही किया जा सकता है. परंतु गठजोड़ नहीं होने की स्थिति में भी भाजपा के लिए चुनावी समर आसान नजर नही आ रहा है. कारण कि कतिपय कारणों से पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर नगर निकाय प्रतिनिधियों तक के बीच से विरोध की गूंज साफ सुनायी देने लगी है. इस स्थिति में अगर यह कहा जाये कि किसी की भी जीत आसान नहीं है तो गलत नहीं होगा. परंतु हार जीत मैदान में खड़े प्रत्याशी के बीच ही होना है यह भी सही है. यही से शुरू होता है वोटों की खरीद फरोख्त की बुकिंग का खेल. जो प्रत्याशी जितना रकम का खाद चुनावी मैदान में डालेगा, इसका वोट फसल इतना ही तेजी के साथ लहलहायेगा. विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में अबकी बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर के अलावा जदयू के राज किशोर कुशवाहा की भूमिका भी दल समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में महत्वपूर्ण होने की चर्चा है. इनके अलावा सीतामढी के सांसद राम कुमार शर्मा के अलावा चार पूर्व सांसद क्रमश: जदयू के नवल किशोर राय व डॉ अर्जुन राय, राजद के सीताराम यादव व राम श्रेष्ठ खिरहर समेत पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय व नवल किशोर शाही एवं पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव व नगीना देवी की संभावित भूमिका पर भी लोगों की नजर है.

अब एक नजर अलग अलग दल के नेताओं की चल रही गुटबाजी पर भी डालना आवश्यक है. जिले की राजनीति में चल रही चर्चाओं पर यकीन करे तो विधान परिषद व विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रतिनिधियों की गुटबाजी चरम पर हो सकती है. जदयू, राजद, भाजपा समेत तकरीबन सभी दलों में नेताओं के बीच टिकट की दावेदारी को लेकर गुटबाजी की शुरूआत पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गयी थी. चर्चा है कि जब इम्मीद धराशायी हुई तब सभी ने अपने - अपने स्तर से कार्यकर्ताओं की पोटली बांधना शुरू कर दिया. जदयू व राजद के नेताओं के साथ रहने वाले कुछ कार्यकर्ता अंतिम क्षण में रालोसपा का दामन पकडने से भी बाज नहीं आये. नतीजतन भाजपा-लोजपा समर्थित रालोसपा का चुनावी राह आसान होता गया. अगर विधान परिषद व विधानसभा चुनाव में भी दलगत नेता पार्टी नेतृत्व के समर्थन में मन से एकजुट नही हुए तब पुन: आपसी गुटबाजी का खामियाजा किसी भी दल को भुगतना पड सकता है. वैसे फिलहाल सभी नेताओं के दरबाजा पर संभावित प्रत्याशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. मान-मनौबल का काम भी बहुत हद तक किये जाने की चर्चा चल रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

समर कैंप का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के फ्रांट एज स्टडीज स्कूल के निदेशक पीआर भारद्वाज द्वारा समर कैंप 2015 का आयोजन किया गया. बच्चों में शारीरिक व मानसिक शक्ति बढ़ाने को लेकर आयोजित कैंप में योगाभ्यास, सूर्यनमस्कार, नृत्य, संगीत, चित्रकला समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान स्कूल के शिक्षकों की देखरेख में बच्चों को अलग -अलग खेल का अभ्यास कराया गया. बताया गया है कि कैंप में सफल बच्चों को शिल्ड व मेडल देकर सम्मानित किया जायेगा.

– विकास

भूकंप पीड़ितो के सहायतार्थ दिया चेक

सीतामढ़ी लायंस क्लब प्रियदर्शिनी की ओर से भूकंप पीडितो के सहायतार्थ सांसद राम कुमार शर्मा को 20 हजार का चेक सौंपा गया. बताया गया कि सांसद उक्त राशि प्रधानमंत्री नेशनल रीलीफ फंड में जमा कर देंगे. डुमरा रोड स्थित आचार्य सुदर्शन आई हॉस्पीटल में आयोजित एक समारोह में क्लब की अध्यक्ष डॉ. लता गुप्ता, कोषाध्यक्ष तारा खेमका, डॉ. रेणु चटर्जी, इंदु गुप्ता, पॉली चौधरी, लायंस क्लब सेंट्रल के सदस्य राज कुमार खेमका व दीपक कुमार चौधरी समेत अन्य थे.

– ब्रजेश

राजद के लोग खून पसीना एक कर देंगे

बेगूसराय एवं खगड़िया स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जनता दल की बैठक अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में बेगूसराय एवं खगड़िया जिला स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच विचार विमर्श किया गया. बैठक में कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि जनता परिवार द्वारा समर्थित उम्मीदवार डॉ संजीव हैं जबकि सच्चाई यह है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचन्द्र पूर्वे ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि जनता परिवार की ओर से राजद डॉ उर्मिला ठाकुर ही प्रत्याशी हैं और रहेंगी. पिछले चुनाव में भी डॉ उर्मिला ठाकुर बहुत ही कम मतों के अंतर से चुनाव हार गई थीं. वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय निकाय के पूर्व एवं वर्तमान प्रत्याशी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव व प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे का आर्शीवाद एवं दिशानिर्देश प्राप्त कर चुनाव की तैयारी में जुट गई हूं और अलौली प्रखंड की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों का आर्शीवाद प्राप्त करने जा रही हूं.उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों की हिफाजत के लिए मैं सदैव सदन में आवाज उठाइंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए भी तैयार रहूंगी. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहा है और खुला रहेगा.■

–गीता

एक नज़र

जेल भेजे गए मानव तस्कर

श्रम संसाधन विभाग द्वारा भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल स्टेशन पर की गयी छापेमारी में पकड़े गए पांच मानव तस्करों को जेल भेज दिया गया. इसकी जानकारी देते हुए पूर्वी चम्पारण जिले के श्रम अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि छापेमारी में सोलह बाल श्रमिकों को विमुक्त किया गया जिस में दो बाल श्रमिक नेपाल के हैं जबकि चौदह चम्पारण जिले के हैं. बाल श्रमिकों की पहचान छौड़ादानों थानाक्षेत्र के तीनकोनी निवासी रघुनी पासवान के तेरह वर्षीय पुत्र सुनिल पासवान, पश्चिमी चम्पारण जिला के सवैया निवासी रामचन्द्र राय के तेरह वर्षीय पुत्र सिकन्दर कुमार, शिवराजपुर नौतन निवासी रसूल अंसारी के पुत्र परवेज अंसारी, मुबारक के पुत्र नौशाद आलम, मंसूर आलम के पुत्र पप्पू अंसारी, साठी थानाक्षेत्र के धर्मपुर निवासी शेख छेदी के पुत्र मो. इसराफील, किशुनदेव राम के पुत्र अनिल कुमार, रामचन्द्र राम के पुत्र शत्रुघ्न कुमार व नेपाल के रामइकबाल व वसीम हैं. इसके अलावा पकड़े गए मानव तस्करों की पहचान छौड़ादानो थानाक्षेत्र के तीनकोनी निवासी भोला पासवान, नेपाल के गजेन्द्र मुखिया, पश्चिमी चम्पारण मैनाटाड़ के अमर किशोर महतो, सिकटा बरदाही के मंसुर अंसारी शामिल है. इन्हे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है. सीडब्ल्यूसी के आदेश से विमुक्त कराये गये सभी बच्चों को प्रयास चिल्ड्रेन होम बेतिया भेज दिया गया. छापेमारी में एसएसबी व प्रयास की टीम भी शामिल थी.

देश में एक साल में हुआ विकास

भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और अनेक ऐतिहासिक योजनाएं चल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है और देशवासी इसका लाभ ले रहे है. वे स्थानीय नगर भवन के सभागार में मोदी सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में चलाये जा रहे योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि एक वर्ष के अंतराल में अनेक ऐतिहासिक योजनायें जमीन पर उतारी गयी है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का विशेष ख्याल रखा गया है और इसके लिए पचास लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान का भी भरपूर लाभ मिल रहा है और सरकारी व गैर सरकारी सभी विद्यालयों में शौचालय बनाने की योजना तैयार की गयी है और इस बाबत एक करोड़ पैसठ लाख एकतीस हजार छह सौ रूपये की स्वीकृति मिल गयी है तथा इसका टेंडर भी हो गया है. मौके पर नगर विधायक प्रमोद कुमार, केसरिया विधायक सचिन्द्र सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष सुनिल मणि तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पंडित राज किशोर मिश्रा, डॉ. लालबाबू प्रसाद, राजा ठाकुर, नगर सभापति प्रकाश अस्थाना समेत बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे.

सांसद प्रतिनिधि बनने पर हर्ष व्यक्त

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के परबत्ता प्रखंड उच्च विद्यालय करना के प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक की गई. जिसकी अध्यक्षता लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष नवल कुमार ने किया. बैठक में लोजपा व भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. बैठक को संबोधित करते हुए लोजपा के जिला अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने कहा कि सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के द्वारा लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष नवल कुमार को परबत्ता का सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है. सांसद प्रतिनिधि चुने जाने के बाद नवल कुमार को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया. मौके पर श्री कुमार ने कहा कि सांसद महोदय ने जिस उद्देश्य से हमें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, ठीक इसी प्रकार इनके आदेश का पालन करूंगा तथा समाज के साथ मिलकर विकास करूंगा. उन्होंने कहा कि मैं जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का हर समय ख्याल रखूंगा. इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नरेश प्रसाद बादल, प्रदेश संगठन सचिव विष्णुदेव मंडल, बेलदौर प्रखंड अध्यक्ष मनिलाल महतो, डॉ. रंजीत पासवान, अरविन्द स्वर्णकार, लोजपा जिला महिला प्रकोष्ठ की सुनीता सिंह, सीता देवी, दिवाकर सिह, रोहित चौरसिया, अनुप कुमार, सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

कार्यशाल के बहाने सरकार पर हमला

गोगरी अनुमंडल के मध्य विद्यालय कन्हैयाचक दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा कार्यशाला का आयोजन किया किया. जिसकी अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी ने की. कार्यशाला का आयोजन डॉ. शियामानंद प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि के बाद दीप प्रज्जवलित कर किया गया. कार्यशाला में कार्यकर्ताओं ने नरेन्द्र मोदी की भूरी-भूरी प्रशंसा किया और कहा आज देश में नरेन्द्र मोदी की हर तरफ जयकार है तथा आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू का नामोनिशान मिट जायेगा. कार्यकर्ताओं ने जमकर नीतीश सरकार पर प्रहार किया और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. बैठक में निर्णय लिया गया कि जो कार्यकर्ता सबसे अधिक नये कार्यकर्ता बनाये होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. इस मौके पर रामनरेश सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह, कमलेश चौहान, दीपक सिह, लक्ष्मी सहनी, नीतीश कुमार, सिकेन्द्र शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

– गीता कुमार

फेसबुक बना परेशानी का सवब

सीतामढ़ी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष युगल किशोर प्रसाद इन दिनों कुछ फेसबुकिया लोगों से परेशान है. पिछले दिनों इस संदर्भ में एक प्रेसवार्ता कर मामले को सार्वजनिक किया. बताया कि कुछ लोग साजिश के तहत उनके खिलाफ गलत बातों को फेसबुक पर पोस्ट कर प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद के उप सभापति इरशाद आलम, पार्षद धनंजय कुमार, अरुण कुमार राय, आफताब अंजुम बिहारी, बंटू सिंह, मुकेश ठाकुर, रंजय सर्राफ, मनोज कुमार, युगेश्वर पासवान, विजय कुमार मिश्रा, रामा शंकर प्रसाद, कैलाश प्रसाद, महेश प्रसाद, अब्दुल खालिक, सूरज राउत, उपेंद्र कुमार, सुनील कुमार व रामानेक सिंह समेत अन्य की मौजूदगी में दोषी के विरुद्ध मुकदमा का निर्णय लिया गया.■

– ब्रजेश

30 साल का फासला भी नहीं रोक सका इनका मिलन

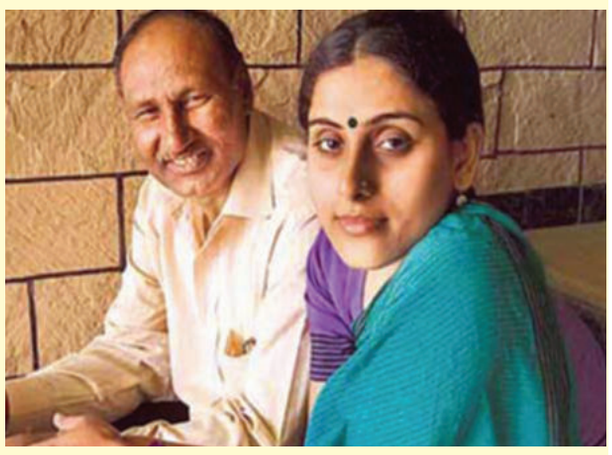

मटुकनाथ और जूली ने लव-स्कूल खोला है. वह भी गुरु जी के अपने गांव जयरामपुर में. इस स्कूल के बारे में वह कहते हैं कि प्यार हमें रचनात्मक बनाता है. प्यार का मतलब है बलिदान. इसमें स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती. प्यार के दो चेहरे होते हैं- पहला विध्वंसात्मक और दूसरा रचनात्मक. दुख की बात है कि आज के युवा प्यार के सही तरीके को नहीं पहचान पा रहे हैं. हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे सर्वोच्च बलिदान करते हुए समाज के लिए उदाहरण पेश किया जाए और कैसे रचनात्मक प्यार किया जाए.

राधिका

लव गुरु मटुकनाथ और जूली शायद आपको याद हों. पटना में प्रोफेसर रहे अधेड़ उम्र के मटुकनाथ ने अपनी ही छात्रा जूली से प्यार किया और फिर घर परिवार छोड़ कर दोनों एक दूसरे के हो गए.

मटुकनाथ और जूली को परिवार और समाज से खूब प्रताड़ना मिली लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी. मटुकनाथ कहते हैं कि मैं और जूली पहली बार क्लासरुम में ही मिले थे. लेकिन उन दिनों मेरा जूली की क्साल में कम आना होता था. साल 2004 में मैंने एक कैंप लगाया था जिसमें जूली ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. इसी दौरान हमारी बातचीत शुरु हुई थी. इसके बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई. हम दोनों फोन पर घंटों बातें करते थे. हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था. फिर एक दिन जूली ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है. यह सुनकर पहले तो मैंने उसे समझाया कि ये संभव नहीं हैं. एक तो मैं शादी-शुदा हूं. मेरे बच्चे भी हैं. और हमारी उम्र में 30 साल का फासला है. लेकिन फिर, कुछ समय बाद मुझे भी लगा कि मैं भी जूली के प्रति काफी आकर्षित हो गया था. इसके बाद शुरु हुई थी हमारे लिए मुश्किलें.

जूली के संग प्रेम प्रसंग की वजह से 15 जुलाई, 2006 को उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा था. 20 जुलाई, 2009 को बर्खास्तगी झेलनी पड़ी थी. लेकिन, कहते हैं ना प्रेम सचमुच अंधा होता है. तमाम विरोधों के बावजूद मटुकनाथ और जूली ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. यहां तक कि इस कदम के बाद पटना विश्वविद्यालय ने उन्हें बर्खास्त भी कर दिया. पटना विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई, 2006 को मटुकनाथ को बी एन कॉलेज के हिंदी विभाग के रीडर पद से निलंबिक कर दिया. बाद में 20 जुलाई, 2009 को उन्हें सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था. उन पर अपनी कक्षा में बाहरी लोगों को बैठाने व अमर्यादित आचरण करने का आरोप लगाया गया था. इस घटना के बाद मटुकनाश और जूली पर गुरु-शिष्य संबंधों को कलंकित करने के आरोप भी लगे. मटुकनाथ और जूली को परिवार और समाज से खूब प्रताड़ना मिली, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी. इसके बाद मटुकनाथ ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर कुलपति तक न्याय की गुहार लगाई. अब इन सबसे उन्हें मुक्ति मिल गई है. वे फिर से नौकरी पर लौट आए हैं. बकाया पैसे का भुगतान भी विश्वविद्यालय से हो गया है जिससे एक कार जूली के लिए खरीद चुके हैं. यही वजह है कि वे खुश हैं.

मटुकनाथ कहते हैं कि जब इस बात का पता समाज को चला तो हमारे लिए काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं. हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. जब मेरी पत्नी को इस बात का पता चला तब उसने हमें थाने भी पहुंचवा दिया था. लेकिन जब ये बात मीडिया में आई तो इस बात ने तूल पकड़ लिया. लोगों के फोन आने लगे. कई ऐसे बुद्धिजीवियों ने कई जगहों से फोन कर हमारे पक्ष में बोला. उन लोगों का ये कहना था कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, प्यार करना गुनाह नहीं होता है. और फिर हमें छोड़ दिया गया. थाने से छूटने के बाद इतना हंगामा हुआ कि मैं कहीं और गया और जूली कहीं और रहने चली गई. रात भर हमें सोने नहीं दिया गया. दूसरे दिन हमें उसी गांव में एक गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया गया. हम दोनों छिपकर रहने लगे थे. लेकिन एक दिन हमने फैसला किया कि इस तरह डरकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला. हमने समाज का सामना करने का फैसला किया. इस राह में भी हमें कई सारी दिक्कतें भी आईं. समाज भी दो पक्षों में बंट गया. लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया और हमारी दिक्कतें कम हो गईं. आज हम दोनों हंसी-खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं.

मुटुकनाथ आगे बताते हैं कि हम दोनों ने शादी नहीं की है. हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह की तरह रहते हैं. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. मुटुक और जूली लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं. मुटुकनाथ कहते हैं कि हम दोनों शादी के बंधन जैसी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं. मटुकनाथ जूली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, सबसे पहले तो उनकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया था. वह जो सोचती हैं, वह करके ही रहती हैं. इतने बवंडर में भी उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में टॉप किया और जेएनयू में भी. वो बहुत ही उच्च विचार की हैं. उनके सोचने समझने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है.

कुछ दिनों पहले मटुकनाथ और जूली ने लव-स्कूल खोला है. वह भी गुरु जी के अपने गांव जयरामपुर में. इस स्कूल के बारे में वह कहते हैं कि प्यार हमें रचनात्मक बनाता है. प्यार का मतलब है बलिदान. इसमें स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती. प्यार के दो चेहरे होते हैं- पहला विध्वंसात्मक और दूसरा रचनात्मक. दुख की बात है कि आज के युवा प्यार के सही तरीके को नहीं पहचान पा रहे हैं. हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे सर्वोच्च बलिदान करते हुए समाज के लिए उदाहरण पेश किया जाए और कैसे रचनात्मक प्यार किया जाए. मटुकनाथ ने इस स्कूल को मान्यता दिलाने के लिए सीबीएसई में आवेदन भी किया है. मटुकनाथ के अनुसार इस जीवन जागृति पाठशाला में जूली केन्द्रीय भूमिका में होंगी और उन्हें स्कूल की माता बनाया जाएगा. गांव के लोग भी इसके लिए तैयार हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीनियर के प्रति समर्पण से मिली कामयाबी

रजनीकांत पाण्डेय

जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें करने या सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इन बातों का बहुत योगदान होता है. हम बात कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील केशव श्रीवास्तव की. इनके जीवन की कहानी आलस्य को त्यागकर मेहनत करने की सीख देती है और युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी है. केशव की प्रारंभिक शिक्षा बिहार के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में हुई. उनके पिता बिहार सरकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी में रहे थे. केशव की दसवीं की पढ़ाई दरभंगा के छोटे से गांव लोहट से सन 1958 में हुई. उन्होनें पटना के बी. एन कॉलेज से राजनीति शास्त्र में सन् 1963 में बीए(आनर्स) और सन् 1965 में एमए की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय से सन 1967 में पूर्ण की. इसके बाद केशव कुछ दिनों तक पटना के एक महाविद्यालय में राजनिति शास्त्र के शिक्षक भी रहे. बाद में उनकी रुचि वकालत के पेशे में हुई और सन 1967 में ही वह ट्रेनी एडवोकेट (जो उन दिनों में आर्टकल क्लर्क कहलाता था) के रूप में हाईकोर्ट से जुड़ गए. उसके बाद वह परिश्रम के दम पर आगे बढ़ते चले गए फिर वहां से उन्होंने पलट कर कभी नहीं देखा. उन्हें अब तक इस पेशे में चार सीनियरों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वे चारों थे स्व. केशरी किशोर शरण जो सिविल केसों के ज्ञाता थे, स्व. प्रेम शंकर सहाय वो क्रिमिनल केसों के जानकार थे, नागेन्द्र प्रसाद सिंह और स्व वृषकेतु शरण सिन्हा जो जी पी सेकेंड थे, इनमें से पिछले तीन पटना हाईकोर्ट के जज भी रहे और नागेन्द्र प्रसाद सिंह सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं. केशव ने कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपना नाम बनाया है. पटना हाईकोर्ट में उनका नाम अच्छे अधिवक्ताओं में लिया जाता है. केशव करीब-करीब 18-19 वर्षों तक बिहार स्टेट बार कांउसिल के चयनित सदस्य रहे, इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण कार्यो में सक्रिय योगदान भी दिया. वह एक बार एडवोकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी रहे. इन सबके आलावा केशव बिहार इंस्टिट्यूट आफ लॉ के सचिव भी हैं. केशव बताते हैं की उनके परिवार से कोई भी लीगल प्रोफेशन में नहीं था, इस वजह से उन्हें अपना स्थान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. लेकिन लाख विपरीत परिस्थिति से भी वह विचलित नहीं होते थे. जब वह आर्टिकल क्लर्क थे, उसी समय से नियमपूर्वक वह हर शाम सीनियर एडवोकेट स्व केशरी किशोर शरण के घर जाकर लॉ की किताबें पढ़ते थे या किसी केस की ड्राफ्टिंग के लिए डिक्टेशन लेते थे. अपने अथक परिश्रम से उन्होंने अपने सीनियरों की नज़र में ऐसी जगह बना ली कि वो भी अपने वैसे केसों को जिनके लिए वे समय नहीं निकाल पाते थे उन केसों को केशव को सौंप देते थे, इस तरह उनको कोर्ट में 2-3 वर्ष बाद से ही केस लड़ने के मौके मिलने लगे. केशव बताते हैं की मैंने इतनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से स्व प्रेम शंकर सहाय जी के साथ उनके जूनियर का कार्य किया कि हम दोनों के बीच एक गहरा विश्वास भरा संबंध बन गया. इसी वजह से जब वह सन् 1976 में पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश नियुक्त हुए तो उन्होंने अपने अनेकों रिश्तेदारों के वकालत पेशे में रहते हुए, अपने सारे पेंडिंग केस मुझे इस विश्वास के साथ सौंप दिए कि मैं उन केसों की देख-भाल और बहस ठीक उसी तरह करूंगा जैसे वे करते थे. केशव मानते हैं की सीनियरों का यह विश्वास आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. आज के युवाओं के लिए केशव कहते हैं कि किसी पेशे में मेहनत, अथक परिश्रम, सीनियर के प्रति पूर्ण समपर्ण और ईमानदारी हमेशा अच्छा फायदा देती हैं. और ये सफलता की सीढ़ियां हैं. वह बताते हैं कि अपने ऊपर विश्वास होना भी जरूरी है. यदि आप मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे सफल होना ही है तो सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी.■

र्ट में उनका नाम अच्छे अधिवक्ताओं में लिया जाता है. केशव करीब-करीब 18-19 वर्षों तक बिहार स्टेट बार कांउसिल के चयनित सदस्य रहे, इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण कार्यो में सक्रिय योगदान भी दिया. वह एक बार एडवोकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी रहे. इन सबके आलावा केशव बिहार इंस्टिट्यूट आफ लॉ के सचिव भी हैं. केशव बताते हैं की उनके परिवार से कोई भी लीगल प्रोफेशन में नहीं था, इस वजह से उन्हें अपना स्थान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा.

feedback@chauthiduniya.com

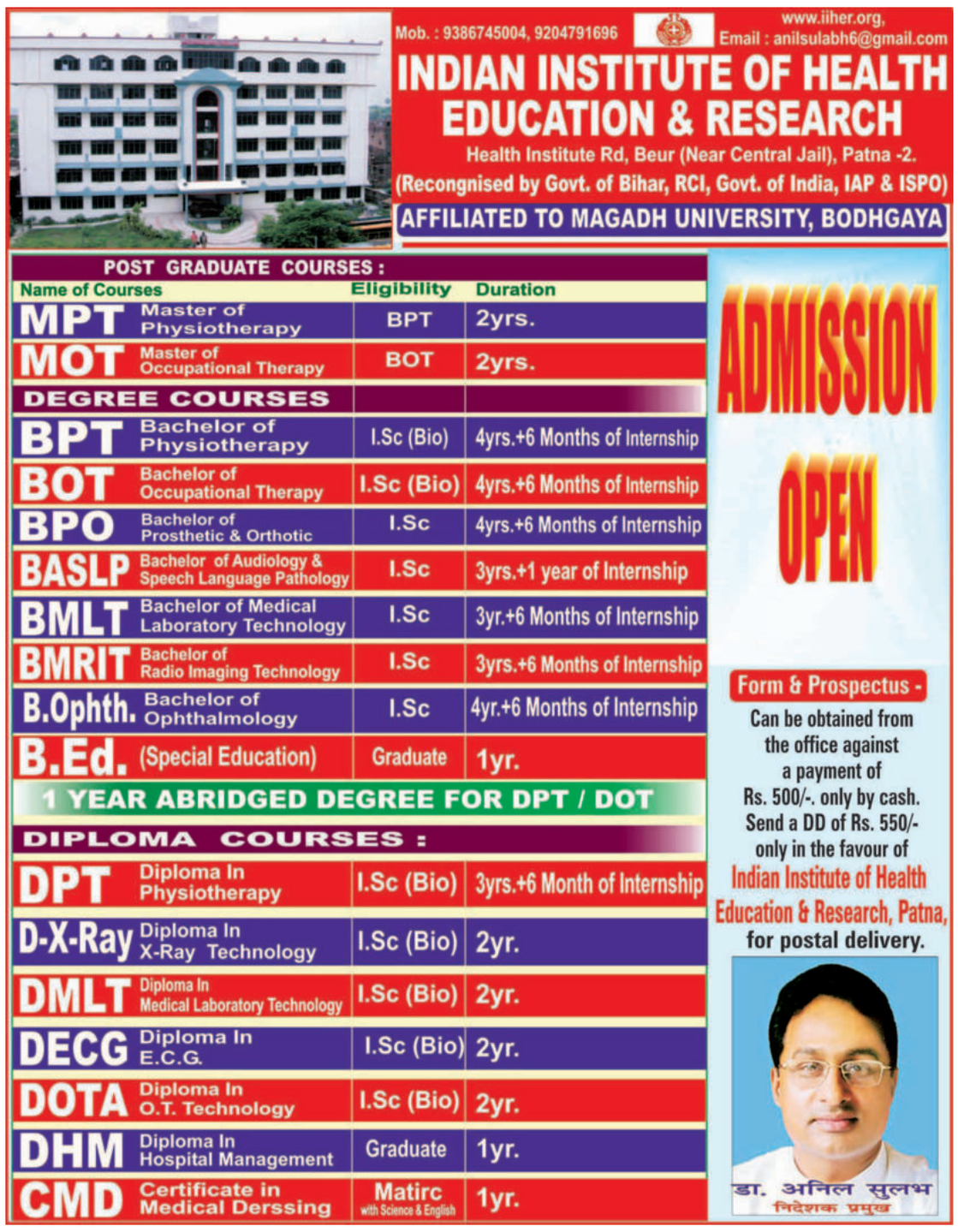

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

08 जून –14 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

कनहर बांध के विस्थापितों पर कहर

प्रभात रंजन दीन

आंदोलनकर्मी गम्भीरा प्रसाद को 27 अप्रैल को इलाहाबाद से गिरफ्तार दिखाया गया. जबकि उन्हें 21 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया था. उनका जुर्म यह है कि वे विस्थापितों के समर्थन में आंदोलन में शरीक थे. वे कोर्ट के माध्यम से भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. इसी सिलसिले में 20 अप्रैल को इलाहाबाद आये हुए थे जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित कनहर घाटी में बन रहे, रुक रहे, फिर रुक-रुक कर बन रहे बांध को लेकर स्थानीय लोगों की पीड़ा और सब्र का बांध टूट रहा है. कनहर बांध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीति लचर और अराजक है. पिछले दिनों विस्थापितों और पुलिस के साथ हुई तनातनी और बाद में पुलिस की तरफ से दो दिन की गई फायरिंग के बाद प्रदेश सरकार ने कई बार दावा किया कि विवाद खत्म करने की दिशा में ठोस पहल हो रही है और लोगों का गुस्सा शांत हो रहा है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना चरम पर है. 14 अप्रैल को फायरिंग के बाद पुलिस ने फिर 18 अप्रैल को भी फायरिंग की थी. दर्जनों लोगों को जख्मी हालत में ही गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तार लोगों में गम्भीरा प्रसाद, राजकुमारी, पंकज गौतम, लक्ष्मण भुईयां, अशरफी यादव वगैरह के नाम शामिल हैं, जिन्हें मिर्जापुर जेल में ठूंस दिया गया है. आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि जेल में उनके साथ अपराधियों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है. उन्हें उनके परिवार से मिलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है. जनता से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार किया जाना असंवैधानिक है, दूसरा उनके साथ बदसलूकी आपराधिक कृत्य है.

आंदोलनकर्मी गम्भीरा प्रसाद को 27 अप्रैल को इलाहाबाद से गिरफ्तार दिखाया गया. जबकि उन्हें 21 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया था. उनका जुर्म यह है कि वे विस्थापितों के समर्थन में आंदोलन में शरीक थे. वे कोर्ट के माध्यम से भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. इसी सिलसिले में 20 अप्रैल को इलाहाबाद आये हुए थे जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गम्भीरा प्रसाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रवि किरन जैन से मिलने आये थे और कुछ जरूरी कागजात की फोटोकॉपी कराने के लिए जैसे ही बाहर निकले, स्कॉर्पियों से आठ लोगों ने धावा बोल कर उन्हें उठा लिया. इस घटना को अपहरण समझ कर शहर के लोगों ने चुनौती दी और तीन लोगों को धर-दबोचा, लेकिन अन्य पांच लोग गम्भीरा प्रसाद को लेकर भाग निकले. पकड़े गए तीन लोगों को कैंट थाने ले जाया गया. बाद में देर रात कैंट थाने में औपचारिकता पूरी कर गम्भीरा प्रसाद को जेल भेज दिया गया.

इसी तरह अशर्फी यादव और लक्ष्मण भुईयां को 14 अप्रैल 2015 को वाराणसी से उठाया गया था. पुलिस फायरिंग में घायल हुए अकलू चेरो को वे वाराणसी के अस्पताल में भरती कराने जा रहे थे. इन लोगों को वाराणसी के सर सुन्दर लाल अस्पताल से आपराधिक तरीके से अगवा कर लिया गया. बाद में हो-हल्ला मचने पर सोनभद्र के जिलाधिकारी ने अरुंधति धुरू को सूचना दी कि वे दोनों जेल में बंद हैं. विस्थापितों के आंदोलन में शरीक आदिवासी महिला राजकुमारी को भी गैरकानूनी तरीके से 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने राजकुमारी पर वन कानून के मुकदमे भी साथ-साथ लाद दिए और जेल में ठूंस दिया. दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के साथ न्याय करने का दावा करने वाली समाजवादी सरकार में राजकुमारी को भीषण प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ रहा है. उनसे जेल में जबरदस्ती कड़ा काम कराया जा रहा है. उनकी हालत खराब होती जा रही है. सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गौतम के साथ भी पुलिस ने ऐसा ही किया. उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे लादे गए और जेल में बन्द कर दिया गया. जेल में उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कनहर बांध से प्रभावित गांव के शिव प्रसाद खरवार और सुन्दरी गांव के प्रधान रामविचार के लिए पुलिस ने लुक-आउट वारंट जारी कर दिया है. साथ ही अनधिकृत चैनेलों से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दिलवाई जा रही हैं. इन गांवों में लोगों को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया है. आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसमें 500 लोग अज्ञात बताए गए हैं. इसी को बहाना बना कर पुलिस जिसे चाहे उसे उठाकर प्रताड़ित कर रही है और उन्हें जेल में बन्द कर रही है. यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे इस प्रायोजित उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार आयोग, केन्द्रीय गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उल्टा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई और तेज कर दी गई है.

आपको याद दिलाते चलें कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार 14 अप्रैल को एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के राजनीतिक समारोहों के आयोजन में लगी थ

(शेष पृष्ठ 18 पर)

विस्थापितों की मांगें

1. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 7 मई 2015 के फैसले के तहत नए निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए व क्षेत्र में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक माहौल कायम किया जाए.

2. कनहर नदी पर बन रहे अवैध बांध के आस-पास के गांव में पुलिसिया दमन पर तत्काल रोक लगाई जाए. दमन के लिए असंवैधानिक रूप से धारा-144 लागू कर दमन तेज करने की प्रक्रिया अविलंब रोकी जाए.

3. 14 और 18 अप्रैल 2015 को की गई पुलिस फायरिंग की न्यायिक अथवा सीबीआई से जांच कराई जाए.

4. छतीसगढ़ बचाओ आंदोलन के जांच दल, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संदीप पांडेय के नेतृत्व में गए जांच दल और एनएपीएम की नेता मेधा पाटकर ने निहत्थे ग्रामीणों पर पुलिसिया दमन के महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए हैं. इन शिक्सयतों की रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए.

5. पुलिस ने ग्रामीणों पर गोली क्यों चलाई? क्या वजह थी अकलू चेरो के सीने पर सीधे गोली दागी गई? बुजुर्गों और महिलाओं के सिर पर पुलिस ने लाठियों से क्यों प्रहार किया? इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए.

6. पुलिस फायरिंग में जख्मी अकलू चेरो (निवासी सुन्दरी) की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. 14 अप्रैल को 35 लोग घायल हुए थे, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं थीं, उनकी भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. 18 अप्रैल को घायल हुए बुजुर्गों की भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और दोषी अधिकारियों को नामजद नहीं किया गया. ग्रामीणों पर अनगिनत झूठे फर्जी केस लादे गए हैं और उन्हें जेल में बंद किया गया. इस उत्पीड़न की जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

7. जख्मी अकलू चेरो के इलाज में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसे शीघ्र दूर किया जाए और गिरफ्तार किए गए सभी निर्दोषों को फौरन रिहा किया जाए.

8. पुलिस अधीक्षक शिव शंकर यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारियों कपिलदेव यादव, प्रभारी निरिक्षक थाना दुद्धी के प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह यादव, बभनी के थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह, विंढमगंज के थानाध्यक्ष महाबीर यादव, अमवार चौकी प्रभारी अमवार चन्द्रशेखर यादव, दुद्धी थाने के उप निरीक्षक चन्दन सिंह, सिपाही सुनील यादव, राजेन्द्र यादव, फूलचन्द मिश्रा, बभनी थाने के सिपाही संजय यादव, विंढमगंज के सिपाही अतुल कुमार, देवेन्द्र सिंह, ओबरा थाने के सिपाही बृजेश कुमार, पुलिस लाइन के सिपाही अविनाश राय, मुख्य आरक्षी अमृत राय, गौरी शंकर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए

9. पुलिस के इशारे पर आंदोलनकारियों पर हमला करने वाले सादिक पुत्र नूर मोहम्मद, एजाज पुत्र सादिक, फैयाज़ पुत्र नूर मोहम्मद, मुरहक पुत्र फजीतो करीब, बहादुर पुत्र मुहम्मद सभी ग्राम बघाड़, शमशेर पुत्र सादिक हुसैन व मुहम्मद पुत्र रमजान अली ग्राम सुन्दरी से, निराला पुत्र किसुन, रमेश पुत्र गुलाब, अलाउदीन पुत्र हैदर, सुभाष प्रधान पुत्र रोशन सभी ग्राम अमवार, चिन्तामणि पुत्र मीठू, जगदीश पुत्र गंगा, शीतल पुत्र सेवक यादव, रामजीत पुत्र शोभी सभी ग्राम भीसूर, सलाउदीन पुत्र इस्लाम ग्राम बैरखड, जगदीश यादव ग्राम जोरूखाड़ और जुब्रैल दुद्धी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए.

10. ग्रामीणों पर हमले में शामिल रहे दुद्धी के विधायक रूबी प्रसाद, रॉबर्ट्सगंज के विधायक अविनाश कुशवाहा और पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

विदेश यात्राओं में पीएम से पीछे नहीं सीएम

सूफी यायावर

उधर देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्राएं कर रहे हैं तो इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विदेश भ्रमण कर रहे हैं. दोनों के उद्देश्य तो एक दिखते हैं, लेकिन अंतरकथा अलग-अलग हो सकती है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले दिनों अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव, मंत्री अभिषेक मिश्र और भारी लावो-लश्कर के साथ फ्रांस यात्रा पर गए. आपको याद ही होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी गए थे तो उसके कुछ ही दिन के बाद अखिलेश यादव भी जर्मनी गए थे. सत्ता के गलियारे में ही यह सवाल उठ रहा है कि जब जर्मनी गए ही थे तो उसी समय पड़ोसी देश फ्रांस की यात्रा भी निष्पादित कर लेते. दोबारा जाने-आने का बेमानी खर्च उत्तर प्रदेश सरकार को झेलना पड़ा. देश के आम नागरिकों के धन का इस्तेमाल भारतीय लोकतंत्र में नेताओं की मौज-मस्ती के लिए होता है. पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे. फिर अखिलेश यादव भी फ्रांस चले गए. यह अभूतपूर्व संयोग है.

इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फ्रांस यात्रा कन्नौज के इत्र उद्योग को एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित करने की मंशा से की गई बताई गई और कहा गया कि फ्रांस इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. फ्रांस और भारत के बीच चूंकी मजबूत वाणिज्यिक सम्बन्ध रहे हैं, इसलिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने फायदे में भी भुनाना चाहती है. अखिलेश यादव ने फ्रांस के सुगंध केंद्र ग्रासे में इत्र उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में कई पहल की. ग्रासे दुनिया की सुगंध-राजधानी के तौर पर मशहूर है. इसी तरह कन्नौज को इत्र की राजधानी कन्नौज कहा जाता है. ग्रासे और कन्नौज के बीच कारोबारी सम्बन्ध स्थापित होने से इत्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रांस के सहयोग से प्रदेश में इत्र उद्योग को नई ऊंचाइयां दी जा सकती हैं. इससे रोजगार की नई सम्भावनाओं का सृजन होगा और फूलों की खेती कर रहे किसानों को समृद्ध किया जा सकेगा. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुलकंद को वैट से मुक्त किए जाने का निर्णय फूलों की खेती को बढ़ावा देने के इरादे से ही किया गया. ग्रासे के मेयर जीरोम वॉयद की मौजूदगी में हुई बैठक में फ्रांस के परफ्यूम एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिप मासे, सुप्रसिद्ध परफ्यूम कम्पनियां मसलन, लुई विटॉन और शैनल के प्रतिनिधि अधिकारी और फ्रांसीसी उद्योगपति मौजूद थे. मुख्यमंत्री के साथ फ्रांस यात्रा पर गए मंत्री अभिषेक मिश्रा, कन्नौज की सांसद डिंपल यादव, यूपीएसआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक मनोज सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव जीएस नवीन कुमार, कन्नौज इत्र उद्योग से जुड़े मुशीद अहमद खान और पुष्पराज जैन भी मौजूद थे.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भारी-भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई फ्रांस यात्रा पर विपक्ष ने कई सवाल सामने रख दिए हैं. भाजपा ने तो मुख्यमंत्री पर लड़कपन तक का आरोप लगाया जो हर तीन-चार महीने के अंतराल पर विदेश सैर-सपाटे को मचलने लगते हैं. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता बिजली-पानी के भीषण संकट से बेहाल है. सैकड़ों किसानों की जान जा चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री पिछले एक महीने के दौरान जर्मनी के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर फ्रांस चले गए. बताया जा रहा है कि फ्रांस दौरे से इत्र निर्माण की नई तकनीक और संभावनाओं का पता लगाया गया. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आठ महीने पहले हॉलैंड से लौटकर भी कुछ ऐसे ही सब्जबाग दिखाए थे. यह भी दावा किया गया था कि नीदरलैंड के लोरा हॉलैंड सहकारी संगठन की कार्यप्रणाली व आल्समीर पुष्प नीलामी केंद्र की तकनीकी का इस्तेमाल यूपी में फूलों की खेती को बढ़ावा देने में किया जाएगा. अब मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि हॉलैंड दौरे के आठ महीने बाद उन्होंने प्रदेश में फूलों की खेती बढ़ाने के लिए क्या नीति बनाई और क्या प्रयास किए. चंद्रमोहन ने कहा कि यह प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखाधड़ी है. मुख्यमंत्री जिस सरकारी धन से विदेशों के दौरे कर रहे है, वह आम जनता व किसान द्वारा चुकाए गए टैक्स का पैसा है. सपा के राज में किसान और जनता बदहाल है और मुख्यमंत्री फ्रांस में परिवार समेत गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं. मुख्यमंत्री और उनकी टीम की फ्रांस यात्रा पर भाजपाई प्रतिक्रिया के जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनाप-शनाप विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया और पूछा कि नरेंद्र मोदी की आलीशान विदेश यात्राओं पर हो रहा खर्च क्या जनता के पैसे से नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से भारतवर्ष को क्या हासिल हुआ, इस पर केंद्र सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार का दावा या छलावा!

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने नीदरलैंड में प्रोग्रेसिव अलाएंस के अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लिया. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने तो यहां तक दावा कर दिया कि दुनिया के प्रगतिशील राजनीतिक दलों के संगठन प्रोग्रेसिव अलाएंस ने यूपी की समाजवादी सरकार की योजनाओं को विभिन्न देशों में लागू करने का फैसला किया है. नीदरलैंड के रॉटर्डम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पेंशन योजना, विमेन पावर लाइन 1090 और लोहिया ग्रामीण आवास योजना पर चर्चा हुई. सांसद डिंपल यादव ने यूपी सरकार की इन योजनाओं के बारे में अलाएंस को जानकारी दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे. सम्मेलन में पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट विमेन की अध्यक्ष ज़ीटा गुरमई, ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की नेता प्रतिपक्ष जेन रॉयाल, डेमोक्रेटिक फोरम फॉर लेबर एंड लिबर्टीज़ ट्युनिशिया की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हेला अलूलू और नीदरलैंड की लेबर पार्टी की अंतरराष्ट्रीय सचिव किर्सटेन माइजर ने भी सत्र को सम्बोधित किया. ■

अखिलेश की हार्वर्ड यात्रा के खर्चे पर उठ चुके हैं सवाल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सरकार के मंत्रियों की तमाम विदेश यात्राओं के औचित्य और खर्चे को लेकर सवाल उठते रहे हैं. उनकी हाल की फ्रांस यात्रा को लेकर भी कई गंभीर सवाल सामने हैं. अखिलेश यादव की हार्वर्ड यात्रा पर उठा विवाद भी उल्लेखनीय ही है. सूचना के अधिकार के तहत संजय शर्मा द्वारा मांगी गई जानकारी पर सरकार ने खुद ही समाजवादी मुख्यमंत्री की शाहखर्ची स्वीकार की थी. वर्ष 2013 में अखिलेश यादव अपने 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिम्पोसियम में भाग लेने गए थे. उस दौरान सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री आजम खान की तलाशी लिए जाने के कारण यह दौरा सुर्खियों में आया था. विवाद के कारण मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शरीक हुए बिना ही लौट आए थे. लेकिन अखिलेश के लौट आने और आजम के मुंह फुलाने से खर्चे में तो कोई कमी नहीं आई. उस दौरे पर गए 11 लोगों का खर्च राज्य सरकार ने उठाया था, केवल एक सदस्य विजय कुमार यादव का खर्च उनका निजी व्यय बताया गया था. सरकार ने अभी हाल ही यह स्वीकार किया कि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो दिवसीय दौरे में अखिलेश यादव के शिष्टमंडल की हवाईयात्रा पर 52 लाख 50 हजार रुपये और होटल में ठहरने वगैरह पर 53 लाख 78 हजार 338 रुपये की भारी भरकम रकम खर्च की गई. इस तरह अखिलेश यादव के शिष्टमंडल के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के राजकोष से 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार 338 रुपये खर्च किए गए. प्रदेश सरकार ने अखिलेश की दूसरी विदेश यात्राओं पर हुए खर्चों का ब्यौरा नहीं दिया. ■

कनहर बांध के विस्थापितों पर कहर

पृष्ठ 17 का शेष

तो दूसरी तरफ प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के तहत विस्थापित ग्रामीणों पर पुलिस गोलियां दाग रही थी. सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र में बांध बनाने के लिए विस्थापित किए गए लोगों पर पुलिस की फायरिंग से 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के तहत बांध निर्माण से विस्थापित होने वाले सैकड़ों परिवार लगातार आंदोलन कर रहे हैं. कनहर बांध परियोजना में सोनभद्र के 11 गांवों के और बिहार-झारखंड के नौ गांवों के करीब 15 हजार ग्रामीण विस्थापित हो जाएंगे. 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था. उस समय इस परियोजना की लागत 27 करोड़ थी. 2015 में इस परियोजना की लागत बढ़कर 2200 करोड़ रुपये हो गई है. प्रशासन की ओर से कुछ विस्थापितों को मुआवजा बांटा गया, लेकिन ज्यादातर अब भी विरोध में खड़े हैं. बांध बना तो तीन राज्यों के करीब 80 गांव डूबेंगे, जिनमें अकेले छत्तीसगढ़ के ही 16 गांव हैं. बांध के डूब क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का हाथी अभयारण्य भी शामिल है. कनहर विस्थापितों के आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार विस्थापितों की सही संख्या और डूब क्षेत्र का सही सर्वेक्षण नहीं करा रही है. ऐसे में विस्थापितों की पहचान और उन्हें मुआवजे की रकम देने का काम कैसे शुरू कर दिया गया, यह गंभीर सवाल है.

सोनभद्र की कनहर परियोजना हिंसा के साथ-साथ भीषण आर्थिक घोटाले से भी जुड़ी है. जमीनी सच्चाई यह है कि कनहर परियोजना के एक तरफ अधर में लटका बांध-निर्माण है तो दूसरी तरफ करीब एक लाख आदिवासी ग्रामीण आबादी है, जो अपने पारम्परिक निवास से बेदखल हो रही है. यह बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की कनहर नदी पर प्रस्तावित है, लेकिन इससे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य सीधे-सीधे प्रभावित हो रहे हैं. कनहर सोन नदी की सहायक नदी है. सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 3792.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल से घिरा है. सोनभद्र की सीमाएं उत्तर-पूर्व में बिहार से, पूरब में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा चंदौली जिलों से मिलती हैं. सोनभद्र की 70 फीसदी आबादी आदिवासी है जिसमें गोंड, करवार, पनिका, भुईयां, बइगा, चेरो, घासिया, धरकार और धौनार जातियां आती हैं. अधिकतर ग्रामीण आदिवासी अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं. ये जंगल से तेंदुपत्ता, शहद, सूखी लकड़ियां और जड़ी-बूटियां इकट्ठा कर उन्हें बाजार में बेचते हैं. कुछ के पास छोटी जोतें भी हैं जो ज्यादातर चावल और कभी-कभी सब्जियां पैदा करते हैं. इस इलाके में रहने वाले बहुत से आदिवासियों को रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट के अनुच्छेद-4 तथा अनुच्छेद-20 ने उनकी जमीन और वनाधिकार से वंचित कर रखा है.

पर्यावरण मंत्रालय ने इस इलाके में होने वाले भयानक नुकसान की आशंका को नजरंदाज किया और कोई भी ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जो परियोजना द्वारा पर्यावरण और आबादी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का ठीक-ठाक आकलन करता हो. शुरुआती अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि इससे तकरीबन एक लाख पेड़, 2500 कच्चे घर, 200 पक्के घर, 500 कुएं, करीब 30 स्कूल और कुछ अन्य इमारतें डूब जाएंगी. 2015 आते-आते आंकड़ों की यह तस्वीर और बदल गई होगी. इस बांध परियोजना के शिलान्यास के बाद एक एकड़ पर 22 सौ रुपये की दर से मुआवजा दिया गया था, जो भीख से भी बदतर है. जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन जमीन किसी को भी नहीं मिली. बाहर से मजदूर बुलाए गए. स्थानीय लोगों को मजदूरी के लायक भी नहीं समझा गया. 1976 में शिलान्यास के बाद काम कछुए की चाल से शुरू हुआ, लेकिन बंद अधिक रहा. कभी भी लगातार काम नहीं चला, लेकिन सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के दस्तावेज पर काम का खर्च लगातार दिखाया जाता रहा. 1984 में काम बिल्कुल ही रुक गया. 1989 में काम फिर से शुरू हुआ और 16 परिवार उजाड़ दिए गए. इसके बाद फिर दो दशक से छिटपुट काम छोड़ कर निर्माण कार्य बंद ही रहा. करोड़ों के उपकरण धूल और मौसम में बर्बाद हो गए. इस रुकी हुई परियोजना का 15 जनवरी 2011 को फिर से तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शिलान्यास कर दिया. काम फिर भी रुका ही रहा. समाजवादियों की सत्ता में आने पर सात नवम्बर 2012 को फिर से एक शिलान्यास हुआ. कनहर बांध के स्पिल-वे का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नया शिलान्यास प्रदेश के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने किया. इस तरह कनहर परियोजना का शिलान्यास दर शिलान्यास होता रहा, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और गांव वाले आशंकाओं में जीते रहे. बजट बनता रहा, पैसा खर्च होता रहा और लोग अर्ध विस्थापन में जीने पर मजबूर होते रहे.

आंदोलनकारियों का कहना है कि कनहर बांध का गैरकानूनी रूप से निर्माण किया जा रहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) द्वारा 7 मई 2015 को दिए गये फैसले में भी यह उजागर हुआ. जिन मांगों को लेकर 23 दिसम्बर 2014 से कनहर बांध से प्रभावित गांवों के दलित आदिवासी शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, आज वह सभी बातें हरित न्यायालय ने सही ठहराई हैं. लेकिन न्यायाधिकरण का फैसला भी तमाम पेचोखम से भरा है. यह फैसला स्थानीय लोगों की त्रासदी को भी उचित ठहराता है और बांध के निर्माण पर रोक भी नहीं लगाता. कनहर बांध परियोजना के खिलाफ ओड़ी सिंह और देवीदिन सिन्हा ने दिसम्बर 2014 में ही हरित न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. कनहर बांध परियोजना के लिए वन-अनुमति और पर्यावरण अनुमति पत्र नहीं है. इससे उत्तर प्रदेश सरकार के सफेद झूठ का पर्दाफाश हुआ. कोर्ट ने इस तथ्य को भी स्थापित किया 2014 तक बांध परियोजना का काम शुरू नहीं हुआ. सोनभद्र प्रशासन यह कहता रहा है कि बांध से प्रभावित होने वाले गांवों में आदिवासियों की संख्या नगण्य है. लेकिन इस तथ्य को भी कोर्ट द्वारा गलत ठहराया गया और कहा गया कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, जिसमें सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है. 25 गांवों से लगभग 7500 परिवार विस्थापित होंगे जिनके पुनर्वास की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी. हरित न्यायलय ने इस फैसले में पर्यावरण के संदर्भ में भी गहरी चिंता जताई है. कनहर बांध परियोजना की आड़ में हुए घोटाले को भी हरित न्यायालय ने रेखांकित किया है.

लेकिन विडंबना यह है कि इतनी चिंता जताते हुए भी कोर्ट ने जो फैसला दिया, वह उनकी चिंता से मेल नहीं खाता. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा काम रोकने से सार्वजनिक पूंजी का नुकसान होगा, इसलिए मौजूदा काम जारी रखा जाए. हरित न्यायालय का यह निर्देश इस मायने में भी विवादास्पद है कि 24 दिसम्बर 2014 की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार द्वारा वन अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी. पेड़ों के कटान पर भी रोक लगाई गई थी. लेकिन इसके बावजूद काम जारी रहा और पेड़ों का कटान भी होता रहा.

क्षेत्र में वनाधिकार कानून-2006 भी लागू है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा. ग्रामसभा से इस कानून के तहत अभी तक अनुमति का प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया है. भूमि अधिग्रहण की सही प्रक्रिया को लेकर भी मसला अटका हुआ है. संसद द्वारा पारित 2013 का कानून लागू ही नहीं हुआ और उसके ऊपर 2015 का भू-अध्यादेश लाया जा रहा है, जो 2013 के कानून के कई प्रावधानों के विपरीत है. कनहर बांध से प्रभावित पांच ग्राम पंचायतों ने हाईकोर्ट में 2013 के भू-अधिग्रहण कानून की धारा 24 उपधारा-2 के तहत याचिका दाखिल कर रखी है. उक्त कानून के तहत प्रावधान है कि अगर किसी परियोजना के लिए भू अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहीत भूमि का पांच साल के अंदर परियोजना के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह भूमि उसके मूल स्वामी के कब्ज़े में वापस चली जाएगी. भू-अभिलेखों में भी अभी तक ग्राम समाज व बसासत की भूमि ग्रामीणों के खाते में ही दर्ज है जो कि अधिग्रहीत नहीं है. प्रदेश सरकार इन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर जबरन परियोजना का निर्माण कराने पर आमादा है. खासतौर पर ऐसे समय में जब नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप से उत्तर प्रदेश में खतरा बढ़ने की आशंका है. प्रदेश सरकार का रवैया संविधान के अनुच्छेद 21 को भी ठेंगा दिखा रहा है. इसके तहत देश के नागरिकों को जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है. ■

बांध का निर्माण स्थगित करें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कनहर नदी पर बांध बनाए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के किसानों और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी कभी नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विवेक ढांड ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन को चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि सहमति की शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डूब क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद मुआवजा वगैरह के मामलों का जबतक निराकरण नहीं हो जाता, तब तक कनहर बांध का निर्माण स्थगित रखा जाए. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि इस परियोजना में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चार गांवों की भूमि प्रभावित हो रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने डूब क्षेत्र का मुआवजा निर्धारित करने के लिए सरगुजा के जिलाधिकारी को प्रस्ताव दिया था. लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव कलेक्टर सरगुजा (छत्तीसगढ़) को अब तक भेजा ही नहीं गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में लिखा है कि इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने राष्ट्रीय सोच अपनाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगातार सहयोग किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा असहयोगात्मक रुख अपनाकर पूर्व निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के हितों की अनदेखी कर बांध का निर्माण शुरू कर दिया गया है. इससे छत्तीसगढ़ के संबंधित गांवों में अनिश्चितता की स्थिति और भारी असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से आग्रह किया गया है कि इस मामले में जब तक सहमति की शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डूब क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद मुआवजा इत्यादि के मामलों का निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक कनहर बांध का निर्माण स्थगित रखा जाए. इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बांध से प्रभावित होने वाले बिहार के गांवों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का निर्देश

मंत्री भ्रष्ट हैं तो क्या, पार्टी को मजबूत कीजिए

दीनबंधु कबीर

विरोधाभास में फंसी समाजवादी पार्टी इन्हीं स्थितियों में चुनाव में उतरेगी. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यह मानते हैं कि मंत्री और नेता जन विरोधी हरकतों में लगे रहे और अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहे, लेकिन फिर भी इन बातों को भूल कर हमें पार्टी को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार का कामकाज देख कर मुलायम सिंह यादव लगातार यह कहते रहे हैं कि पार्टी के कई नेता और अखिलेश सरकार के मंत्री जन विरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. ऐसे मंत्रियों के खिलाफ मुलायम ऐक्शन लेने की बात भी कहते रहे, लेकिन न तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोई ऐक्शन लिया और न सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कोई कार्रवाई की.

पिछले दिनों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने फिर कहा कि मंत्री और विधायक गड़बड़ कर रहे हैं. सपा मुख्यालय पर हुई जिलाध्यक्षों और विधायकों की बैठक में सपा प्रमुख ने पूछा कि कितने विधायक-मंत्री-सांसद आपके जिले के संगठन की बैठकों में जाते हैं? कितने लोग संगठन पर ध्यान दे रहे हैं? सपा प्रमुख के इस सवाल पर किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. इस पर मुलायम बिफर पड़े. उन्होंने कहा कि जो संगठन पर ध्यान नहीं देगा, उस पर ऐक्शन होगा. मुलायम बोले कि उन्हें सारी जानकारी है कि कितने विधायक और मंत्री ठेके-पट्टों में ही जुटे पड़े हैं. पर अब वक्त इसका नहीं है. सारे धंधों को छोड़कर संगठन के कामों में लग जाना चाहिए. मुलायम ने जिलाध्यक्षों से कहा कि वे हर जिले में एक रजिस्टर बनाएं और यह रिकार्ड रखें कि कितने मंत्री विधायक उनकी बैठकों में आते हैं. मुलायम ने कहा कि जिलों में संगठन ज्यादा बड़ा है. संगठन से मंत्री-विधायक-सांसद हैं, संगठन उनसे नहीं है. जिलाध्यक्ष हर जिले में ज्यादा बड़ा है. सभी को जिलाध्यक्ष के कहे अनुसार चलना होगा.

सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि कई जिलाध्यक्ष मंत्रियों और विधायकों की ही चापलूसी में लगे रहते हैं. मुलायम बोले कि कोई मंत्री या विधायक जिलाध्यक्ष से बड़ा नहीं है. उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है. बैठक में सपा महासचिव अरविंद सिंह गोप, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नरेश उत्तम, सचिव एसआरएस यादव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे. मुलायम से कई जिलाध्यक्षों ने मंत्रियों और अफसरों की औपचारिक तौर पर शिकायत की. एक जिलाध्यक्ष ने तो बाकायदा दो मंत्रियों का नाम लेते हुए कहा कि वे गड़बड़ी कर रहे हैं. इस पर मुलायम ने कहा कि उन्हें शिकायत करने से किसने रोका है. वह बंद लिफाफे में शिकायत करें. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर ऐक्शन होगा. फिर मुलायम ने अपना निशाना केंद्र की तरफ किया. बोले कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है. उपचुनाव से सपा की जीत से भाजपा में बौखलाहट है. इससे सतर्क रहने की जरूरत है. अब इन सभी पर हमला बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए. अब कार्यकर्ता गांव-गांव में मोदी सरकार के खिलाफ कामों का खुलासा करें और अपने काम बताएं.

मुलायम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का एक वर्ष दिशाभ्रम का शिकार रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के तीन वर्षों में विकास हुआ है और सद्भाव का माहौल बिगाड़ने वालों को विफलता मिली है. उन्होने कहा कि विधानसभा के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत से भाजपा में बौखलाहट है. राज्य सरकार के विरूद्ध दिल्ली से भी साजिशें हो रही हैं. इससे सतर्क रहना आवश्यक है. मुलायम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को बर्बाद कर रही है. किसानों की भूमि लुटवाई जा रही है. भाजपा ने चुनाव के दौर में नौजवानों को नौकरी देने, मंहगाई पर रोक लगाने और चीन को भगाने का वायदा किया था पर केंद्र सरकार ने एक भी काम नहीं किया. उनके वादों का क्या हुआ? उन्होने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम जनहित के काम किए हैं. नेपाल के मुसीबत के समय राहत दी. मुलायम ने इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों से यह भी कहा कि वे निराश न हों और 2017 के चुनावों के लिए अभी से तैयारी में जुट जाएं. मुलायम एक तरफ विधायकों-मंत्रियों के जन विरोधी और पार्टी विरोधी आचरणों पर तल्ख टिप्पणियां करते रहे तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के कामों की प्रशंसा भी करते रहे. मुलायम बोले कि समाजवादी सरकार जैसा सराहनीय कार्य किसी प्रदेश सरकार का नहीं है. यहां जबरन जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा. किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी. घोषणा पत्र के तमाम वादे पूरे हो गए हैं. सरकार अभी और काम करेगी. जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है. देश में भी समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सांसद निधि का पैसा खर्च करने का भी वक्त नहीं...

नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है. यानी 16वीं लोकसभा का भी एक साल पूरा हो चुका. लेकिन 16वीं लोकसभा के 542 में से 298 सांसदों ने अपने सांसद निधि का एक रुपया भी इस एक साल की अवधि में खर्च नहीं किया. संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक सांसद को सालाना पांच करोड़ रुपये मिलते हैं. इंडिया स्पेंड के एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जिन सांसदों को अपनी सांसद निधि का एक रुपया भी खर्च करने का वक्त नहीं मिला उनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, डीवी सदानंद गौड़ा, उमा भारती और कलराज मिश्र भी शामिल हैं. इनके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी उन सांसदों में शुमार हैं, जो क्षेत्र के विकास के लिए अपनी निधि से सालभर में एक अठन्नी भी खर्च नहीं कर पाए. उसी सत्ताधारी दल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी सीट पर अपनी सांसद निधि के 5 करोड़ रुपये में से 16 प्रतिशत हिस्सा खर्च कर लिया. मौजूदा लोकसभा में भाजपा के 281 और कांग्रेस के 44 सांसद है. उत्तर प्रदेश में 52 सांसदों ने अपनी सांसद निधि का एक भी पैसा खर्च नहीं किया है. अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश के 10 सांसदों ने सांसद निधि के पैसे में हाथ नहीं लगाया. इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश के 1 सांसद, असम के 13 सांसद, बिहार के 25 सांसद, गुजरात के 16 सांसद, हरियाणा के 5 सांसद, जम्मू-कश्मीर के 5 सांसद, कर्नाटक और केरल के 2 सांसद, मध्य प्रदेश के 17 सांसद, महाराष्ट्र के 30 सांसद, मेघालय के 1 सांसद, ओड़ीशा के 14 सांसद, पंजाब के 4 सांसद, राजस्थान के 20 सांसद, तमिलनाडु के 11 सांसद, त्रिपुरा के 1 सांसद, पश्चिम बंगाल के 13 सांसद, अंडमान-निकोबार के 1 सांसद, दादर एवं नागर हवेली और दमन-दीव के 1 सांसद, दिल्ली के 2 सांसद, लक्ष्यद्वीप के 1 सांसद, पुडुचेरी के 1 सांसद, छतीसगढ़ के 5 सांसद, झारखंड के 12 सांसद और तेलंगाना के 10 सांसदों ने भी अपनी निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं किया. इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश, ओड़ीशा, असम और राजस्थान के सांसदों ने कम धन खर्च किया. उधर तमिलनाडु और तथा पूर्वोत्तर के सांसदों का एक वर्ष का प्रदर्शन बेहतर रहा. भाजपा के छतीसगढ़ से सांसद कमलभान सिंह और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सेंगडुवेन ने अपनी निधि से करीब 80 प्रतिशत धन का इस्तेमाल कर लिया. भाजपा के भिवानी से सांसद धरमवीर सिंह ने अपनी सांसद निधि का 98 फीसद धन क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च किया है. ■

प्राचीन मंदिर ध्वस्त कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश

डॉ. पंकज सिंह/डॉ. रामझरोखे दास

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रायबरेली में दुर्गा के प्राचीन मंदिर को बुल्डोजर लगा कर ध्वस्त किए जाने की प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा न केवल रायबरेली जिले बल्कि इर्द-गिर्द के जिलों में भी बढ़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शासन के इशारे पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की. धार्मिक उन्माद फैलाने के सोचे-समझे इरादे से यह किया गया ताकि क्षेत्र में ध्रुवीकरण की सियासत कायदे से हो सके. लोग कहते हैं कि दुर्गा मंदिर काफी पुराना है और इसे लेकर कोई विवाद भी नहीं है. सब कुछ सामान्य स्थिति में था, तो प्रशासन ने ऐसा काम कर लोगों की धार्मिक भावना को भड़काने का काम क्यों किया. बहरहाल, रायबरेली में जेल रोड स्थित चक अहमदपुर नजूल, जो आचार्य द्विवेदी नगर के नाम से जाना जाता है, के पास गाटा संख्या 881 की नजूल भूमि पर लगभग 50 साल पुराना दुर्गा जी का मंदिर स्थित है. तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. चरनजीत सिंह बक्शी ने वहां रमणीय स्थल बनाने का प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन मंदिर का सौन्दर्यीकरण सियासी पेंच में उलझा दिया गया. मंदिर के इर्द-गिर्द अवैध कब्जों को प्रशासन ने तरजीह दी. इस वजह से मंदिर भी जीर्ण-शीर्ण होने लगा. प्राचीन दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और जैसे ही जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, पहले से तैयार बैठा प्रशासन रायबरेली विकास प्राधिकरण के कंधे पर सवार होकर मामले में कूद पड़ा और अवैध निर्माण का आरोप लगा कर काम रोक दिया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के आरोप को विधिक तौर पर गलत बताया और मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू कराने का आग्रह किया, लेकिन जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य रोक कर अगले ही दिन 23 मई को जेसीबी मशीन लेकर मंदिर को ही ध्वस्त करा डाला. मंदिर ध्वस्त कराए जाने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई. बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी प्रशासन के इस कृत्य का विरोध करने सड़क पर उतर आए. पुलिस ने जमकर लाठियां चलाईं, लेकिन विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा. मंदिर तोड़ने का मुद्दा जब गरमाया तो रायबरेली के अलावा अमेठी, फतेहपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ सहित कई अन्य जनपदों के लोगों ने भी शासन-प्रशासन के इस कृत्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. अमेठी से आश्रम के पीठाधीश्वर यौनी महाराज ने पूरे दल-बल के साथ रायबरेली आकर मंदिर मुद्दे पर जिलाधिकारी से वार्ता की. सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज पांडेय की भाभी व भाजपा नेता भारती पांडेय ने सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन के तुगलकी फरमान के खिलाफ ज्ञापन दिया. इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह थी कि विरोध दर्ज करने में मुस्लिम महिलाएं भी शरीक थीं. मंदिर ध्वस्त कराए जाने का मसला जब अन्य जनपदों में पहुंचने लगा और लोगों का रायबरेली जुटना शुरू हुआ तब पुलिस का हाथ-पांव फूलना शुरू हुआ. रायबरेली के सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है. फतेहपुर से आ रहे कार्यकर्ताओं की बस को पुलिस ने शहर के आउटर राजघाट पर ही रोककर वापस कर दिया. मंदिर तक पहुंच गए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी. इसमें हिन्दू वाहिनी के अध्यक्ष अभय सिंह, डॉ. बृजेश सिंह वगैरह को चोटें आईं. विभिन्न संगठनों ने मौके पर पहुंच कर विरोध दर्ज कराया और जिलाधिकारी प्रेम नारायण के अविलंब स्थानान्तरण की मांग की.

खूबी यह है कि दुर्गा मंदिर ध्वस्त किए जाने के मुद्दे पर सभी दलों के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं. यह मसला भाजपा से जुड़ा नहीं है. कांग्रेस पार्टी, व्यापार मंडल, सपा की स्थानीय इकाई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भाजपा या हिन्दू वाहिनी, सभी दलों के स्थानीय नेताओं-कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के इस कृत्य को गलत ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया. हिन्दू वाहिनी के अभय सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय त्रिपाठी, भाजपा की महिला इकाई की जिलाध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता आशीष द्विवेदी, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष वंसत सिंह बग्गा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी के गोविन्द सिंह समेत दर्जनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंदिर ढहाये जाने गलत करार दिया है. रायबरेली जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मेडिकल सेल के नेता डॉ. राजीव सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिख कर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. डॉ. सिंह ने रायबरेली के जिलाधिकारी प्रेम नारायण और क्षेत्राधिकारी सत्यपाल सिंह पर धार्मिक उन्माद भड़काने का आरोप लगाया है. डॉ. सिंह मंदिर के जीर्णोद्धार के मसले पर लगातार सक्रिय रहे हैं. उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि पार्क और मंदिर के दुरुस्त रख-रखाव की चिंता को ताक पर रख कर जिलाधिकारी ने वहां अतिक्रमण को बढ़ावा दिया और उसे अराजकता का केंद्र बना दिया. राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में रायबरेली के जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को अविलंब हटाने और प्रशासनिक अराजकता का माहौल बनाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है.

करोड़ों की जमीन पर है भूमाफिया की नजर

जिस भूमि पर मंदिर का जीर्णोद्धार और नव-निर्माण हो रहा था, उस भूमि की आधिकारिक कीमत 19 नवम्बर 2014 को 2 करोड़ 17 लाख 36 हजार रुपये थी. यह कीमत निश्चित रूप से अब ज्यादा हो गई होगी. इस भूमि के कुछ हिस्से पर तो प्रशासन की मिलीभगत से पहले ही अवैध कब्जा हो चुका है. शेष बची जमीन पर ताकतवर भूमाफिया की नजर है. स्थानीय लोगों में यह चर्चा सरेआम है कि भूमाफिया से मिलीभगत कर जिला प्रशासन ने मंदिर ढहाया. मंदिर के जीर्णोद्धार से भू-माफिया की योजना फेल हो जाती. ■

गंगा के लिए मैं बलिदान देने को तैयार हूं-शिवानन्द

रेनू शर्मा

धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा में खनन माफिआओं द्वारा किया जा रहा अवैध खनन हरीश सरकार के गले की फास बन गयी है. सूबे की सरकार को इस बार मातृ सदन के संत की गंगा के लिए की जा रही अन्न, जल त्याग कर तपस्या ने सरकार के मुखिया को हिला कर रख दिया है. मुख्यमंत्री रावत इस समय पुरी तरह दबाव में है, एक ओर गंगा में हो रही खनन की बदनामी से उन्हे सरकार को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर गंगा के लिए तप पर आमादा संत के जीवन के रक्षा की चुनौती है. इसके पहले भी सूबे की भारतीय जनता पार्टी की निशंक के कार्यकाल में इसी सदन के युवा संन्त निगमानन्द की बली चढ़ चुकी है. जिसका परिणाम रहा कि इसी एक महान पाप ने देवभूमि में मोदी लहर की आज तक हवा निकाल रखी है. भाजपा गंगा-पुत्र की शहादत रोकने में सफल न रहने के कारण हिमालय नहीं चढ़ सकी. गंगा में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए अन्न-जल त्याग चुके मातृसदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती की हालत नाजुक बनी हुई है, आमरण अनशनकारी संत का खुला आरोप है कि हरीश सरकार और शासन-प्रशासन मिलकर गंगा को बर्बाद करने पर तुले हैं, गंगा की दुहाई लगा कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मूक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं. उत्तराखंड में सरकार और खनन माफिआओं का इस तरह गठजोड़ है कि न्यायालयों के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है. हरिद्वार में गंगा की इनती दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई, अब गंगा की दुर्दशा देखी नहीं जाती. ऐसे में मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. गंगा के लिए मै आत्माहुति देने को तैयार हूं.

अवैध खनन के खिलाफ शिवानंद सरस्वती 21 मई से अनशन कर रहे हैं. 22 मई से उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया है. भीषण गर्मी में बिना जल के दो दिन में इनकी हालत नाजुक हो गई है. स्वामी शिवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके कई करीबियों पर निशाना साधा. स्वामी शिवानंद ने कहा कि अवैध खनन के कार्य में लगे लोगों से मुख्यमंत्री को अपने संबंध बताने चाहिए. उन्होंने कई लोगों के नाम गिनाते हुए अवैध खनन कराने के आरोप लगाए. वहीं अवैध खनन कराने के आरोपी अधिकारी हरिद्वार के जिलाधिकारी हरिचंद्र सेमवाल और खनन निदेशक श्रीधर बाबू अद्दांकी के निलंबन की मांग को लेकर स्वामी शिवानंद के शिष्य ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद भी 16 मई से अनशन कर रहे हैं. मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती के तप को कई संगठनों ने समर्थन दिया है. वहीं मातृ सदन की ओर से गंगा में उपखनिज उठाने को लेकर सचाई विभाग के सामने भी आपत्ति दर्ज कराई गई.

जनसंघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मातृ सदन पहुंचकर स्वामी शिवानंद को समर्थन दिया. मोर्चा ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार गंगा की स्वच्छता की बात कह रहे हैं, गंगा की स्थिति सुधारने पर वे गंभीर नहीं हैं. स्वामी शिवानंद के तप का समर्थन करते हुए इनसे अपनी जीवन रक्षा के लिए जल लेने का आग्रह किया. भाजपा मजदूर मोर्चा की बैठक में भी स्वामी शिवानंद व ब्रह्माचारी आत्मबोधानंद के तप का समर्थन किया गया. कहा कि राज्य सरकार संतों व गंगा का अपमान कर रही है. परिवर्तन पार्टी के प्रभात ध्यानी ने भी इनके तप को समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन गंगा से पोकलैंड और अन्य मशीनों को बाहर निकाले, इसके बाद ही कोई बात की जाएगी. इससे पहले कोई शर्त मंजूर नहीं है. पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी शिवानंद ने कहा कि इनके शिष्य स्वामी निगमानंद ने अवैध खनन के खिलाफ तप करते हुए प्राणों की बलि दे दी. अब हम गंगा को तहस-नहस होते नहीं देख सकते. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी स्थिति बचाने के लिए मुख्य सचिव एन रविशंकर को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को खनन मुक्त जिला बनाने पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. इससे पहले सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलकर स्वामी शिवानंद का अनशन तुड़वाने के लिए पहल करने का आग्रह किया. किशोर ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी कहा है कि खनन को बिल्कुल ही बंद करवा दिया जाए. फिर भी समाचार लिखने तक परिणाम ढाक के तीन पात ही है.

धर्म नगरी हरिद्वार में जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं चारो ओर गंगा में अवैध खनन की गुंज ने उन्हे तंग कर रखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार और उधमसिंहनगर को खनन मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एन रविशंकर को तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है. रिर्पोर्ट की समय सीमा तय न होने को लोग उनकी एक राजनीतिक चाल मान रहे हैं.

1. हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर को खनन मुक्त करने पर राज्य की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी भरपाई के लिए क्या किया जा सकता है?

2. खनन न होने पर नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इससे वन और नदियों के किनारे रह रही आबादी पर क्या असर पड़ेगा?

3. खनन न होने से निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे भवन निर्माण की लागत कितनी बढ़ जाएगी?

स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कमेटी के गठन को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव ने उनके एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया. उल्टे उनके आश्रम को लेकर पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट मांग ली गई. मुख्य सचिव पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है. प्रदेश की नदियों में खनन का मुद्दा खासा विवादित रहा है. अवैध खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सख्त रवैया अपनाया है. अब सरकार भी फिर हरकत में आई है. खनन से आपदा प्रबंधन, रोजगार और प्रदेश के राजस्व जैसे मसले जुड़े हुए हैं. ऐसे में खनन को पूरी तरह बंद करवाना आसान नहीं होगा. प्रदेश सरकार पर खनन से जुड़े कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं. इस मामले में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर चर्चाओं में रहे हैं. खनन को सरकार राजस्व बढ़ाने के विकल्प के रूप में देखती रही है.

खनन से जुड़ा दूसरा मुद्दा आपदा प्रबंधन का है. राज्य सरकार लगातार इस बात की दुहाई देती रही है कि नदियों से मलबा नहीं हटाया जाएगा, तो यह नदी किनारे बसी बस्तियों के लिए खतरनाक साबित होगा. विश्व बैंक के सहयोग से तैयार किए गए डिजास्टर रिकवरी प्लान में नदियों के तल से मलबा हटाने पर भी जोर है. अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि खनन के कारोबार से प्रदेश में कितने लोग और किस तरह से जुड़े हुए हैं. इस मामले को सुलझाने का दबाव मुख्यमंत्री पर कांग्रेस सगठन के मुखिया किशोर उपाध्या और पूर्व मुख्यमत्री विजय बहुगुणा का भी है. ■